KGG-VNK/1A/11.00

The House met at eleven of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair

--

PAPERS LAID ON TABLE

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I lay on the Table, under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Mines Notification No. G.S.R. 1120 (E), dated the 8th December, 2016, publishing the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2016.

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF), New Delhi, for the year 2015-16, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Foundation.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (i) (a) above.

(ii) (a) Annual Report of the National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD & PR),

Hyderabad, for the year 2015-16.

(b) Annual Accounts of the National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD & PR), Hyderabad, for the year 2015-16, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Institute.

(d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (ii) (a) above.

SHRI RADHAKRISHNAN P.: Sir, I lay on the Table, under sub-section (4) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Road Transport and Highways Notification No. S.O. 2590 (E), dated the 8th October, 2014, amending Notification No. S.O. 1365 (E), dated the 13th December, 2004, to insert certain entries in the original Notification, along with Explanatory Memorandum and delay statement.

SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA: Sir, I lay on the Table—

I.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (2) of Section 103 and Section 106 of the Major Port Trusts Act, 1963:—

(a) Administrative Report of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2015-16.

(b) Annual Accounts of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2015-16, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Port

Trust.

(d) Review by Government of the Annual Accounts of the above Port Trust.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 5(E) of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948:—

(a) Annual Administration Report and Accounts of the Calcutta Dock Labour Board (CDLB), Kolkata, for the year 2015-16, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Board.

(Ends)

MATTERS RAISED WITH PERMISSION OF CHAIR

ALLEGED BAN ON DEMOCRATIC RIGHTS OF STUDENTS IN SOME CENTRAL UNIVERSITIES

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : महोदय, तकरीबन एक साल पहले बीएचयू में छात्रों ने साइबर लाइब्रेरी को रात भर खोलने की मांग की। उनके prospectus में यह बात है कि साइबर लाइब्रेरी रात में भी खुलेगी और इसके लिए उन्होंने मांग की। वहां के वीसी ने रात में साइबर लाइब्रेरी खोलने से मना किया। उसके बाद लड़के धरने पर बैठे। इस

घटना को घटे एक साल हो गया, लेकिन इसके लिए उन लड़कों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नौ लड़कों को कॉलेज से निकाल दिया गया। इधर कुछ महीने पहले दो गुटों में झगड़ा हुआ, उसमें इन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। इन लोगों को examination देने से रोका जा रहा है और इनके गार्जियन्स को फोन करके यूनिवर्सिटी की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं।

महोदय, वहां पर लड़कियों के साथ क्या हो रहा है? वहां पर लड़कियों को हॉस्टल में नॉन-वैज खाने की मनाही है। लड़के नॉन-वैज तो खा सकते हैं, लेकिन लड़कियां नॉन-वैज नहीं खा सकती हैं। लड़कियां आठ बजे के बाद होस्टल में नहीं आ सकती हैं, नौ बजे के बाद वे सैल फोन पर बात नहीं कर सकती हैं। वहां पर लड़कियों को होस्टल में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। लड़कों को यह सुविधा मिलती है, लेकिन लड़कियों को यह सुविधा नहीं मिलती है। लड़कों को यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है, लेकिन लड़कियों को यह सुविधा नहीं है। इस तरह से ट्रंप के टाइप का फरमान वहां के वीसी जारी कर रहे हैं। इसके लिए वहां पर लड़के और लड़कियां आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर एडमिशन के समय ही लड़कियों से इस तरह का affidavit लिया जा रहा है कि वे किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगी। चूंकि उनको एडमिशन कराना है, इसलिए उनका इस तरह से लिखना मजबूरी हो जाता है। इस तरह की ज्यादती वहां चल रही है। जिन नौ छात्रों को निकाला गया है, उनमें से ज्यादातर ओबीसी के हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के हैं। इस तरह से उनकी लाइफ बरबाद हो रही है।

सर, इसी तरह की स्थिति जेएनयू में है। आप जानते हैं कि अभी जेएनयू में 15 लड़कों को सस्पेंड किया गया है। उनको अभी हाल में अंतरिम रजिस्ट्रेशन का मौका तो मिला है, लेकिन वे लोग भूख हड़ताल पर बैठे, उन्होंने अपनी डिग्रियां जलाने की कोशिश की और हद तो यह हो गई कि वहां पर एनएसयूआई, एबीवीपी भी धरने पर बैठे कि वहां के वीसी ज्यादती कर रहे हैं। पहले तो एबीवीपी को छोड़ कर अन्य छात्र संगठन आंदोलन करते थे, लेकिन अब एबीवीपी के लोग भी वहां के वीसी से आजिज़ आ गए हैं। महोदय, मामला क्या है? मामला यह है कि यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि पीएचडी में एडमिशन के लिए अब 100 परसेंट इंटरव्यू होगा, जब कि लड़के कह रहे हैं कि यह 10 परसेंट होना चाहिए। वे इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि क्योंकि जो रिटन में भी टॉप में आ जाते हैं....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over. It is not going on record.

श्री अली अनवर अंसारी : *

श्री उपसभापति : आप अपनी बात बोल चुके हैं, कृपया आप बैठ जाइए। अब आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, इसलिए कृपया आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... It is not going on record.

श्री अली अनवर अंसारी : *

*** Not recorded.**

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करते हुए कहना चाहती हूँ कि ...(व्यवधान)...

श्री तपन कुमार सेन : महोदय, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी में यह क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)...

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

SHRI MAJEED MEMON (MAHARASHTRA): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI C.P. NARAYANAN (KERALA): Sir, I too associate myself with the issue raised by the hon. Member.

(1b/केएलएस-एनकेआर पर आगे)

NKR-KLS/1B/11.05

श्रीमती विप्लव ठाकुर : लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार होना, इन लोगों की मैंटेलिटी बताता है।..(व्यवधान)..

SHRI TAPAN KUMAR SEN: What is going on in the country? Are we in a democratic, socialist, secular country or are we somewhere else? ...(Interruptions)... Why is this nasty experiment being made in the Central Universities where the Central Government is ultimately the deciding authority?

SHRI D. RAJA: Let the Minister respond. ...(Interruptions)...

श्री शरद यादव : सारी सैंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कभी पिछले 70 वर्षों में इस तरह के हालात नहीं बने। आज इस यूनिवर्सिटी में या कल दूसरी यूनिवर्सिटी में, तमाम तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं, सरकार को इस पर गम्भीर होना चाहिए। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ आपके अंडर हैं। उनमें इस तरह की घटनाएं पहले कभी नहीं होती थीं। अब क्यों हो रही हैं? क्यों रोज नियम बदलने से किसी न किसी तरह की बच्चों को परेशानी हो रही है? यह बहुत ही गम्भीर मामला है। ..(व्यवधान)..मैं इसमें विस्तार से नहीं बोलना चाहता लेकिन मामला बहुत गम्भीर है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके विश्वविद्यालय हैं, आपके हाथ में दिए गए हैं।..(व्यवधान)..

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर,यह गम्भीर मामला है और इन लोगों की मैंटेलिटी बताता है। हमें भी बोलने का मौका दीजिए।..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आपका कोई नोटिस इस मामले में नहीं मिला है।

श्रीमती विप्लव ठाकुर : नोटिस नहीं दिया तो क्या, यह मामला गम्भीर है और इनकी मैंटेलिटी बताता है। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : यदि आप एसोसिएट करना चाहती हैं, तो ऐसा बोलिए कि एसोसिएट करना है।..(व्यवधान)..

श्रीमती विप्लव ठाकुर : महोदय, मैं इस विषय के साथ एसोसिएट करती हूं। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : ठीक है।..(व्यवधान)..

श्रीमती जया बच्चन : *

श्रीमती विप्लव ठाकुर :*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jayaji, this you usually do. You are not chairing, I am chairing. …(Interruptions)… Sit down. …(Interruptions)… What they have said is not going on record. …(Interruptions).. Jayaji, this is not the first time you are doing such things, always you do like this. Don't question the Chair. …(Interruptions)… You can give suggestion but you cannot question the Chair. …(Interruptions)… You are an hon. lady Member, behave properly. Sit down. …(Interruptions)… What you have said will not go on record. …(Interruptions)… All what you have said is expunged. …(Interruptions)… Now you sit down. …(Interruptions)…

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी) : माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है और कई वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने अपने आपको उसके साथ एसोसिएट किया है, यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ की autonomy और यूनिवर्सिटीज़ में जो administrative activities हैं, उनकी day-to-day जो activities हैं, सरकार उनमें कभी हस्तक्षेप नहीं करती।..(व्यवधान)..

***Not recorded**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Universities have autonomy also. ...(Interruptions).. आप सुनिए।..(व्यवधान)..

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : दूसरा विषय यह है कि जो विश्वविद्यालय हैं, उनकी अपनी गरिमा होती है। उनकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक मापदंड होते हैं। हम सब छात्र आंदोलन से निकलकर आए हैं। हमें मालूम है कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो निश्चित तौर से छात्र अपनी बात उठाते हैं, अपनी बात को वहां के वाइस-चांसलर से और वहां की administrative machinery से कहते हैं, लेकिन हमें इन चीजों का राजनीतिकरण यहां पर नहीं करना चाहिए। ..(व्यवधान).. अगर कोई स्पेसिफिक घटना आपकी जानकारी में है..(व्यवधान).. आप हमें बताइए, हम संबंधित मंत्री के संज्ञान में उसे लाएंगे। इसके अलावा स्वीपिंग स्प्री ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You listen. ...(Interruptions)... Listen please. ...(Interruptions)... Listen please. ...(Interruptions)...

श्री अली अनवर अंसारी : यह छोटी चीज़ नहीं है सर। ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I allowed you. Please sit down. ...(Interruptions).. I have already allowed you. ...(Interruptions).. Now sit down. ...(Interruptions)...

श्री अली अनवर अंसारी :*

***Not recorded**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. Naqviji, Mr. Ansari has raised a specific issue. He mentioned the name of a University. He also mentioned about certain discriminations where girl students are discriminated against. Of course, I concede these are autonomous bodies. In spite of that if these things are there which are said to be unlawful, you can inform the HRD Minister to find out what the position is. That is all. Dr. T. Subbarami Reddy. …(Interruptions)… All those who associate, their names will be added, including Shrimati Jaya Bachchan's name. …(Interruptions)…

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with this issue raised by the hon. Member.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with this issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (UTTAR PRADESH): Sir, I also associate myself with this issue raised by the hon. Member.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with this issue raised by the hon. Member.

SHRI VIVEK GUPTA (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with this issue raised by the hon. Member.

SHRI K.K. RAGESH (KERALA): Sir, I also associate myself with this issue raised by the hon. Member.

SOME HON. MEMBERS: We also associate ourselves with this issue raised by the hon. Member.

(Followed by 1C/SSS)

SSS-DS/1C/11.10/

SHRI ANAND SHARMA (HIMACHAL PRADESH): Sir, we are grateful to the Chair that you have registered fully the importance of this issue. When the Minister of Parliamentary Affairs conveys this to the HRD Minister, it should be clearly underscored that this is not a small matter. Secondly, within the Constitutional framework the autonomy of the Central Universities must be protected. That is all what I have to say.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is correct. I appreciate that point. Autonomy is very important. It should be protected. I agree. Dr. T. Subbarami Reddy.

SHRI ABDUL WAHAB: If that is the case, what… …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Wahabji, please sit down. Dr. T. Subbarami Reddy.

NEED TO FRAME NATIONAL POLICY TO PREVENT FOREST FIRES

DR. T. SUBBARAMI REDDY (ANDHRA PRADESH): Sir, protecting the forests from fire accidents across the country is the prime duty of the Government. It is very important. We have seen that 24,817 fire incidents took place in various parts of the country. Therefore, measures should be taken by the Government on top priority. In recent years, forest fires have increased across Central Indian forests and the Himalayan Pine forests. The frequency of such blazes has risen by more than 60 per cent. So, Madhya Pradesh has seen nearly ten-fold increase in forest fires. The three States of Odisha, Chhattisgarh and Madhya Pradesh contribute to a third of forest fires. The prolonged forest fires destroyed 4,000 hectares of forest land across 13 districts of Uttarakhand itself. In Himachal Pradesh and Uttarakhand, over 17,502 acres have been damaged in the last year due to increasing number of forest fires. The Parliamentary Committee which had gone into the whole issue has observed that a large number of posts of frontline forest staff are lying vacant and the fire fighting equipment is almost

nil in most of the cases. This is very important. It is surprising, actually. How has the Government not filled up the posts? Why are they not giving any equipment? How are they keeping quiet when there are fire accidents taking place throughout the country? The Committee has recommended procurement of sweeping machines to clear roadsides of Chirpine needles, while advocating large scale incentives and programmes, including the Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Scheme, to collect dry pines for use as fuel and other incineration. Sir, it primarily focusses on the prevention and containing of fires in the Himalayan forests -- which is important -- spread across Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. It also suggested framing a national policy to manage forest fires. This is important. I urge upon the concerned Minister to make a White Paper and tell us what action they are taking and how they are going to protect the forests. I urge upon the Central Government in the Ministry of Environment and Forests to frame a national policy on managing forest fires on an urgent basis to address these issues. I would also urge upon the hon. Minister to implement the recommendations of the Parliamentary Committee, in the short-term measures, to safeguard the forests for the future generation, especially in the wake of coming summer which is

predicted to be hot and severe. I, once again, urge upon the Government to take measures on top priority. Thank you.

(Ends)

SHRI C. P. NARAYANAN (KERALA): Sir, I associate myself with the issue raised by Dr. T. Subbarami Reddy.

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue raised by Dr. T. Subbarami Reddy.

SHRI RIPUN BORA (ASSAM) : Sir, I also associate myself with the issue raised by Dr. T. Subbarami Reddy.

(Ends)

PATHETIC CONDITION OF ENGINEERS CATEGORIZED UNDER GROUP 'C' IN RAILWAYS

श्री शरद यादव (बिहार) : सर, मैं आपकी अनुमति से एक सवाल, जो बहुत वर्षों से सरकार के अधीन है, उठाना चाहता हूँ। सर, मेरे साथ के कई मित्र रेलवे में इंजीनियर बने हैं। आप यह जानकर ताज्जुब करेंगे कि रेलवे में जो इंजीनियर्स हैं, वे जब भर्ती होते हैं, तब वे जूनियर इंजीनियर होते हैं और उनको "सी" ग्रेड मिलता है, जबकि भारत के बाकी सभी विभागों में ग्रेड "बी" मिलता है। ऐसे-ऐसे केस हैं कि एक जूनियर इंजीनियर "सी" ग्रेड में भर्ती होता है और सारी उम्र काम करने के बाद भी उसको एक भी प्रमोशन नहीं मिलती है। इस मामले के बारे में कई एमपीज़ आज से नहीं बल्कि वर्षों से लिख रहे

हैं। यह जो disparity है, यह जो फर्क है, यह इतना बड़ा है कि एक आदमी को जिन्दगी भर किसी तरह की प्रमोशन नहीं मिलती। इस तरह रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, उनके साथ अन्याय और जुल्म हो रहा है।

(1डी/एमसीएम पर जारी)

MCM-PK/1D/11.15

श्री शरद यादव (क्रमागत) : सरकार उस पर ध्यान नहीं देती, मैंने भी कई बार उसके बारे में लिखा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस दौर में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं रेल में हो रही हैं। आंध्र में होती हैं, ओडिशा में होती हैं, उत्तर प्रदेश में होती हैं, यानी जो सेफ्टी है, इस सेफ्टी में सबसे ज्यादा काम करने वाले, इसको देखने वाले कोई लोग होते हैं तो ये इंजीनियर्स होते हैं। इसलिए जो इंजीनियर्स हैं, इनकी जो मांग है वह जस्टिफाइड है, न्यायसंगत है। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस डिस्पैरिटी को मिटाना चाहिए, इस अंतर को मिटाना चाहिए। जो इंजीनियर्स हैं बड़े पैमाने पर, पूरे जीवन भर जब वे देश के अन्य विभागों को देखते हैं तो उनके अंदर एक इनफीरियॉरिटी कॉम्पलेक्स हो जाता है, एक हीन भावना होती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से चाहूंगा कि इस विषय पर रेल मंत्री को जरूर जल्दी से जल्दी कोई न कोई रास्ता निकाल करके इनके सवाल को हल करना चाहिए, यही मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार) : महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K.T.S. TULSI (NOMINATED): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Partap Singh Bajwa.

(Ends)

DEMAND FOR PAYING ATTENTION TO PROBLEMS OF CENTRAL ARMED POLICE FORCES

SHRI PARTAP SINGH BAJWA (PUNJAB): Sir, I rise to draw the attention of the hon. Minister of Home Affairs to the appalling problems faced by the personnel of the Central Armed Police Forces.

Last month, we read the disturbing news of a Border Security Force (BSF) jawan who vented his grievance through social media. If we are to go by the media reports, the resentment over the allegedly

poor quality food is just the outer layer of the problems, the discontent runs much deeper. The reports suggest that personnel in the CAPF are dissatisfied with the harsh service conditions.

They are expected to perform duties in snow-bound areas, in desert tracts and in jungle terrain, depending on the stations they are deployed at. They are over-stretched and on the move most of the time. There is also a high attrition level within the forces and large numbers go on voluntary retirement after completing the mandatory 20 years of service. The unplanned expansion of the Forces has led to visibly grave deficiencies in infrastructure. There is an acute shortage of housing in the Forces. About 95 per cent of the Forces remain deployed throughout the year and this affects the morale of the Forces. The men aren't even able to avail of their leave, which naturally leads to anger and resentment.

It is a matter of shame, Sir, that the brave jawans who protect our borders are unable to find ears within the system to voice their complaints. The existing grievance redressal mechanism seems weak and calls for a structured method to ensure that our jawans do not have

to employ social media to air their concerns.

At this juncture, Sir, some of the major recommendations of the six-member National Police Commission Report, submitted to Home Minister, Shri H.M. Patel, on February 7, 1979, seems valid even today and needs to be considered earnestly. The Commission had strongly recommended the establishment of District Police Staff Councils (DPSCs) and State Police Staff Councils (SPSCs) comprising a majority of subordinate policemen to consider the grievances of the personnel.

The Commission also recommended sanction of weekly off days and eight-hour workdays for all policemen. This step, I believe, will greatly help the jawans in recuperating from the stress that they undergo on a daily basis. Implementing a transparent, rational and fair leave policy will greatly reduce the burden on the personnel and refresh them for future commitments.

Another key issue concerns the salary paid to the personnel. Although the CAPF personnel have been entrusted with duties akin to

that of the Army, they draw lesser quantum of pay and allowances vis-a-vis their Army counterparts and thus the fundamental principle…..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over.

SHRI PARTAP SINGH BAJWA: …of equal pay for equal work is grossly violated in respect of CAPF personnel.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Bajwa*ji*, time is over. It is not going on record.

SHRI PARTAP SINGH BAJWA: Okay, Sir.

(Ends)

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI RAM CHANDRA PRASAD SINGH (BIHAR): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार) : महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री विवेक गुप्ता (पश्चिमी बंगाल) :महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time over. Shukla*ji,* do you want to associate?

SHRI RAJEEV SHUKLA (MAHARASHTRA): Sir, it is a matter of serious concern. The jawans of Paramilitary Forces live in the most miserable and pathetic conditions and they are compelled to put it on social media. I think some preventive measures must be taken. On the one hand, there is an issue of discipline and on the other hand, nothing is being done to provide justice to them.

(Contd. by PB/1E)

PB-SC/1E/11.20

SHRI RAJEEV SHUKLA (CONTD.): They are compelled to do that. So, I think, the Government should come out with a statement, and the Home

Minister should make a statement on the floor of the House. This is what I demand.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. All right. Now, Shri Derek O'Brien.

SECURING INTERESTS OF INDIAN I.T. WORKFORCE CREATING VALUE GLOBALLY.

SHRI DEREK O'BRIEN (WEST BENGAL): Sir, the subject today is, 'Securing the interests of Indian IT firms creating value globally'.

Sir, this is a very important subject, and a few days ago, the Chief Minister of West Bengal was the first person to react on this. I just want to read two lines of that quote before I get into the meat. 'News about H1B visas is concerning. We must protect our IT companies and professionals. They are our pride. They are our inspiration. We stand by them. India is proud of its world-class talent and it is our duty to secure their interests. We pledge our solidarity with our IT professionals across the world'.

Sir, I don't want to get into discussing what this new executive order does but, suffice to say that it will fundamentally and adversely affect Indian IT companies. Now Indian IT companies don't need our pity nor do they need our sympathy. They are very, very strong to stand on their own feet,

and there is an alternative view, Sir, but I think it must be tabled as to what role these IT companies have played globally. Now, science and medicine doctors, technology, science professionals are always in short supply and it is well known that Indians across the world always come and top them up. No one is doing us a favour. It is because we are qualified to do what we do. Sir, there are three or four very important points to highlight here. Seventy-five per cent of 'Fortune 500 companies' have operational support from Indian IT companies. I am not only talking about the 'Fortune 500 companies', I am also talking about the thousands of other American companies which have this support. Sir, from 2011 to 2015 when the American job market had been growing at 1.7 per cent, those Indian companies, supporting American companies, were growing at 10 per cent. That is a huge contribution. Sir, if it even comes to tax, 20 billion is being contributed every year by these companies. Sir, there are millions of jobs which are being created as a result. So, we need to protect these companies. We fully believe that these companies can stand on their own feet. I don't mean 'protection' in negative kind of way. There is an alternative view to suggest that these companies could be looking globally, elsewhere but I think we need to place on record that these companies play a positive

role not only in the American economy but also across the world. Sir, these engineers, these software engineers, are truly a jewel in the crown of the Indian workforce, of the international workforce. Thank you, Sir.

(Ends)

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (WEST BENGAL): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K.T.S. TULSI (NOMINATED): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI VIVEK GUPTA (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K. SOMAPRASAD (KERALA): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MS. DOLA SEN (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. All those who associate are welcome. Now, Shri Hariprasad.

N.H.R.C. REPORT ON RAPE OF 16 TRIBAL WOMEN IN BASTAR

SHRI B.K. HARIPRASAD (KARNATAKA): Sir, I would like to draw the attention of this House about the slogan of the NDA Government '*Sabka Sath, Sabka Vikas*'.

Sir, it has become a fashion in Chhattisgarh. Way back in 2012, Meena Khalkho, 14-year old girl, was raped and murdered by the Police force, and, later, she was branded as a 'Naxalite'. The then Congress President, Mr. Nand Kumar Patel, was killed by the Naxalites. I demanded for a judicial inquiry to this episode, and later in 2015, the Judicial Commission had submitted its report to the Assembly saying that 'Meena Khalkho was not a naxalite'. It is nothing but a *. Later, in 2013, Sir, we have witnessed Jalaimari *kand* where 40 children, aged between 6-13 years, in a tribal ashram were molested by the people in the ashram. Fortunately, the District Commissioner, DC, had exposed this episode but no action has been taken. Sir, recently, the *Indian Express* had reported the NHRC report indicting the State Government and the Police of

---

***Expunged as ordered by the Chair.**

f raping of 16 tribal women in Bastar region, especially, in Bijapur region, in the whole of Bastar.

(Contd. by 1f/SKC)

SKC-GS/1F/11.25

SHRI B.K. HARIPRASAD (contd.): Sir, I would like to stress upon the fact that in the whole of Bastar, there is no governance except on the National Highways. Way back in 2015, according to the Commission Report, in Pegdapalli, Chinnagelur, Peddagelur, Gundam and Burgicheru, the State Police personnel allegedly sexually harassed and assaulted more than 40 of them and gang raped at least two in Bijapur district of Chhattisgarh. It was also reported that belongings of many villagers were destroyed, stolen or scattered by the forces passing through these villages.

Sir, they talk about "सबका साथ, सबका विकास". In Bastar, it is not *vikas* but *vinash*. No action has been taken against the people or the Police who were responsible for such acts. NHRC has taken *suo motu* cognizance of the NGO which was fighting for the cause of the tribals. Instead of filing cases against the Police under The SC and ST (Prevention of Atrocities) Act, they have filed cases against the lawyers who were giving free legal aid to these tribals. They have filed cases against the NGOs, they have filed

cases against the journalists, but they are yet to file a case against these police officers. Unfortunately, despite such barbaric and beastly acts by the Police officers there, the name of one of the top officers has been recommended for the Presidential Award.

Sir, at this juncture, we demand that action be taken against these officers. If the Government believes in "सबका साथ, सबका विकास" then, it should dismiss the Government in *

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time over. …(Interruptions)…

SHRI SHANTARAM NAIK (GOA): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI VIVEK GUPTA (WEST BENGAL): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

---

* Not recorded

MS. DOLA SEN (WEST BENGAL): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.K. RAGESH (KERALA): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI MAJEED MEMON (MAHARASHTRA): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI RAJANI PATIL (MAHARASHTRA): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं भी इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री परवेज़ हाशमी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, मैं भी इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

SHRIMATI WANSUK SYIEM (MEGHALAYA): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Venkaiah Naidu, do you wish to respond to this? ….(Interruptions)… Now, listen. …(Interruptions)…

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, this is not the way to condemn the entire… …(Interruptions)… The Zero Hour is not meant to condemn a particular Force. Let me make this very clear from the Government side. …(Interruptions)…

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, no action has been taken against people who committed these atrocities. What else can be done? …(Interruptions)…

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, it is the naxalites and the maoists who have taken the law into their hands. …(Interruptions)… They are killing innocent people. They are killing *adivasis*. They have killed a number of people. …(Interruptions)… The police personnel who get into the job for their livelihood are also being put to untold miseries and even being killed. …(Interruptions)… If they have sympathies for the naxalites and maoists, let them say so openly. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. …(Interruptions)…

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The Police and the CRPF are doing a fairly difficult job. …(Interruptions)…

SHRI B.K. HARIPRASAD: No, Sir. …(Interruptions)… They should take action against those people. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Listen to the Minister. …(Interruptions)… Listen to the Minister. …(Interruptions)…

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the Police, the CRPF and others are doing a difficult job. They are also staking their lives for the protection of the people there. …(Interruptions)…

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, they are.. …(Interruptions)…

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: People who sympathize with these people talk about the Human Rights Commission! …(Interruptions)… Human rights are for human beings; human rights are not for people who kill others, who spread terror and who stop development. …(Interruptions)… This has to be clearly noted, Sir. The Zero Hour is not meant to defame the Forces and make allegations against officers. They are not here. …(Interruptions)… If they have some evidence, let them write to the Government and the Government would take suitable action. …(Interruptions)… But such political allegations against the Forces should not be allowed, Sir. I hope the Chair would take notice of this and such things would not be allowed in future. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. …(Interruptions)…

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, please allow me. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you; please sit down. …(Interruptions)… I said, I will allow. Sit down; I will allow you. If Mr. Hariprasad has condemned any Force in particular, then I would go through the records and expunge it. …(Interruptions)…

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, he talked about 40 raids. What is the evidence for those 40 raids and for the allegation that those children in the *Ashram* were raped? They have given a statement that they were not raped. …(Interruptions)…

SHRI B.K. HARIPRASAD: The NHRC has given a report. What more do you want? …(Interruptions)…

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: They are using the Parliamentary forum to make such sweeping allegations. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will go through the records. …(Interruptions)…

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, they cannot demoralize the Forces. …(Interruptions)…

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Such allegations about the Forces and State should not be allowed at all. Chhattisgarh is one of the best performing and forward-looking States in the country. …(Interruptions)… Their Party leader, the former Chief Minister, left the Party and went away. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Hariprasad, the only point is, any blanket allegation or any vague allegation for that matter against any Force of the Government will be expunged. …(Interruptions)… Please sit down. …(Interruptions)… Yes, Mr. Tapan Kumar Sen.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, the fact of the case is that some abnormality is prevailing in those extremism-affected areas. The Force is surely playing a role there. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not the Forces, but may be some individuals who are doing it. …(Interruptions)…

SHRI TAPAN KUMAR SEN: At the same time, if you look at similar situations prevailing at various places, there are cases of over-action and atrocities against the common people by abusing their rights in the name of the abnormal situations prevailing there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But you cannot blame the entire Force for that. That is the point. May be some individual.. …(Interruptions)…

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Definitely, Sir. The Force cannot be blamed, but who is to be blamed for that?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just one minute.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, let me complete. It is the concerned administration that is to be blamed.

(CONTD. BY HK/1G)

HK-HMS/1G/11.30

SHRI TAPAN KUMAR SEN (CONTD.): Who is to be blame? ...(Interruptions)... Please let me complete. ...(Interruptions).. 'Who is to be blamed'? It is the concerned administration. ...(Interruptions)... 'Who is to be blamed"? It is the concerned administration which is supervising the utilization of the Force there. ...(Interruptions)... The concerned administration is to be blamed and they are to take the responsibility. Zero Hour is definitely a proper legitimate hour to raise these problems of common people. ...(Interruptions)...

श्री मेघराज जैन : ये जवाबदेह हैं। ...(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The issue is not that. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Nobody including the Minister can ever question raising an issue in the Zero Hour. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The issue is not that. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Nobody can even question raising the issue. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tapan, the issue is not that. ...(Interruptions)... For the fault committed ...(Interruptions)... Listen, let me make it clear. ...(Interruptions)... Let me make it clear. ...(Interruptions)... For the mistakes or wrongs committed by a person or two persons of a particular Force, you cannot blame the entire Force. ...(Interruptions)... This is the issue. ...(Interruptions)... That is all. ...(Interruptions)..

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Nobody is doing that. ...(Interruptions)... Please do not overreact. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. ...(Interruptions)...

श्री मेघराज जैन : सर, इन्होंने पैदा किया है। ..(व्यवधान)...ये जवाबदेह हैं। ..(व्यवधान)..

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Don't we have to discuss Kerala, Sir, where our party workers are being murdered every day? Please discuss that too, Sir. ...(Interruptions)... Our

party workers are murdered in Kerala. ...(Interruptions)... Please discuss that too. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri K. Somaprasad. ...(Interruptions)... Shri Somaprasad. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: At the same time, the entire State administration has to be condemned. ...(Interruptions)... The entire administration has to be condemned. ...(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is over. ...(Interruptions)... No discussion. ...(Interruptions)... I have not allowed any discussion. ...(Interruptions)... What do you want? What is your problem? ...(Interruptions).. Why are you getting angry with me? ...(Interruptions)...

SHRI K.K. RAGESH: Sir, * is killing. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. That is expunged. ...(Interruptions)...

श्री मेघराज जैन : लोगों की हत्या कर रहे हैं। ..(व्यवधान)..

***Expunged as ordered by the Chair.**

SHRI D. RAJA: This is a serious matter. ...(Interruptions)... We want some response. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is already replied to. ...(Interruptions)... Please sit down. ...(Interruptions)... That is already replied to. ...(Interruptions)... That is explained. ...(Interruptions)... Don't be impatient. ...(Interruptions)...

SHRI K.K. RAGESH: Sir, * is killing. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How do you say like that? ...(Interruptions)... Why do you bring in the name of *? ...(Interruptions)... It is expunged. ...(Interruptions)... Don't do that. ...(Interruptions)...

SHRI K.K. RAGESH: Sir, * is killing and they are pretending to be innocent. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What are you doing? ...(Interruptions).. It is already expunged.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: He is telling what is actually happening there. ...(Interruptions)...

***Expunged as ordered by the Chair.**

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Let us discuss Kerala also. ...(Interruptions)... Let us discuss Kerala also. ...(Interruptions)...

SHRI K.K. RAGESH: It is not the CPI (M) but the ...(Interruptions)... The Minister is misleading the House. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ragesh, if you have mentioned any organization, its name is expunged. ...(Interruptions)... Now, Mr. Ragesh, I am telling you that killing is going on from both sides. ...(Interruptions)... You cannot say that killing is from one side only. ...(Interruptions)... I also read newspapers. ...(Interruptions)... I don't want to apportion blame on anybody; but killing is from both sides. ...(Interruptions)... Now, Shri Somaprasad. ...(Interruptions)...

SHRI K.K. RAGESH: People were killed by *. ...(Interruptions)... They are doing that. ...(Interruptions)...

***Expunged as ordered by the Chair.**

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: It is the Chair which decides. ...(Interruptions)...

SHRI K.K. RAGESH: * is doing that. ...(Interruptions)... It is the * which is doing it. ...(Interruptions)... (Ends)

PROBLEMS BEING FACED BY KERALA MINERALS AND METALS LIMITED

SHRI K. SOMAPRASAD (KERALA): Sir, with your permission, I raise certain points relating to Kerala Minerals and Metals Limited. The Kerala Minerals and Metals is a public limited company and Government of Kerala Undertaking. The peculiarity of the company is that it is the only manufacturer of rutile grade titanium dioxide in India. The company started its production in 1984 with the capacity of 40,000 metric tonnes per annum. The company produces five different types of titanium products. One of the products is titanium pigment. The titanium pigment plant is a joint venture of KMML with VSSC and DMRL. Titanium pigment is the raw material for the titanium metal. Titanium pigment is famous for its high strength and less weight.

***Expunged as ordered by the Chair.**

Titanium metal is used in the manufacture of aeroplanes and it is also used in nuclear plants. (Contd. by YSR/1H)

-HK/YSR-ASC/11.35/1H

SHRI K. SOMAPRASAD (CONTD.): Thus, the KMML becomes a strategically important company. It gives employment to 1,600 persons directly and more than 10,000 persons indirectly. Nowadays, the company is facing so many challenges.

China is one of the major producers of titanium dioxide. China has even penetrated the Indian market. They offer very cheap price which our Indian companies can never imagine. The KMML cannot compete with China even in our market. The import duty on titanium dioxide is only ten per cent. It should be enhanced to a minimum of twenty-five per cent. Only then the KMML can survive.

The Government of India should do something in this matter. My humble request is that the Government should enhance the import duty, which is now ten per cent, to a minimum of twenty-five per cent. Thank you, Sir.

(Ends)

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member. Hon. Commerce Minister is here. I request her to kindly respond to this serious issue. I know she has a mind of doing that.

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI C.P. NARAYANAN (KERALA): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.K. RAGESH (KERALA): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member. It is extremely important to increase the import duty on titanium dioxide from ten per cent to twenty-five per cent. In the last two decades, many public sector units had closed down because of liberalisation policy and that is why it is extremely important to increase the import duty on titanium dioxide to save the KMML.

(Ends)

RELEASE OF FATHER TOM UZHUNNALIL FROM CAPTIVITY IN YEMEN

SHRI JOY ABRAHAM (KERALA): Mr. Deputy Chairman, I thank you for giving me this opportunity.

Sir, I wish to raise the issue of Father Tom Uzhunnalil, an Indian citizen and native of Kerala, who was serving in Yemen. He has been in the captivity of terrorists in Yemen for the last several months. All efforts by the Government to get his release are in vain. It seems that his life is in danger. Recently, a video clipping, in the form of appeal by Father Tom, appeared in the visual media. His appeal was so passionate that it moved the hearts of everybody who viewed it. It seems that his health is deteriorating day by day. A *dharna* under the auspices of Archdiocese of Faridabad and All Kerala Catholic Congress is being staged today at Jantar Mantar to draw the attention of the Central Government for its speedy intervention. I request that someone from the Government's side respond to this humanitarian issue. I seek the help of the whole House to get the release of Father Tom as early as possible.

(Ends)

SHRI K. SOMAPRASAD (KERALA): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI C.P. NARAYANAN (KERALA): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K.K. RAGESH (KERALA): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not a Catholic issue. It is an issue concerning all of us. I think hon. External Affairs Minister has already made a statement.

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I am sure the House is aware that the External Affairs Minister, Shrimati Sushmaji, had spoken about it and efforts were being made on this issue. Because he is an Indian citizen, we all have to be concerned about this. I am sure the External Affairs Ministry will be able to give extra information on the latest position. I have got up only to remind that the House was earlier given information how the External Affairs Ministry was definitely taking the matter up. I am sure the Parliamentary Affairs Minister, Mr. Naqvi, will be able to pass on the message. I just want to remind the House that the efforts were on at that time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I saw that statement. Naqviji may kindly convey the feelings to the External Affairs Minister and, if possible, share the position with the House.

(Ends)

DEMAND FOR C.B.I. INQUIRY INTO CASE OF MISSING STUDENT OF J.N.U.

श्री विवेक गुप्ता (पश्चिमी बंगाल) : डिप्टी चेयरमैन साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे यहां खड़े होकर बोलने का मौका दिया। सर, एक छात्र नज़ीब है, जो कई महीनों से लापता है। आज मेरे ज़ीरो ऑवर का सब्जेक्ट उसी के बारे में है। सर, नज़ीब का मतलब होता है, जो सराहनीय है।

(1J/LP पर जारी)

LP-VKK/11.40/1J

श्री विवेक गुप्ता (क्रमागत) : मगर जे.एन.यू. के जो अधिकारी हैं, उनका जो आचरण है, उनका जो तौर-तरीका है, वह सराहनीय नहीं है। वॉर्डन की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अक्तूबर, 2016 को यह घटना घटी, जिसमें नज़ीब और कुछ और छात्र शामिल थे। वे छात्र किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते थे। मैं दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस पर नहीं जाना चाहता हूं। वहाँ पर एक झमेला हुआ। सिक्युरिटी गार्ड, स्टुडेंट्स और

वॉर्डन इंचार्ज, इन सभी ने इस घटना को देखा। इसकी रिपोर्ट बनाकर दी गई, मगर आश्चर्य की बात यह है कि वाइस चाँसलर से लेकर जितने भी अधिकारी इस युनिवर्सिटी के हैं, उनमें से किसी के द्वारा भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ तक कि एफ.आई.आर. दर्ज़ कराने के लिए भी लड़के की माँ को जाना पड़ा। इसके पहले कि सरकार यह बोले कि यह युनिवर्सिटी का आंतरिक मामला है और हम लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, मुझे लगता है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर सरकार का मामला है, और दिल्ली राज्य का होने से खास कर केंद्र सरकार का मामला है। क्या हम लोग नज़ीब को सिर्फ एक गुमशुदा स्टेटेस्टिक्स बनने देंगे? मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से जानना चाहूंगा कि नज़ीब को खोजने के लिए क्या कुछ स्पेशल प्रयास किए गए हैं? क्या नज़ीब सिर्फ एक missing student की तरह बनकर रह जाएगा, जबकि यह एक क्लियर कट पोलिटिकल वेंडेटा का केस है?

सर, आजकल हम लोग देखते आ रहे हैं कि देश में पोलिटिकल वेंडेटा किस तरह से कैंसर की तरह फैलता जा रहा है। अगर कोई सरकार में है, तो उनका यह प्रयास होना चाहिए कि नज़ीब को जल्द से जल्द खोजा जाए। उसके घरवालों से, उसकी माँ से ज्यादा से ज्यादा बातचीत की जाए, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वाइस चाँसलर ने उनकी माँ से मिलने तक के लिए मना कर दिया था। सर, अगर उन लोगों में संवेदना नहीं है तो कम से कम केंद्र सरकार वह संवेदना तो जगा सकती है। मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि सरकार इस पर या तो सीबीआई इंक्वायरी कराए या कोई अन्य उचित इंक्वायरी करवाए। सरकार यह पता तो लगवाए कि यह जो

नज़ीब गया है, उसके पीछे क्या कारण थे, जबकि हम लोगों को घटनाएँ मालूम हैं? सर, मजे की बात यह है कि जो लोग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र, इस घटना में इन्वॉल्व हैं उनसे आज तक पूछताछ तक नहीं हुई है। सर, यदि उन लोगों का कुछ स्पेशल स्टेटस है, तो हम लोगों को यह भी बता दिया जाए कि उनको पूछताछ से क्यों एग्जम्प्ट किया हुआ है?

सर, देश में यह जो पोलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, यह एक बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए और उचित कार्यवाही की जाए। हम लोगों को कम से कम एक उचित स्टेटमेंट दी जाए कि पोलिटिकल वेंडेटा पर सरकार का क्या रुख है? धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री अली अनवर अंसारी : उसको जमीन निगल गई या आसमान उठा ले गया? कहाँ चला गया लड़का? ..(व्यवधान).. अभी तक जाँच नहीं कर रही है। ..(व्यवधान)..एक खास दल से संबंधित लड़कों..(व्यवधान)..को नहीं देख रही है, पुलिस उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। यह क्या हो रहा है? ..(व्यवधान)..एक तरफ तो रोहित वेमुला को स्युसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है और दूसरी तरफ नज़ीब को मार दिया जाता है..(व्यवधान) और यह जाँच तक नहीं करेगी। ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You associate. That's okay. …(Interruptions)… What do you want to say? …(Interruptions)…

SHRI MAJEED MEMON: Sir, the offence against the State needs to be examined, investigated and the law must take its own course. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You associate. …(Interruptions)…

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूं।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूं।

جناب جاوید علی خان (اترپردیش): اُپ سبھاپتی جی، میں بھی خود کو اس وشے سے سمبدّ کرتا ہوں۔

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

SHRI MAJEED MEMON (MAHARASHTRA): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

SHRI HARIVANSH (BIHAR): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

MS. DOLA SEN (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

SHRI AHAMED HASSAN (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

SHRI K.T.S. TULSI (NOMINATED): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (WEST BENGAL): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

SHRI C.P. NARAYANAN (KERALA): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the matter raised by Shri Vivek Gupta.

(Ends)

CONCERN OVER POOR CONDITION OF EX-SPORTSPERSONS OF COUNTRY

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (WEST BENGAL): Sir, I thank you for giving me this opportunity. Sir, I want to speak about the tragedy of those who made our nation proud, that is, our ex-sportspersons.

जब अपनों ने दिया दर्द, तो दुनिया से क्या कहना

यूँ तो लाखों दर्द मिले हैं हमें, पर इस दर्द का क्या कहना।
جب اپنوں نے دیا درد، تو دنیا سے کیا کہنا
یوں تو لاکھوں درد ملے ہیں ہمیں، پر اس درد کا کیا کہنا

Sir, while the nation is celebrating our recent win in cricket against England, there is a sad state of affairs which I would like to bring to the notice of the House through you.

A nation must honour its heroes – be it a soldier, a sailor or a sports star. Wherever they go, they are the ones who carry our country's pride and cause with them. But, are we doing enough to honour those who make our nation proud? Are we taking care of those athletes who won medals for us? Though the Ministry of Sports has always talked about the efforts to improve sports facilities in the country, it is important that they also start talking about the efforts to honour ex-sportspersons who brought glory to our nation. Sir, I am deeply saddened by the way they have been pushed to the margins of sports history and by the fact that they have to spend their lives in poverty, struggling to make ends meet.

(Contd. by GSP/1K)

GSP-KLG-11.45-1K

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (CONTD.): Sarwan Singh, a gold medalist in 110m hurdles at the 1954 Asian Games worked as a cab driver and finally as an agricultural labourer at the age of 70 years.

Yousuf Khan was part of the gold medal winning team in soccer in the 1962 Asian Games. In the same Games, Makhan Singh won the relay race. Both led poverty stricken life after retirement. Gopal Bhengra, a 1978 world cup participant had to work in a stone quarry. Kabaddi champion Shanti Devi sells vegetables whereas Sita Sahu who won two bronze medals at the 2011 Special Olympics in Athens now sells *gol gappas.* I have named a few though there are numerous such cases. A small amount of monthly pension is now granted to our retired sportspersons from the Sports Fund for Pension to Meritorious students but we need to ask ourselves, is it enough?

बेटा कैसा भी हो जाए, पर मां तो मां ही होती है।

तू झांक के दिल में देख कभी, हम कितने दर्द समेटे हैं।

मां हम भी तेरे बेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं।

بیٹا کیسا بھی ہوجائے، پر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے
تو جھانک کے دل میں دیکھ کبھی، ہم کتنے درد سمیٹے ہیں
ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں۔

Sir, I would like to bring to the notice of the House the poor financial conditions of some of our ex-sportspersons. It is their voice that I raise here, when I say.

भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से कहता है।

मां हम भी तेरे बेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं।

بھیگی پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے کہتا ہے
ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں۔

(समाप्त)

श्री विवेक गुप्ता (पश्चिमी बंगाल): महोदय, मैं इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको संबद्ध करती हूँ।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

SHRI K.T.S. TULSI (NOMINATED): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI M. C. MARY KOM (NOMINATED): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI A.V. SWAMY (ODISHA): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI B.K. HARIPRASAD (KARNATAKA): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. T. SUBBARAMI REDDY (ANDHRA PRADESH): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI PARVEZ HASHMI (NCT OF DELHI): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ALI ANWAR ANSARI (BIHAR): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is full support. Naqvi ji, you also heard what Mr. Haque has said. Many of our ex-sportspersons are starving and finding it very difficult to make both ends meet. That is what he said. He is suggesting something. Why don't you convey it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): Right, Sir. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, it is a very reasonable demand. …(Interruptions)…

श्री प्रेम चन्द गुप्ता: उपसभापति जी, यह एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। Across the party lines, it is the same feeling.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Everybody is supporting it.

श्री प्रेम चन्द गुप्ता: कोई किसी एक पार्टी का इश्यू नहीं है। What I suggest is that we should have a one hour discussion on this issue, which is very important.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, somebody can give notice. …(Interruptions)… I think, in this Session… …(Interruptions)… It may not be possible before… …(Interruptions)…

SHRI PREM CHAND GUPTA: Next session, Sir. …(Interruptions)… It is a very important issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I also agree with you. Notice can be given and the hon. Chairman may consider it. I will also request hon. Chairman to consider it. I agree with you.

Now, Shrimati Kahkashan Perween, not present. Okay. Now, Special Mentions. (Ends)

SPECIAL MENTIONS

URGENT NEED TO ADDRESS GENDER INEQUALITY

SHRI K.C. RAMAMURTHY (KARNATAKA): Sir, I thank you for giving me the opportunity. Sir, this issue has been discussed many times here. However, I would like to mention the urgent need to address gender inequality. Sir, gender inequality in India is a growing concern. As per UN Gender Inequality Index, India ranks abysmally 127 out of 146 countries in gender inequality. Even McKinsey's Report "The Power of Parity: Advancing Women's Equality in India shows poor levels of gender parity. And, our global Gender Parity Score is 0.48 whereas a score of 1 would be ideal. It represents 'extremely high' level of gender inequality, which compares poorly with 0.71 for Western Europe, 0.74 for North America and Oceania.

No doubt a significant progress on promoting girls' education and advancing gender equality is made, but stark inequalities still exist between men and women in their access to education, healthcare, resources and opportunities in socio- economic and cultural spheres. Just 13 per cent of women of low economic status avail institutional deliveries, while only 19 per

cent in the lowest quintile avail any kind of post-natal care. Adverse child (0-6 years) sex ratio of 914 in 2011 when compared to 927 in 2001 gives grim reminder of continuing aversion to girl child and tempering natural demography. Female literacy rate is 65 per cent against 81 per cent for men and 97 per cent women undergo sterilisation.

So, it is imperative to address low status of women as a national priority by channelizing potential of our 300 million young people to catapult itself into a new trajectory of development. Programmes that educate adolescents and young males and females to influence their health and consequently their overall well-being are an absolute priority, apart from investing in skill development on young.

(Ends)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRIMATI RAJANI PATIL (MAHARASHTRA): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

(Ends)

-GSP/BHS-AKG/1L/11.50

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, just on the issue of business in the House today and tomorrow, all we have is the President's.....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(Interruptions)...

SHRI DEREK O'BRIEN: One second, Sir. It is just to clarify. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: After this, I will. I think, we will finish this. Then, I will allow you. There will be time. Now, Shri Vivek Gupta.

DEMAND FOR TAKING STEPS TO MAINTAIN SPIRIT OF COOPERATIVE FEDERALISM IN THE COUNTRY

श्री विवेक गुप्ता (पश्चिमी बंगाल) : सर, आपका एक बार फिर धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। Special Mention पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है।

सर, हमारे प्रधान मंत्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था कि भारत की ताकत उसका federal character और federal structure है और हम स्टेट्स के साथ बड़े भाई के attitude में विश्वास नहीं रखते हैं। "We believe in cooperative federalism." उनके स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि सरकार को स्टेट्स की मदद करनी चाहिए। सरकार को एक स्टेट को उसके कामकाज करने देने में पूरी-पूरी मदद करनी चाहिए और उसको इसके लिए जिस-जिस चीज की दरकार है, वह देनी चाहिए।

सर, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में कुछ आँकड़े लाना चाहता हूँ। पश्चिमी बंगाल सरकार को 2011 में करीब ढाई लाख करोड़ का कर्ज मिला था। 5 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन केन्द्र सरकार ने न तो हमें कोई फंड दिया है, न हमारी कोई मदद की है, न कोई moratorium किया है, कुछ भी नहीं किया है। मगर, surprisingly, हम लोग विदेशी देशों की जा-जाकर मदद कर रहे हैं। सर, पश्चिमी बंगाल में 101 IAS ऑफिसर्स की shortage है और 88 IPS ऑफिसर्स की shortage है। इस demand को सरकार के साथ regularly उठाया जा रहा है, मगर अभी तक हमारे पास सरकार से कोई response नहीं आया है।

इसके अलावा, आजकल देखा गया है और last six months में हमारी दीदी, hon. Chief Minister of West Bengal ने कई बार इस issue को उठाया है कि आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे फैसले बिना स्टेट गवर्नमेंट को consult किए arbitrarily लेती है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. …(Interruptions)… Vivek*ji,* you have to read from the prescribed page. …(Interruptions)…

SHRI VIVEK GUPTA: Yes, Sir. I am reading. I am just reading in Hindi. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot go out of that. …(Interruptions)…

SHRI VIVEK GUPTA: I am not going out of it. …(Interruptions)… I am just reading in Hindi. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please read that. …(Interruptions)…

SHRI VIVEK GUPTA: I have given in English but I am reading in Hindi.

श्री उपसभापति : ठीक है, आप पढ़िए।

SHRI VIVEK GUPTA: It is a literal Hindi translation, Sir. You can check it. I will go as per your instruction, Sir.

The Central Government has now taken a decision (without consulting the States) to remit money under MNREGA directly to the beneficiaries against the earlier practice of involving States in the process of remitting the same.

Despite regular audits done by the CAG, the Central Government recently appointed two senior officers to monitor the working and spending of the Treasury of the Bengal Government. Sir, we feel this is a direct attack on our fiscal independence.

Despite all these challenges, the hon. Chief Minister of West Bengal has made Bengal grow by leaps and bounds. We hope the Government takes these concerns seriously and lays more trust with the State Governments by decentralizing greater powers. Thank you, Sir.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Dr. V. Maitreyan, not present. Shri T. Rathinavel, not present.

Now, hon. Members, I will allow Derek O'Brien*ji*. You are going to speak on the listed Business of the House, isn't it? I am going to allow you. Now, I am also going to say about the Business of the House. See, how productive and fruitful was this one hour! All could raise their issues. The Government could react in some cases. Even Special Mentions could be read. So, now, compare it with the days of disruption. That is all what I have to say. …(Interruptions)…

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I read your interview today. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; that is all. So, let us do like this. It will be good for all of us. …(Interruptions)…

SHRI DEREK O'BRIEN: You look at this side also. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, both sides. …(Interruptions)… I am talking to both sides. …(Interruptions)… No doubt about it. …(Interruptions)… Both sides should cooperate. Now, Shri Derek O'Brien.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, just on one point on the List of Business as we understand, so that we do not get into a situation, when we are discussing

the Budget, as happened about four-five years ago. Due to paucity of time, all the 35 speakers who wanted to speak on the Budget were asked to lay their speeches on the Table.

(Contd. by DC/1M)

DC-RPM/1M/11.55

SHRI DEREK O'BRIEN (CONTD.): Sir, if this finishes today or tomorrow, as we are going, then, the next two days after that are on the Budget. Everybody gets a chance to speak then. So laying is not a solution. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Laying is not a…(Interruptions)…

SHRI DEREK O'BRIEN: There is a precedent of three or four years ago when Chidambaram*ji* was the Finance Minister. There was no fault of Chidambaram*ji,* but we were in the House and about 22 speakers laid their Budget speeches. I said, 'let us…(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That must be a special permission perhaps given by the hon. Chairman.

SHRI DEREK O'BRIEN: Protect us, Sir. Protect us as you complimented the Government and the Opposition for running the House together. So

protect us. On Wednesday and Thursday, we all can make our Budget speeches and no speech needs to be laid. That is my only contention.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes; there is no rule to allow it to be laid on the Table but, however, I have to question one thing… …(Interruptions)…

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the House is working in a very serious manner and the issues have been taken up and discussed. I seek your indulgence for a minute. A very serious situation has arisen in recent days because of the various laws that have been proposed or tabled in the US Congress.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Let us conclude this issue first.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, if you conclude that…(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I did not conclude that. I thought you are on this issue. Regarding the List of Business, I have to ask the House. For this Motion of Thanks on the Presidential Address, 12 hours is the time allotted. We have exhausted only four hours. So another eight hours are there, and we have today and tomorrow. It will be over only by tomorrow. I think the reply should be by tomorrow evening. What is the position? Can you tell us, Mr. Minister?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): माननीय उपसभापति जी, जो डिसकशन है, वह आज होगा और कल होगा। रिप्लाई के बारे में,

डिसकशन के बाद क्या स्थिति है, उसे देखने के बाद बताएंगे। Then I will convey it to you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; that is all right. Then, for Budget, there are only two days.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, it has 16 hours.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Budget has 16 hours. Then how is it possible? That is the point. How is it possible in two days? What is the way out? …(Interruptions)… Mr. Derek, you please listen. According to the Business listed on Thursday, there is the Private Members' Business also. First thing is, we will have to postpone the Private Members' Business. The House has to do that. That is number one. Number two, even then it is not possible to have 16 hours. …(Interruptions)… So, in practice, it may not be possible to conclude the Budget in two days. …(Interruptions)…

SHRI TAPAN KUMAR SEN: So the Budget discussion has to spill over to the Session, starting from 9th March.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all what I want to say.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, my suggestion is, whatever Budget discussion remains, it should spill over to the Session, which is starting from 9th March and going up to 12th April, because we are very much within the

penultimate date and as per the Constitutional mandate, we can have the discussion and then pass it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Otherwise, there is a way out. Today and tomorrow also, let us sit late. If that is not possible, the Budget discussion cannot be completed by Wednesday and Thursday.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Why should you make us sit late? We are very much within the time. …(Interruptions)…

SHRI ANAND SHARMA: Sir, …(Interruptions)… Just one minute. …(Interruptions)…

SHRI TAPAN KUMAR SEN: And the hon. Parliamentary Affairs Minister cannot say like that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Anand Sharma, you have only two minutes.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I just have to make this submission that I agree with our colleagues here. The Budget has to be passed before the 31st March. Now, 16 hours have been allocated for the Budget discussion. That may not be possible. The Budget has been presented by the Government. Heavens will not fall. Why should we be pushed? This should spill over. The allotted 16 hours have to be completed because this is an important Budget and this is the first time, Sir, that the General Budget and the Railway

Budget have been combined. This is the first time; otherwise, there used to be separate time for General Budget and separate time for Rail Budget. Sir, it would only be fair that the discussion starts and continues. Here nothing is going to happen.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; we will try. We can try. We all will try.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, we still have a minute. The issue which I was raising is about the H-1B Visas. The Bills have been tabled in the US Congress. Over three lakh Indian professionals are there, their careers are threatened. They are afraid to come to India even for family emergencies because they may not be allowed to return. Sir, the Government must make a statement. If we are investing in strategic partnerships with the United States of America, then the US administration and the new President have to be fully sensitized and credible assurances must be sought by our Prime Minister, Shri Narendra Modi, from President Trump.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is time for Question Hour.

(Ends)

(12.00-1.00 P.M. - Question Hour)

SK/2B/2.00

The House reassembled after lunch at five minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS (CONTD.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yesterday, Shri D. Raja completed his speech.

(Contd. by YSR/2C)

-SK/YSR-VNK/2.05/2C

MR. DEPUTY CHAIRMAN (CONTD.): Mr. La. Ganesan did not start. One round is complete. That is the position.

SHRI SITARAM YECHURY: We did not speak. How did you complete one round?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One round complete means those who were here to speak.

SHRI SITARAM YECHURY: If we were called and we were not here that I can understand. But that also did not happen.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You were not here.

SHRI SITARAM YECHURY: I was not here. But you did not call.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The point is, if I start with Mr. Ganesan that will be considered as second round. Then after him, Mr. Rajeev Shukla will speak. Then Mr. Sanjay Seth will speak. Then will come the turn of the AIADMK. Then Shri Sharad Yadav will speak. Then Shri Sitaram Yechury will speak. Since you and Sharad Yadavji did not speak on that day, your turn will come in the second round. Shri La. Ganesan, your party has allotted you only ten minutes. You have to speak within ten minutes.

श्री ला. गणेशन (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं तमिलनाडु से आया हूँ। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि तमिलनाडु में हिन्दी सिखाने की व्यवस्था नहीं है। हिन्दी सीखने के लिए मेरे पास समय भी नहीं है, इसलिए मैं हिन्दी नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका कारण यह है कि मैं मध्य प्रदेश से चुन कर आया हूँ। ...(व्यवधान)...

SHRI JAIRAM RAMESH: *Speak in Tamil. Speak in Tamil.

SHRI LA. GANESAN: *When I speak in Hindi, there are only very few people to listen. If I speak in Tamil, who will listen?

SHRI JAIRAM RAMESH: *Speak in Tamil. Speak in Tamil.

SHRI LA. GANESAN : Thank you for supporting me to speak in Tamil.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why not in Telugu?

*** English translation of the Tamil portion.**

श्री ला. गणेशन : ये चाहते हैं कि मैं तमिल में बोलूं। मेरे द्वारा हिन्दी में चार सेंटेंस बोलने के बाद उनको मेरी हिन्दी कष्टप्रद लगने लगती है, इसलिए वे मुझे तमिल में बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं हिम्मत से हिन्दी में ही बोलने की कोशिश करूंगा।

अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं मध्य प्रदेश की जनता, वहां के जनप्रतिनिधि, मान्यवर मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे मौका देने के लिए मैं प्रधान मंत्री जी और अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं हिम्मत से हिन्दी में बोलना शुरू करता हूँ, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि मैं जो बोलता हूँ, वह हिन्दी ही है, ऐसा आपको मानना चाहिए। पिछले सेशन में यहां पर पहली बार आने के बाद मैंने देखा कि यहां पर स्लोगन और काउंटर स्लोगन, एड्जर्नमेंट और एड्जर्नमेंट हुआ। यहां पर इस तरह देख कर मेरे मन में बहुत दुख हुआ। मेरे मन में कल्पना थी कि यहां पर मुझे अच्छी तरह बोलने वाले वरिष्ठ नेताओं के मुख से अच्छे-अच्छे भाषण सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन जो देखने को मिला, वह इससे अलग था। तमिलनाडु में एक कहावत है, 'Balakumara, you desired only for this. Didn't you?' मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन इस बार सदन अच्छी तरह से चल रहा है और वक्ताओं को बोलने का मौका मिलता है तथा बाकी लोगों के भाषण को सुनने का भी मौका मिलता है, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ।

(2डी/एनकेआर-वीकेके पर जारी)

NKR-VKK/2D/2.10

श्री ला. गणेशन (क्रमागत): मान्यवर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अलग से देखना उचित नहीं है बल्कि समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। देश में, 2014 में, आम चुनाव होने के बाद, मान्यवर नरेन्द्र मोदी के प्रधान मंत्री पद ग्रहण करने के बाद, पार्लियामेंट के ज्वाइंट सैशन में जब मान्यवर राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण दिया, मुझे याद है, हमने, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पूर्व जो अपना घोषणापत्र, election manifesto, रिलीज़ किया था, हमने चुनाव के समय जो वायदे किए थे, जिन्हें घोषणापत्र में लिखा था, उसके सभी अंशों को, all those points which were mentioned in the manifesto were incorporated in the Presidential Address. इसका अर्थ यह हुआ कि बी.जे.पी., यानी मेरी पार्टी ने चुनाव के समय घोषणापत्र में जिन वायदों को शामिल किया, वे केवल वोट मांगने के लिए नहीं किए, बल्कि जीतने के बाद उन सभी वायदों पर सीरियसली implementation करने, उन पर अमल करने की हमने कोशिश की और उन सबको हमने माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में शामिल किया। It is a progress report and accountability. इन दो सालों में हमने क्या किया, उसकी accountability - one-by-one - सभी स्कीम्स को शामिल करके इस साल का अभिभाषण कराया। उसके बाद, अपनी बजट स्पीच में, हम आगे क्या करने वाले हैं, अपने वित्त मंत्री जी ने उन स्कीमों को शामिल करके इस साल का बजट पेश किया है, जिस पर हम अलग से चर्चा करने वाले हैं। फिर भी, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आए एक-दो मुद्दों पर मैं यहां बोलना चाहता हूं।

जब माननीय लालबहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधान मंत्री थे, उस समय हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। उन दिनों टी.वी. नहीं होता था लेकिन ऑल इंडिया रेडियो में जब हमने शास्त्री जी का भाषण सुना जिसमें उन्होंने कहा था कि देश कष्ट में है, हमें खाने को चावल नहीं मिलता और उन्होंने देशवासियों से अपील की - I appeal to the people - कि हर सोमवार रात्रि उपवास करना चाहिए, मैंने तुरंत उस अपील का पालन किया। उनकी अपील का पालन करने में आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि बचपन से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। उस समय मैं एक सरकारी कर्मचारी था। मेरे अलावा अन्य सरकारी कर्मचारियों ने भी उनकी अपील का पालन किया, क्योंकि शास्त्री जी में आम जनता का बहुत विश्वास था। आपको अभी भी याद होगा, जहां लालबहादुर शास्त्री जी की अपील का जनता ने पालन किया, उसके बाद अगली बार, जब मान्यवर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एल.पी.जी गैस consumers से अपील की कि जो लोग समर्थ हैं, उन्हें गैस सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए, तुरंत एक करोड़ बीस लाख लोगों ने अपना सब्सिडी वापस कर दी। इसका अर्थ क्या है? यह आश्चर्य का विषय है कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आम जनता में कितना विश्वास है, यह उसे प्रदर्शित करता है।

दूसरा विषय है कि आज सब लोग बोलते हैं कि देश की पॉपुलेशन में पुरुषों की संख्या ज्यादा है और महिलाओं की संख्या कम हो रही है। यह जो परसेंटेज़ में फर्क है, उसके लिए क्या करना है, बेटी के लिए क्या करना है, उसकी चर्चा आज भी हुई है।

(डीएस/2E पर जारी)

-VKK/BHS-DS/2E/2.15

SHRI LA. GANESAN (CONTD.): There is one another demography**,** जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। मैं सुझाव दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग विरोध करेंगे। यह बात अच्छी तरह जानते हुए भी मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। जैसे प्रधान मंत्री जी ने "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" की घोषणा की है, उसी प्रकार "बेटी बढ़ाओ" के लिए भी एक घोषणा की जानी चाहिए। हर एक घर में एक बेटा-दो बेटी, ऐसी अगर एक घोषणा की जाती है, तो उससे बेटियों की संख्या अधिक होगी। मेरा सुझाव है, "एक बेटा-दो बेटी, रक्षा करेंगे देश की माटी" यह स्लोगन भी हम दे सकते हैं।

इस चर्चा की शुरुआत में मैंने प्रतिपक्ष के नेता का भाषण सुना। यहाँ आने के बाद मुझे उनका भाषण बार-बार सुनने का मौका मिला है। उनकी आवाज इतनी सुन्दर है कि जब मैं उनको सुनता हूँ, तो वह मुझे बहुत पसंद आती है। गुलाम नबी आज़ाद जी आज सभा में नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज अच्छी है, सुन्दर है, लेकिन विषय के बारे में कुछ विरोध करने की बात भी है। उन्होंने कश्मीर के बारे में बताया। कश्मीर के बारे में बोलते समय उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली आम जनता को कितना कष्ट है, उनके लिए सुविधा नहीं है आदि। मेरे मन में बहुत कष्ट हुआ। मुझे जो कष्ट हुआ, उसका कारण यह है कि कांग्रेस सत्ता में 60 साल तक रही और 60 साल तक सत्ता में होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता अगर यह बताते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली आम जनता को इतना कष्ट है, तो इसका कारण क्या है? Who is responsible for that?

उन्होंने दूसरा विषय यह बताया कि वहाँ हमारे बहुत-से जवान हैं। More Forces are there. He has mentioned about that also. मैं पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर में इतनी अधिक फोर्सेज़ क्यों हैं? ...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति : आपका 10 मिनट का समय समाप्त हो गया।

श्री नारायण लाल पंचारिया : अगले वक्ता का टाइम कम कर दीजिएगा।

श्री उपसभापति : बाकी और लोगों का समय कम कर दूँ?

श्री नारायण लाल पंचारिया : जी हाँ, सर।

श्री उपसभापति : ठीक है, आप बोलिए।

श्री ला. गणेशन : एक हॉस्पिटल में सैंकड़ों पेशेंट्स आते हैं, लेकिन जब एक ही पेशेंट के पास चार-पाँच डॉक्टर्स बार-बार जाते रहें, तो उसका कारण यह होता है कि वह पेशेंट सीरियस होता है। That is the reason. पूरे देश के मुकाबले कश्मीर में अधिक Armed Forces हैं, तो इसका कारण यह है कि कश्मीर की स्थिति खतरनाक है, वहाँ सिचुएशन ठीक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कर्फ्यू के बारे में अपनी बात कही, लेकिन वह कर्फ्यू क्यों लगाया गया? उसका कारण क्या है, उसके पीछे कौन है, इसके बारे में आप एक वाक्य भी नहीं बोले। मैं तमिलनाडु से आया हूँ। आप कश्मीर से हैं और मैं कन्याकुमारी से हूँ। Though I am from Chennai, Tamil Nadu, I am very much concerned about the people of Kashmir. मैं कश्मीर के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि कश्मीर के बारे में सोचने और उसके बारे में बोलने का मेरा अधिकार है। उसका नाम कश्मीर इसलिए पड़ा, क्योंकि it was a Kashmir *Maharishi*, जिनके कारण

उसका नाम कश्यपनीरम् पड़ा, जो आजकल कश्मीर हो गया है। ऐसा मैंने सुना है और पढ़ा है। मैं कश्यप गोत्र में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुझे यह अधिकार है। भारत एक देश है, ऐसा मैं सोचता हूँ, इसलिए मुझे यह अधिकार है। लेकिन, आपको भी सोचना चाहिए कि आज तमिलनाडु में क्या हो रहा है? The people those who are inspired by Pakistan, वैसे उग्रवादियों के हाथों तमिलनाडु में 130 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता और अलग-अलग हिन्दू संगठनों में काम करने वाले लोग शामिल थे। यह अभी भी चल रहा है, लेकिन उनके बारे में आप नहीं बोलते हैं। कश्मीर में इतनी मिलिट्री फोर्सेज़ क्यों हैं, आप केवल इस बारे में बोलते हैं। आप पूरे देश के बारे में बोलिए। आपकी राष्ट्रीय पार्टी है और आप एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, इसलिए पूरे राष्ट्र के बारे में आपको भी चिन्तन करना है, सोचना है, यह मेरी प्रार्थना है। इसके अलावा, एक और दूसरा विषय भी है।

(2एफ/एमसीएम पर जारी)

MCM-DC/2F/2.20

श्री ला0 गणेशन (क्रमागत) : दूसरा विषय है, पांच सौ रुपये का एक नोट मिला है। एक साइड से यह तो आधा साफ है, सिम्पली व्हाइट है और केवल आधा प्रिंटेड है। Sir, exception makes the rule. अगर कोई पांच सौ का नोट खराब है तो यह मसला पार्लियामेंट में देखने के लिए, बोलने के लिए विषय नहीं है। इसके लिए रोज अखबार में छापते हैं। It is an exception because man has bitten the dog and, that is why, they have printed it in the newspaper. I never expected that such a small

thing will be raised in this august House by a senior leader. उन्होंने अच्छी तरह अध्ययन किया है। पूरे विदेश के अखबारों में demonetization के बारे में क्या-क्या छपा है, क्या-क्या article है। He has studied all the newspapers that publish in foreign countries but they have not studied the mood of the आम जनता of India. आम जनता अलग सोचती है तथा वह demonetization को सपोर्ट करते हैं। Demonetization घोषित करने के बाद हुए सभी चुनावों में, even we have won in many places where we had not at all won so far. The people are with us. So please study the mood of the people before studying the articles published in other countries. This is my only request. .....(समय की घंटी)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri La. Ganesan, now please conclude.

SHRI LA. GANESAN: Sir, I will tell you here that I never expected that I would be called yesterday. That is why मैं विस्तार से बोलने के लिए तैयारी करके आया हूं, लेकिन आप बोलते हैं, and I am a disciplined soldier, so मैं अब समाप्त करता हूं।

(समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Rajeev Shukla.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : धन्यवाद उपसभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो माननीय विधि और न्याय मंत्री लाए हैं, उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, अमूमन मैं पिछले कई सालों से धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलता रहा हूं,

पिछले दो साल मैंने जान-बूझ कर सरकार की आलोचना नहीं की थी, क्योंकि मैं उनको कहता था कि जब कोई चुनकर आए तो उनकी तुरन्त आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसको वक्त देना चाहिए कि वह अपने कार्यक्रमों को लागू करे, अपनी नीतियों को लागू करे, अपने फैसलों को लागू करे। इसलिए अपनी कंस्ट्रक्टिव स्पीच उस समय दी थी कि यह सरकार कुछ करेगी। लेकिन पौने तीन साल बाद राष्ट्रपति जी का यह तीसरा अभिभाषण है और मैंने पाया कि इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, कोई ऐसी नई चीज नहीं है जिसकी सराहना की जाए। उसको लेकर, उसको पढ़कर काफी निराशा हुई, क्योंकि यह एक सरकारी दस्तावेज होता है जो सरकार देती है और राष्ट्रपति जी अपनी सरकार के उस क्रियाकलाप को पढ़ते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जो सरकार है उसको काम करने के अब डेढ़ साल बचे हैं, क्योंकि आखिरी 6 महीने तो चुनावों के कारण लग जाते हैं। अभी तक जो उनका रिकॉर्ड है, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं जो देश को राहत प्रदान कर सके, चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो, चाहे सामाजिक मोर्चे पर हो, चाहे किसी मोर्चे पर हो। तो इसलिए यह अभिभाषण सुनकर हमें बहुत निराशा हुई है। आज मैं यह समझता हूं कि सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, खास तौर से पार्टी के लोग। जिस तरह से ये लोग महिमामंडन में लगे हुए हैं उसके बजाए जो सही फीड बैक, सही बात है, अपने नेता को बताएं, तो शायद स्थिति में बदलाव आए, लेकिन कोई बतलाता नहीं। सेंट्रल हॉल में बैठकर आलोचना करते हैं ये लोग, लेकिन वहां जो है, उनको सही पिक्चर, तस्वीर नहीं देते कि क्या स्थिति नीचे है, क्या जमीन पर स्थिति है। वे कहते हैं सब सही चल रहा है, हर चीज गुलाबी है, रोज़ी पिक्चर उनके सामने रखी

जाती है और यहां पर बोलते भी हैं। ठीक है, वह नौकरी का खतरा होता है, जो अपनी जगह है। लेकिन फिर भी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए तो बताना चाहिए कि असलियत क्या है। चाय-कॉफी पर सेंट्रल हॉल में चर्चा होती है, वहां अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन बाहर जो स्थिति है, वह सदन में आकर, उनके पास मिलकर नहीं कहते। मैं तो उनको 20 साल से जानता हूं, वे सुनेंगे। ऐसा नहीं है, प्रधान मंत्री बहुत व्यस्त होता है, उसके ऊपर रात दिन इतना काम होता है, मैं तो प्रधान मंत्री के डॉयरेक्टली अंडर में काम कर चुका हूं, इतना काम होता है कि उनको फुर्सत नहीं होती। आप लोगों का फर्ज बनता है कि उनको बताएं, उनको समझाएं। वे सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई बताता नहीं। आज मैं पूछता हूं कि अगर सब ठीक है तो किसान क्यों दुखी है, मजदूर क्यों दुखी है, दुकानदार क्यों दुखी है, व्यापारी क्यों दुखी है, आम आदमी क्यों दुखी है, जो टूरिस्ट आ रहा है, वह परेशान है। हर तरफ तो लोग आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि परेशान हैं। आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक है। यह वैसे ही है जब सरकार को 8 साल हो जाते हैं, तब इस तरह का अहंकार आता है, तब इस तरह का लगता नहीं है कि सब ठीक है।

(2G/SC पर जारी)

SC-KR/2.25/2G

श्री राजीव शुक्ल (क्रमागत) : अब यह ढाई-पौने तीन साल में हो गया है। इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है। यही मुझे उधर से सबके भाषण में लग रहा है,

चाहे प्रस्तावक का भाषण हो, जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया है, चाहे समर्थक का हो या बाकी लोगों का हो, जिन लोगों ने भाषण दिया है।

आज आप किसान को देखिए। उसे न बीज मिल रहा है, न खाद मिल रही है। उसे अपना सामान फेंकना पड़ रहा है। आप सब भी इस बात को जानते होंगे कि आलू और टमाटर का दाम कितना सस्ता हो गया, पांच रुपए, दस रुपए किलो हो गया। उसने अपना सारा सामान फेंक दिया क्योंकि उसका सारा माल सड़ गया था क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रखने की कीमत इतनी अधिक थी कि वह उसे बरदाश्त नहीं कर सकता था, बाज़ार में उसे अपने सामान की उतनी कीमत नहीं मिल रही थी। इस प्रकार किसानों का यह हाल हो रहा है। उन्हें अपना समर्थन मूल्य नहीं मिलता, जो आपने वायदा किया था। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे नहीं आ रही है, जो लागत लगती है। इस प्रकार किसान बहुत बुरी हालत में है। माननीय आज़ाद साहब ने आंकड़ा दिया कि 36 प्रतिशत किसानों ने आत्महत्या की। हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको देखने और समझने की जरूरत है। मेरा आपको सुझाव है कि आप इस तरफ ध्यान दें। किसान बेहद दुखी और परेशान हैं। दूसरी तरफ दुकानदार हैं। छोटे-छोटे करोड़ों दुकानदार त्रस्त हैं, सब परेशान हैं। किसी का माल नहीं बिक रहा है, फैक्टरियां बंद हो रही हैं, मज़दूर बेरोज़गार हो रहे हैं। आप देखिए कि कितनी ट्रेनें भरकर जा रही हैं। कोई छठ पूजा नहीं है, फिर भी बिहार, ओडिशा और बंगाल की ट्रेनें भरी हुई हैं क्योंकि सब मज़दूर वापस जा रहे हैं, फैक्टरियां बंद हो गयी हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। अर्थव्यवस्था में जीडीपी नीचे जा रहा है। यह चीज़ भी देखने लायक है कि

लोगों की कितनी बुरी हालत हो रही है। उसको अगर आप सिर्फ यह समझें कि चूंकि हम आलोचना कर रहे हैं, इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं देना है तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप गलती कर रहे हैं, कहीं न कहीं चूक कर रहे हैं।

आप जीतने की बात करते हैं। मैं आपको महाराष्ट्र का एक उदाहरण देता हूं। वहां पर 2,100 नगरपालिकाएं हैं। आप कहते हैं कि हम जीत गए। वहां 600 सीटें बीजेपी को मिलीं, 500 के करीब एनसीपी को मिलीं, 480 कांग्रेस को और 490 शिवसेना को मिलीं। कांग्रेस भी नोटबंदी की आलोचना कर रही थी, शिवसेना भी नोटबंदी की आलोचना कर रही थी और एनसीपी भी नोटबंदी की आलोचना कर रही थी। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो 1,500 से 1,600 जगह आप हारे, सिर्फ 600 जगह ही तो जीते। अगर आप नोटबंदी को mandate मान रहे हैं, तो फिर इसे जीत कैसे कहेंगे? कॉर्पोरेशन और छोटे-छोटे निकायों में नोटबंदी के बाद 1,600 जगह आप हारे और 600 जगह जीते। अगर नोटबंदी पर mandate है तो एक तरह से यह mandate आपके खिलाफ था। इसलिए आपको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि नगरपालिका और ग्राम पंचायत के चुनाव में नोटबंदी की वजह से आपको वोट मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये बातें आपको सही रास्ते पर ले जाएंगी, इसलिए आपको यह सब देखना पड़ेगा। चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे बिज़नेस हो, आप लोगों को रोज़गार कैसे देंगे? आपने कहा कि दस करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन आज manufacturing sector, छोटी-छोटी इकाइयों और उद्योगों का बुरा हाल है, वे सब बंद हो रहे हैं। सबके पीछे इंस्पेक्टर लगा हुआ है। जहां देखो, आपने एक ही काम किया है कि डंडा लेकर हरेक के पीछे इंस्पेक्टर

लगा हुआ है। आज करोड़ों नोटिस issue होंगे - आज इसको नोटिस, कल उसको नोटिस - हर डिपार्टमेंट लगा हुआ है तो रोज़गार कौन देगा? अगर वे सब भाग जाएंगे तो रोज़गार कौन देगा? आप दुबई के अपने Consulate General की लिस्ट मंगा लीजिए कि आज कितने लोग दुबई में जा-जाकर बस रहे हैं और Emirates Hills में घर ले रहे हैं क्योंकि भगदड़ मची हुई है। इसलिए यह चीज़ देखने, सोचने और समझने की है। आप यह मत समझिए कि हम आप पर कोई आरोप लगा रहे हैं या आपकी आलोचना कर रहे हैं। इस चीज़ को देखने की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। Cashless Economy अच्छी है, आप शुरू कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे-धीरे कीजिए, डंडा मारकर एक दम नहीं करा दें, यह बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था का आपको पता ही है कि जीडीपी का क्या हाल है। आज तो यह रिपोर्ट भी आयी कि डॉलर 70 रुपए का हो जाएगा। जब चुनाव हुए थे तो आपने वायदा किया था कि हम डॉलर को पचास रुपए पर ले आएंगे, वह भी आपके एक वायदे में शामिल था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसा आपने कहा कि नोटबंदी करने का आपका मुख्य मकसद काले धन पर रोक लगाना था। क्या एक रुपए का भी काला धन आया है, इस पर सरकार जवाब दे? मुझे नहीं लगता कि एक रुपए का भी काला धन आया, बल्कि जिनके पास काला धन था, उन्होंने भी सफेद कर लिया, बैंकों में चला गया। तो या तो काले धन की परिभाषा गलत थी, जिस पर आप काम कर रहे थे या आपने पूरा होमवर्क नहीं किया था। यह चीज़ समझने की है, जिसका आपको जवाब देना चाहिए।

दूसरा, आपने जाली नोट और आतंकवाद के बारे में कहा। आतंकवादियों के पास लबालब लाल नोट निकल रहे हैं। इसका मतलब उन्हें भी सब मिल गया। इस प्रकार न इससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो पायी और न आप काले धन की लड़ाई लड़ पाए, केवल लोग त्रस्त और परेशान हुए और इसका economy पर दूरगामी प्रभाव पड़ा, इसलिए यह चीज़ भी समझने की जरूरत है।

तीसरा, जो संवैधानिक ढांचा है, जो संस्थाएं हैं, उनके संबंध में यह आपका प्रयोग है। मैं नहीं कहता कि आप प्रयोग मत कीजिए - हर सरकार करती है, यह आपका प्रयोग है, लेकिन सोचना-समझना चाहिए, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपने योजना आयोग खत्म कर दिया और नीति आयोग बना दिया। वहां नीति कम, राजनीति ज्यादा है। पहले मैं योजना मंत्री था, योजना आयोग में बैठता था। कुछ न कुछ प्लानिंग, कुछ न कुछ अंकुश, कुछ न कुछ समीक्षा होती थी। अब तो पता ही नहीं चलता कि नीति आयोग कर क्या रहा है? नीति आयोग में क्या हो रहा है, कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पहले हर मुख्य मंत्री को वहां पर अपनी बात रखनी पड़ती थी - ठीक है, कुछ मुख्य मंत्रियों को उसका बुरा लगा होगा कि क्यों जाना पड़ता है?

(2एच-जीएस पर जारी)

KS-GS/2H/2.30

श्री राजीव शुक्ल (क्रमागत): लेकिन एक परम्परा थी। कोई मुख्य मंत्री जब केन्द्र में मंत्री हो जाते हैं, प्रधान मंत्री हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि मुख्य मंत्रियों की जवाबदेही होनी चाहिए, राज्यों की जवाबदेही होनी चाहिए। जब तक वे राज्यों में रहते

हैं, तब तक उन्हें लगता है कि कोई अन्याय हो रहा है। सब मिल-जुल कर सभी स्कीमों पर काम करते थे। योजना आयोग में चतुर्वेदी कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसने तमाम योजनाओं को, स्कीमों को खत्म करने की बात कही थी, उसका कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है? बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जिनका पैसा नीचे तक पहुंचता ही नहीं है, सिर्फ कागजों पर रह जाता है या ब्यूरोक्रेसी में गड़प हो जाता है। उन सारी योजनाओं का क्या हुआ? उन सारी योजनाओं पर जो काम चल रहा था, उस काम का कहीं पता नहीं चल रहा है कि वह कहां पर है? इसी तरह से FIPB आपने खत्म कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका alternative system क्या रहेगा, यह लोगों को नहीं पता कि कैसे क्लियरेंस लोगों को FIPB पर मिलेगी?

आपने रेल बजट खत्म कर दिया। प्रभु जी की ऐसी लीला हुई बेचारों की कि उनका जलवा ही खत्म हो गया। उनका कुछ पता नहीं, हाउस में भी आने में बेचारे शरमा रहे हैं। क्या जलवा होता था, दो राज्य मंत्री साथ होते थे, उनके फोटो खिंचते थे। पूरा एक दिन शानदार होता था, सब लोग चर्चा करते थे, बहस होती थी, अब पांच मिनट में रेल बजट समाप्त हो गया। पूरी परम्परा खत्म हो गई, उसमें सिर्फ क्या allocation और provision है, सिर्फ इतना पता चला, आगे क्या डिटेल है किसी को कुछ पता नहीं, तो रेल बजट भी खत्म कर दिया।

आर.बी.आई. की स्वायत्तता को लेकर पहले से ही आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। आपको कहीं न कहीं यह सोचना चाहिए कि इन संस्थाओं के बारे में क्या हुआ। इन

संस्थाओं का जो प्रयोग हम कर रहे हैं, वह उचित है या इसका कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी आपको सोचने की जरूरत है।

उपसभापति जी, कुछ चीजों का इसमें जिक्र ही नहीं है, जैसे गंगा का प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना हो-हल्ला हुआ, ऐसा लग रहा है कि न जाने क्या हो जाएगा? चूंकि गंगा जी के स्वच्छीकरण के लिए कोई इस तरह का कारगर चीज़ हुई नहीं, इसलिए "नमामि गंगे" का कोई जिक्र ही नहीं है। वह सब्जेक्ट ही गोल कर दिया।

विदेश नीति की बात आती है, विदेश नीति में कहीं न कहीं.. सुषमा जी बहुत बीमार हैं, हम सब उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं कि वे जल्दी स्वस्थ हों। उनकी तरफ से जितनी कोशिश होती है, वे करती हैं। वे ट्विटर के माध्यम से सहायता करने की कोशिश कर रही हैं। आज आप देखिए कि सब पड़ोसियों से रिश्ते बिगड़ गए हैं। अब अमेरिकी सरकार का जो रुख है, कोई भी बात उनसे की हो, वहां पर लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं, जो काम आउटसोर्सिंग का मिलता था, हमारी आई.टी. कम्पनियों को मिलता था, वह भी खतरे में आ गया है, तो कहीं न कहीं विदेश नीति पर भी प्रधान मंत्री जी को ध्यान देना पड़ेगा कि सब कुछ सही नहीं है। हमारे अपने सभी पड़ोसियों से रिश्ते खराब हैं। पाकिस्तान से तो रिश्ते बहुत ही खराब हो चुके हैं। जबकि उन्होंने पहल की थी, अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज़ शरीफ को बुलाकर, उनकी पोती की शादी में जाकर, उन्होंने पूरा गले लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका परिणाम देश के हित में आया हो, ऐसा नहीं है। जब हम सरकार में थे, तो हमारी बड़ी आलोचना होती थी। अगर हम धोखे से भी लाहौर की तरफ मुंह कर लेते थे या

इस्लामाबाद की तरफ देख लेते थे, तो हमारी इतनी आलोचना होती थी कि पता नहीं हमने कौन सा अपराध कर दिया। आपने पूरा गले लगाया, सब किया, इसकी हमने तो सराहना की, अच्छा है, रिश्ते मजबूत करने चाहिए, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं आया है। सर्जिकल स्ट्राइक - यह पब्लिसिटी लेने के लिए नहीं है। हर चीज़ को इवेंट बनाओ, मार्केटिंग करो, हंगामा करो और उसके बाद असलियत में वह विवादास्पद बन जाए। देखिए, ओवर मार्केटिंग हर चीज़ की, नुकसान करती है, ओवर पब्लिसिटी हर चीज़ में नुकसान करती है। हमारी सरकार में भी तीन बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और यह आर्मी का काम है, वह ऐसा करे। लेकिन ऐसा लगा कि यह पहली बार हुआ है। हमें तो यह घबराहट हुई कि कहीं इस्लामाबाद पर कब्जा तो नहीं हो गया है, जिस तरह से चारों तरफ से हंगामा हो रहा था, पता ही नहीं लग रहा था। जब इंदिरा जी ने 1971 का युद्ध लड़ा था, तब उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। इस तरह से लग रहा था कि रक्षा मंत्री कोई गदा लिए हुए आगरा में खड़े हैं, कोई बाण लिए हुए खड़ा हुआ है, कोई कुछ लिए खड़ा है, पता नहीं क्या-क्या कर दिया । आखिर में जनरल को खड़े होकर कहना पड़ा कि भाई साहब, यह तो पहले भी हो चुका है, तब यह बात खुली। फिर विदेश सचिव को बोलना पड़ा कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हो चुकी है, यह कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे काम 26 मई, 1914 के बाद ही हुए हैं, उसके पहले भी देश में बहुत काम हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके पहले कुछ हुआ ही नहीं है, चाहे जो सरकारें रही हों। यह जो attitude है, इसके कारण प्रॉब्लम आती है। इतनी ज्यादा

पब्लिसिटी कर देते हैं कि उससे दिक्कत आती है, मुझे दुष्यंत कुमार का शेर याद आ रहा है -

" अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार,
घर की दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार ।"

ये जो आपने इश्तिहार चिपका कर दरारें छिपा रखी हैं। यह आपके हित में नहीं है, क्योंकि पानी अंदर आ जाएगा, हवा अंदर आ जाएगी, ठंड अंदर आ जाएगी। इससे आपको ही नुकसान होगा। इसलिए इश्तिहार हटाओ और दीवार की दरारों को भरने का काम करो। तभी जाकर होगा, इसमें आप सोचो कि हम आलोचना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हां, आपने स्वच्छता अभियान शुरू किया, यह अच्छी बात है। इसको गांधी जी ने शुरू किया था और इसको आपने आगे बढ़ाया, यह बहुत अच्छी बात है। चाय पीने जाओ, तो स्वच्छता शुल्क लगता है।

(HMS/2J पर जारी)

RSS-HMS/2.35/2J/

श्री राजीव शुक्ल (क्रमागत) : समोसा खाने जाओ, तो स्वच्छता शुल्क लगता है। आज रेस्टॉरेंट में और हर जगह आप स्वच्छता शुल्क ले रहे हैं। सर, मेरे पास इस के आंकड़े हैं, जिनके अनुसार 9800 करोड़ रुपया इस में इकट्ठा हो रहा है, लेकिन यह रुपया कहां जा रहा है? आप सिर्फ टॉयलेट्स बनाने की बात कह रहे हैं। महोदय, सब से बड़ी समस्या खुली नालियों की है। जब तक आप सीवेज सिस्टम नहीं बनाएंगे तब तक सिर्फ टॉयलेट्स बनाने से वह वेस्टेज या मल कहां जाएगा? वह तो नालियों में खुला घूमता

रहता है जिस कारण ज्यादा infection फैलता है और उससे ज्यादा बैक्टीरियाज़ जनरेट होते हैं। इसलिए आप साथ-साथ सीवेज सिस्टम बनाने की योजना शुरू करिए। आप इस पैसे से सरकार की तरफ से जगह-जगह डस्टबिन्स रखवाइए। आप ग्रीन ब्रिगेड बनाइए और इस तरह से गरीब युवकों को रोजगार दीजिए। ये ग्रीन ब्रिगेड के लोग कपड़े पहनकर जगह-जगह कूड़े की सफाई करें। आप डस्टबिन रखिए, सीवेज सिस्टम बनवाइए ताकि खुली नालियां खत्म हों। तब जाकर यह कार्यक्रम comprehensively चालू हो पाएगा। आप रेल लाइंस के किनारे-किनारे चले जाइए, आपको बहुत गंदगी देखने को मिलेगी और जब कोई विदेशी हमारी ट्रेन में बैठकर जाता है, तो वह देखकर अचम्भित हो जाता है कि क्या कोई देश ऐसा भी हो सकता है? स्वच्छता अभियान बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन आप इसे एक comprehensive plan के तौर पर चलाइए और उसमें वेस्ट मैनेजमेंट की सारी व्यवस्था कीजिए। अगर आप इस तरह चलाएंगे तो यह भारत देश के लिए बड़ी अच्छी योजना हो सकती है, लेकिन खाली इसके प्रचार और विज्ञापन से काम नहीं होगा।

दूसरी बात, आप हमारी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, यह अच्छी बात है, चाहे वह आधार कार्ड की योजना हो। मैं जब योजना मंत्री था तो 167 करोड़ आधार कार्ड बन चुके थे। आपने इस योजना को आगे बढ़ाया, यह बहुत बढ़िया बात है। हमारे insurance reforms को आपने आगे बढ़ाया, अच्छी बात है। आपने banking reforms को बढ़ाया, अच्छी बात है। राजीव जी ने Digitisation और Computerisation शुरू किया था, उस समय उन की आलोचना हुई थी, आप इसे आगे ले जा रहे हैं, हम इस के लिए कोई

आलोचना नहीं करते बल्कि यह अच्छी बात है, लेकिन यह मत कहिए कि हमने यह सब शुरू किया है, इस के पहले कुछ था ही नहीं। यह श्रेय लेने की होड़ में कहीं ऐसा न हो कि आप पहले के लोगों के किए काम को भुला दें। महोदय, अटल जी के कामों का भी कोई जिक्र नहीं होता। अटल जी ने कभी श्रेय नहीं लिया कि यह मैंने किया। जो पिछले काम अच्छे थे, उन्होंने आगे बढ़ाया। आप भी वैसा कर रहे हैं, यह अच्छी चीज है।

मैं एक बात ज्यूडिशियरी के बारे कहना चाहूंगा। महोदय, करीब ढाई करोड़ केसेज कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, लेकिन विवाद चल रहा है और ज्यूडिशियरी से टकराव भी चल रहा है। इस बारे में कुछ रास्ता निकाला जाना चाहिए। आप National Judicial Appointments Commission का एक बिल यहां लाए थे, जोकि unanimously पास हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे टर्न डाउन किया और कहा कि इस में कुछ improvement होना चाहिए। आप उसे दोबारा से improve कर के या चेंजेज कर के ला सकते थे। अब न वह आ रहा है और न यह आ रहा है। इस वजह से ज्यूडिशियरी में किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भारत सरकार में चपरासी से लेकर राष्ट्रपति महोदय, प्रधान मंत्री, मंत्री, एम0पी0 और एम0एल0ए0 तक की अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन एक जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में संसद को और सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर उनकी भी कुछ अकाउंटेबिलिटी हो। हर सेक्टर में रिफॉर्म्स हों - आसमान में रिफॉर्म हो, जमीन पर रिफॉर्म हो, सब का रिफॉर्म हो, लेकिन ज्यूडिशियरी में कोई रिफॉर्म न हो। यह कौनसा attitude है? वहां भी रिफॉर्म होना चाहिए। आज ज्यूडिशियरी की बहुत आलोचना हो रही है, बहुत बातें हो

रही हैं। आज जजेज़ भी कह रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि यह सिस्टम opaque है। यह कोलीजियम सिस्टम मनमाने ढंग से चलाया जाता है। सर, यह तो बहुत गंभीर बात है। अगर कोलीजियम का एक मेंबर कह रहा है, तो इस बात का नोटिस लेकर गवर्नमेंट को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। इस बारे में संसद आपके साथ है। इसलिए आपको इस बारे में कदम जरूर उठाना चाहिए। आप इसे बीच में छोड़कर भाग गए, यह बात ठीक नहीं है। ..(समय की घंटी)..

सर, आप घंटी बजा रहे हैं, इसलिए हम अपनी पूरी बात नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन मैंने आपके सामने कुछ चीजें रखी हैं। आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए और जो डेढ़ साल आपका बचा है, उस डेढ़ साल में ये सारा काम कीजिए वरना बशीर बद्र साहब ने फरमाया है कि,

"शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है,
जिस साख पर बैठे हो, वह टूट भी सकती है।"

इस बात का ध्यान रखिए। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should translate it also. You should translate the couplet.

SHRI RAJEEV SHUKLA: The fame is a very temporary thing. Otherwise, we are sitting on a branch of a tree which can break also.

(Ends)

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, यह मेरी maiden speech है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Maiden speech means, you can take maximum 15 minutes.

श्री संजय सेठ : सर, हम दो लोगों को ही बोलना था, जितना समय बचा हो दे दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I said. Maiden speech के लिए maximum time 15 minutes.

(2 के/एएससी पर आगे)

ASC-KGG/2.40/2K

श्री संजय सेठ : सर, over and above….

श्री उपसभापति : बोलिए, बोलिए।

श्री संजय सेठ : सर, मैं सबसे पहले तो आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रति पूर्ण श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि उनके उद्बोधन में बहुत ही नीतियां और योजनाएं गलत हैं। उसमें बिल्कुल वैसे ही किया हुआ है, जैसे किसी फाइल की नोटिंग में होता है। जिसमें जमीन के धरातल पर क्या-क्या हो रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है।

सर, इसमें सबसे पहले इन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास' के बारे में कहा है। मैं मानता हूं कि उसमें यह बिल्कुल गलत नारा है। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि इस केन्द्र सरकार ने जहां-जहां बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें हैं, वहां उनको पूरे सहयोग और विकास में सहायता दी है, लेकिन जहां गैर बीजेपी शासित

प्रदेश हैं, वहां पर इन्होंने उनका कोई साथ नहीं दिया है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में बहुत सारी केन्द्र से संबंधित योजनाएं हैं, जिनके लिए हम लोगों ने केन्द्र से पैसा मांगा था। हम लोगों ने पिछले सत्र में भी आपका ध्यान उनकी ओर दिलाया था, लेकिन आज तक इन्होंने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि 'सबका साथ, सबका विकास' बिल्कुल नहीं हो रहा है। यह सिर्फ इनका अपना विकास हो रहा है।

सर, अभी तक केन्द्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही थीं, वे सबकी सब अब पीछे चली गई हैं, सिर्फ एक नोटबंदी की योजना ही दिख रही है। इस नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश की सरकार को हुआ है, क्योंकि आबादी के हिसाब से यह सबसे बड़ा प्रदेश है। सर, हमारे यहां किसानों की सारी फसलें, उपजें, खराब हो चुकी हैं। उनका सारा सामान नष्ट हो चुका है। किसानों को बीज नहीं मिला, fertilizer नहीं मिला, जिसके कारण उनका यह सारा सीज़न खराब हो गया। जब किसान का एक सीज़न खराब होता है, तो पूरे दो साल तक उसकी आर्थिक चीजें खत्म हो जाती हैं। किसानों के लिए जो कर्ज़ माफी थी, उसके लिए आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया है।

सर, श्रमिकों का भी बहुत बुरा हाल है। सारे कंस्ट्रक्शन की लेबर वापस चली गई है। उनके पास पैसा नहीं है और सब अपने-अपने क्षेत्रों से वापस जाकर पलायन कर चुके हैं। सर, व्यापारियों का हाल तो सबसे बुरा है। आज उनके 40 से 50% बिजनेस खत्म हो चुके हैं। आज उनके पास पैसा न होने की वजह से उनको अपने बिजनेस से

कर्मचारियों को निकालना पड़ रहा है। सर, कर्मचारियों की नौकरियां जा रही हैं, तो बेरोजगारी का लेवल अब एक बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। इस नोटबंदी में जो एक चीज देखने में आई, वह यह कि इस पीरियड में सैकड़ों सर्कुलर जारी हुए। कुछ ऐसे सर्कुलर भी जारी किए गए, जो मज़ाक का विषय बने। जैसे एक विषय बना कि आप केवल पांच हजार रुपए जमा कर सकते हैं। जब उसका मज़ाक बना, तो उसको 24 घंटों में ही वापस कर दिया गया। यह सब शो करता है कि किसी प्लानिंग के हिसाब से ये सारी चीजें नहीं हो रही थीं।

सर, इसके बाद इन्होंने कैशलेस इकोनॉमी की तरफ सबका ध्यान खींचा। जिस देश के अंदर ग्रामीण अंचलों में आदमी सिग्नेचर नहीं कर पाता है, अंगूठा लगाता है

(उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) पीठासीन हुए)

और उसको स्मार्ट फोन से मोबाइल बैंकिंग के लिए कहा जाए, तो यह बड़ी हंसी की चीज नजर आती है। इन लोगों को सबसे पहले साक्षरता की तरफ देखना चाहिए था, इसके बाद ही कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था।

सर, ATMs की जो पोजिशन है, इसमें यहां पर एक लाख पर बीस ATMs हैं, जबकि पूरे विश्व में तकरीबन एक लाख की आबादी पर सौ ATMs होते हैं। अब मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि इसमें secrecy रखने की क्या जरूरत थी? पहले इसको कर लिया जाता, तब नोटबंदी और कैशलेस का काम किया जाता।

(2L/LP पर जारी)

LP-KLS/2.45/2L

श्री संजय सेठ (क्रमागत) : सर, इनकी एक "प्रधान मंत्री आवास योजना" है। यह एक अच्छी योजना है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। मैंने भी एक वेबसाइट खोलकर देखी तो उसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि इसको कौन, कैसे और कहाँ से अवेल करेगा? इसकी पूरी जानकारी नहीं है। जब आप सब चीज़ों के इतने विज्ञापन देते हैं, तब इसकी भी डिटेलिंग होनी चाहिए कि इसको कोई कैसे अवेल कर सकता है और कैसे उसके इंटरेस्ट की सब्सिडी उसको मिल सकती है?

सर, यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में हम लोगों की एक "समाजवादी आवास योजना" चल रही है। उस "समाजवादी आवास योजना" के अंदर हम लोग गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सारे आवास उपलब्ध करवा रहे हैं। वहाँ पर यह योजना हाथों-हाथ चल रही है और करीबन लाखों मकान इस योजना के अंतर्गत बन रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से कहूंगा कि उस योजना को देखे और दूसरे स्टेट्स में भी उसको लागू करे।

सर, मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहूंगा कि अगर केंद्र सरकार गरीबों को मकान देने के लिए बहुत जिम्मेदारी से कह रही है, तो उनको, किसी गरीब आदमी को दो कमरों का एक मकान इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में देना चाहिए। आज के दिन में, जिसकी 10-15 हज़ार रुपये की तनख्वाह है, वह इंटरेस्ट नहीं दे सकता है, चाहे उसको सब्सिडी भी मिल रही हो। दो कमरों का मकान प्रोवाइड कराने के लिए उस पर लोन का इंटरेस्ट नहीं पड़ना चाहिए।

सर, मैं यह मानता हूं कि "Right to Housing" एक Fundamental Right की तरह होना चाहिए और संसद में शीघ्र ही एक कम्पल्सरी हाउसिंग बिल भी लाना चाहिए।

सर, इसके बाद "स्वच्छ भारत मिशन" का जिक्र किया गया है। यह बहुत अच्छी योजना है। हमारे हिसाब से, पूरे भारतवर्ष को इसमें पूरा सहयोग देकर यह कार्य करना चाहिए, लेकिन आज के दिन में जो टॉयलेट्स बन रहे हैं, "स्वच्छ भारत अभियान" के अंदर जो सबसे मेजर चीज़ चल रही है, उसमें उसकी मेंटेनेन्स का कोई तरीका नहीं है। जितने भी टॉयलेट्स बने हैं, उनमें किसी का दरवाज़ा टूट गया है, किसी की सीट टूट गई है, किसी की छत टूट गई है। वह पैसा बरबाद हो रहा है। वह कैपिटल अमाउंट टोटली बरबाद हो रहा है। मेरा केंद्र सरकार को यह सजेशन होगा कि जैसे हमारे सुलभ शौचालय की एक मेंटेनेन्स एजेंसी है, वैसे ही, उस तरह की किसी एजेंसी को लगाना चाहिए, जो इसको मेंटेन कर सके।

सर, इस "स्वच्छ भारत अभियान" में जो बहुत बड़ी चीज़ है, वह यह है कि सारे शहरों के गंदे नाले और नालियाँ नदी में गिर रहे हैं। प्रदेश सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह एसटीपी लगाकर, उसका पानी साफ़ करके नदियों में गिराए। चूँकि हम लोग स्वच्छ भारत का सरचार्ज भी ले रहे हैं और इनके पास पैसा भी आ रहा है, इसलिए इन स्टेट्स को एसटीपी लगाने का पैसा मिलना चाहिए, जिससे हमारी नदियाँ साफ़ हों। यदि नदियाँ साफ़ होंगी, तो शहर और उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों को फायदा मिलेगा।

सर, मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं और कॉरपोरेट्स हैं, बैंकों के मुख्यालय हैं, वे उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ़ नहीं हैं। चूँकि हमारी पॉप्युलेशन ज्यादा है, इसलिए उनको सबसे ज्यादा बिजनेस भी हम लोगों से ही मिलता है। उनकी सीएसआर के तरीके से केंद्र सरकार को ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि वह पैसा, जो बिजनेस कर रहा है, उसको अपनी एक सर्टेन परसेन्टेज सीएसआर के रूप में उस स्टेट में खर्च करनी चाहिए, जिससे कि वहाँ पर टॉयलेट का काम हो सके या और अन्य जो भी सीएसआर के रूप में काम हो सकते हैं, वे काम हो सकें।

सर, इस पूरे अभिभाषण में इनफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा चैप्टर रहा है। मेरा यह मानना है कि इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितनी भी योजनाएँ आपके यहाँ से चलाई जा रही हैं, वे ज़मीन पर नहीं दिख रही हैं। हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 23 महीनों में 302 किलोमीटर का लखनऊ-आगरा का एक एक्सप्रेस-वे, बनाकर तैयार कर दिया। सर, 23 महीनों में मकान नहीं बनता है, लेकिन हम लोगों ने 302 किलोमीटर की लैंड एक्विजिशन करके इसको पूरा तैयार कर दिया और आज वह चालू भी हो चुका है।

(klg/2m पर जारी)

KLG-SSS/2M/2.50

श्री संजय सेठ (क्रमागत): जिस वक्त आपकी सरकार बनी थी, वहां के सांसद ने यह कहा था कि लखनऊ के अंदर एक आउटर रिंग रोड बनेगी, लेकिन आज ढाई, पौने

तीन साल हो गए हैं और अभी तक उसकी शुरुआत कहीं नहीं हुई है। अगर आप इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए तेजी से काम नहीं करेंगे, तो स्कीम्स फाइलों में पड़ी रहेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी। ऐसा सिर्फ बातों से नहीं चलना चाहिए।

महोदय, विदेश-नीति के बारे में भी इसमें कहा गया है। हम लोगों के अमरीका के साथ बहुत अच्छे संबंध बताए जा रहे थे, लेकिन जब से नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, वे H-1B वीज़ा को कम कर रोजगार हटाने की बात करने लगे हैं। इस पर हमारी सरकार को उनसे जाकर बात करनी चाहिए कि हमारे इतने नौजवान वहां काम कर रहे हैं, वे नौकरी से न हटें। अगर कुछ होता है, तो हमें अपने देश के अंदर उनको रोजगार देने के लिए कुछ इकाइयां, कुछ नौकरियां ऐसी तैयार करनी चाहिए, जिससे वे यहां पर आएं तो उनको नौकरी मिले, वे बेरोजगारी न रहें। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी आज इतनी बेरोजगारी होती जा रही है कि 2016 के आखिरी क्वार्टर में 23 हजार आदमी काम से निकाले गए हैं। सब तरफ आज एक ऐसा माहौल बन रहा है, जिसे देखकर लगता है कि सब तरफ लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। इसको आपको देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा प्रदेश सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी कुछ ऐसी इकाइयां लाने का आपका विचार होना चाहिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश के नौजवान कहीं और न जाएं, उसी प्रदेश मे काम करें, चाहे वे सरकारी इकाइयां हों या अर्ध-सरकारी इकाइयां हों, उनको उनमें नौकरियां मिलें।

महोदय, स्वास्थ्य के बारे में कहीं पर कुछ नहीं लिखा है। हम लोगों की उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक समाजवादी स्वास्थ्य सेवा करके 108 नंबर की एम्बुलेन्स सेवा

शुरू की है और वह इतनी सक्सेसफुल हो रही है कि जिसको एम्बुलेन्स सेवा की जरूरत होती है, दस मिनट में उसके पास पहुंचती है। हम लोग अपने संसाधनों से तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ से हमें ऐसी कोई सहायता नहीं मिल रही है, जिससे हम उसको और आगे बढ़ा सकें। हम चाहेंगे कि उसके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार को मदद मिले। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एनवार्यनमेंट का भी इसके अंदर कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। इस प्रदूषण से निपटने के लिए क्या-क्या योजनाएं चल रही हैं, इसके बारे में भी हमें कुछ पता होना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में एक दिन में पांच करोड़ पेड़ लगाकर गिनीज़ बुक में रिकॉर्ड ...(समय की घंटी)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): एक मिनट बचा है।

श्री संजय सेठ: सर, बस एक मिनट। हम लोगों ने पांच करोड़ पेड़ लगाए। आखिर में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कई सम्मानित व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिनकी शताब्दी, जन्म शताब्दी आदि मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई स्वतंत्रता सेनानियों और उपन्यासकारों के पैतृक स्थान हैं, जैसे चन्द्रशेखर आज़ाद जी, मुंशी प्रेमचन्द जी, आज उनके पैतृक स्थानों की हालत बहुत ही खराब है, उनके मकान वगैरह गिर चुके हैं। हम चाहेंगे कि केन्द्र सरकार वहां पर भी उनके ऐसे स्मारक बनाए या ऐसे रिस्टोर करे, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी उनको पूरी तरह से देख सके। इसी क्रम में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार ने डा. मुरली मनोहर जोशी जी और शरद पवार जी को "पद्म विभूषण" से सम्मानित किया है। हमारे देश में एक गरीब किसान के घर में जन्म लेकर, लोहिया जी

के सिद्धांतों पर चलकर पिछले पचास वर्षों से किसानों, गरीबों के मसीहा धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं। इन्होंने देश के सभी वर्गों, धर्मों और लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया है, तीन बार आप उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं और एक बार देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इनको भी सरकार "पद्म विभूषण" से सम्मानित करे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

(2एन/एकेजी-एनबीआर पर आगे)

AKG-NBR/2N/2.55

श्री शरद यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी का जो उद्बोधन है, उस पर काफी लोगों ने बहुत विस्तार से कहा है। मैं राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर धन्यवाद के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस दौर का एक बड़ा फैसला नोटबंदी का हुआ है। इस सदन में एक-दो पार्टियों को छोड़ कर इस कदम का, चूँकि सरकार इसे काले धन के खिलाफ लाई थी, लोगों ने स्वागत किया। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उसमें उसका ज़िक्र तो है, लेकिन इसके नतीजे क्या हुए, कितना काला धन आया, यह सरकार को बताना चाहिए। कितने नकली या फर्जी नोट मिले और बैंक में कितना पैसा जमा हो गया, सरकार को यह भी बताना चाहिए। अभी राजीव शुक्ल जी ने काफी विस्तार से बताया कि किस-किस चीज में किस-किस तरह से नुकसान हुआ है। जो नुकसान हुए हैं, मैं उन सारी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं

इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस सारी नोटबंदी के मामले से एक बड़ी आबादी बहुत तकलीफ में आई है। सब्जी उगाने वाले जो किसान हैं, वे हिन्दुस्तान में बहुत small farmers हैं या फिर वे किसी से खरीद कर सब्जी लेते हैं। मैंने उनकी पहचान की है, लोगों से पता लगाया है, वे साढ़े तीन करोड़ लोग हैं। इस नोटबंदी के मामले में अगर सबसे ज्यादा दिक्कत, किल्लत और तबाही किसी की हुई है, तो ये जो साढ़े तीन करोड़ लोग हैं, जो सब्जी-भाजी जैसे perishable items उगाते हैं, उनकी हुई है। यहाँ किसानों की चर्चा होती है, लेकिन ये किसान बड़ी तादाद में हैं। इसके उत्पादन में बहुत पैसा लगता है। ये items इस बार खेत में ही सड़ गए। अगर वे उनको बाजार में लाए भी हैं, तो वे उनका किराया तक नहीं चुका पाए। उनकी ऐसी हालत हुई है। बाकी और रोजगार कितने गए हैं, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो भारतीय मजदूर संघ है, उसने कहा है कि करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया है। उसके बाबत इस अभिभाषण में कोई ज़िक्र नहीं है।

सर, कश्मीर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में कभी हालत इतनी नहीं बिगड़ी, जितनी आज है। अभी ऐसा मौसम है, जिसकी वजह से वहाँ लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस मौसम के खत्म होने के बाद जैसे ही बर्फ पिघलेगी, बर्फबारी जाएगी, यह सीज़न जाएगा, उसके बाद कश्मीर के हालात बहुत बिगड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि अभी मौका है, आप इस सवाल को हाथ में लीजिए। आपने जो agenda for alliance रखा है, उसमें आपने सब तरह के लोगों से बात करने

की बात कही थी। वहाँ 70 लोगों की जानें पैलेट गन और गोलियों से चली गईं। हमारे सिक्योरिटी फोर्स के लोगों की जानें चली गईं। वहाँ हालात बहुत तनावपूर्ण हैं।

(2ओ/एससीएच पर जारी)

SCH-USY/3.00/2O

श्री शरद यादव (क्रमागत) : आपका जो नेशनल एजेंडा है, उसमें आपने जम्मू-कश्मीर का जिक्र किया है। आप ताज्जुब करेंगे कि वहां एनएचपीसी का जो प्लांट है, उससे जो आमदनी होती है, वह हिन्दुस्तान के बाकी प्लांट्स की कुल आमदनी की आधी होती है। वहां लगभग आठ या नौ प्लांट लगे हुए हैं। आपने अपने Agenda for Alliance में कहा था कि जहां एनएचपीसी के प्लांट्स हैं, वहां आप पानी रोक नहीं सकते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। आप सिर्फ बहते हुए पानी से ही लाभ ले सकते हैं और उस बहते हुए पानी से वहां पर हमने आठ-नौ प्लांट बनाकर रख दिए हैं। हिन्दुस्तान में एनएचपीसी से होने वाले कुल लाभ का आधा अकेले जम्मू-कश्मीर से होता है। आपने अपने Agenda for Alliance में यह लिखा हुआ है। वहां की सरकार, वहां के सब लोग लगातार आपसे इसके लिए मांग करते आए हैं, अब तो वहां आपकी सरकार है, लेकिन पहले भी हर सरकार यह मांग करती आई है। वहां की जो माली हालत है, उसको ठीक करने के लिए आप दो या तीन प्लांट दीजिए, आप इसकी शुरुआत तो करिए। वहां की जो जनता है, वह कई तरह के नारे लगा रही है, यह देश के लिए चिंता का सवाल है। दुलहस्ती पॉवर प्लांट है, बुरसर है, सलाल है, उरी है, ऐसे बहुत से पॉवर प्लांट हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन....(व्यवधान)... तो ये कश्मीर का जो मामला है,

उसको कहीं न कहीं हम सभी को महसूस करना चाहिए। अभी वहां यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में बहुत से लोग गए थे। वे सरकार से और हम सभी लोगों से आग्रह करके कह रहे हैं कि यही वक्त है कि बातचीत करके हमें उनकी समस्याओं का कोई रास्ता निकालना चाहिए। देश को बनाने के लिए, देश को ठीक रखने के लिए आपको हर तरह के लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए।

कितनी ही तरह की समस्याएं हमारे सामने आई हैं। चाहे किसी सरकार के समय में ये समस्याएं रही हों, सभी सरकारों ने इन समस्याओं का समाधान करने का काम किया है, लेकिन सिर्फ इस बार कश्मीर के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। आपने जो सारे का सारा अलायंस किया, इस अलायंस के सामने जितने भी सवाल रखे गए हैं, एक बात पर भी आपने कदम उठाने का काम नहीं किया है। आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि यही वक्त है, जब सरकार इस दिशा में पहल करे।

आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस दौर में बॉर्डर पर जितना तनाव रहा है और जितने लोग हलाक़ हुए हैं, उतने पहले कभी किसी दौर में नहीं हुए। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सारी समस्याएं कश्मीर में के हैं। इसलिए कश्मीर की समस्या का समाधान करने के लिए हमें चाहे किसी से भी, किसी भी सीमा जाकर बात क्यों न करनी पड़े, हमें करनी चाहिए। पहले भी हम यह करते आए हैं। यह विकट समस्या है और इसको ठीक करने का हमारे पास यही मौका है।

उपसभाध्यक्ष जी, इस पूरे के पूरे अभिभाषण में बताया गया है कि इस देश में 10 करोड़ आदिवासी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश में हर तरह के लोग हैं, किसान हैं, दलित हैं, मजदूर हैं, ट्रेडर्स हैं। इन सबकी अपनी एक आवाज है। अगर कहीं किसी एक तबके की आवाज नहीं है, तो केवल ट्राइबल तबके के लोगों की नहीं है, क्योंकि ट्राइबल्स अकेले हैं, जंगलों में जाकर बस गए हैं, बेज़ुबान हैं। मैं आपसे कहूंगा कि 10 करोड़ में कोई एक आदमी है, जो आगे बढ़ा है, अन्यथा जिन हालात में वे लोग हैं, उसका बयान करना भी कठिन है। इनकी कोई आवाज़ नहीं है, कोई सामूहिक ताकत नहीं है, क्योंकि ये इकट्ठे नहीं हैं। ओडिशा का आदिवासी अलग नाम से जाना जाता है, गुजरात के आदिवासी का अलग नाम है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी का नाम अलग है, इसी तरह मध्य प्रदेश में अलग तरह के आदिवासी बसे हुए हैं। आज़ादी के बाद से हमने इनके लिए शैड्यूल्ड-V और शैड्यूल्ड-VI बना कर रखे हैं, लेकिन आज तक उनको ठीक से लागू नहीं किया गया। 1996 में हमने एक नया कानून बनाया था कि पंचायत के माध्यम से इनको पूरे अधिकार देंगे। याद रखिए, अगर हिन्दुस्तान की संपदा और संपत्ति सबसे ज्यादा कहीं पर संचित है, तो वहां संचित है, जहां हिन्दुस्तान के आदिवासी बसे हुए हैं। ये आदिवासी सतपुड़ा और विंध्याचल की रेंज में बसे हुए हैं। वहां पर सरकार ने उनका एक छोटा सा टाउन बना दिया है, लेकिन केवल इससे उन्हें राहत मिलने वाली नहीं है।

(2p/RPM पर जारी)

RPM-USY/2P/3.05

श्री शरद यादव (क्रमागत): इन आदिवासियों के प्रोटेक्शन के लिए राष्ट्रपति और गवर्नर को अधिकार दिए हुए हैं। मैं राष्ट्रपति जी से आदिवासियों को लेकर मिला और गुजरात के गवर्नर से मिला। गुजरात के गवर्नर से कई बार आदिवासी मिले। यहां हमारे भाई बैठे हुए हैं, जो उसी इलाके से हैं, जहां भील लोग रहते हैं। वे कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। कई दिनों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके जो हक और हकूक हैं, वे उन्हें नहीं मिल रहे हैं। उनकी पंचायत और उनकी काउंसिल को अधिकार था कि कोई भी आदमी बाहर से नहीं आ सकता है। उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता है और कोई भी काम, किसी भी प्रकार का खनन उनकी अनुमति के बिना नहीं हो सकता, लेकिन उनकी अनुमति के बिना सब काम जारी हैं। उन्हें भारत सरकार से जो भी पैसा मिलता है, वह उन तक नहीं पहुंचता है।

महोदय, यह हालत केवल गुजरात में ही नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में भी यही हालत है। देश की सरकार, यानी भारत सरकार, हिन्दुस्तान के 10 करोड़ आदिवासियों के बारे में और राज्यों की सरकारें भी उनके बारे में ध्यान नहीं देंगी, तो हिन्दुस्तान का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें इतने सीधे, इतने बेज़ुबान और जंगल में बसे लोग हैं, उनका कल्याण नहीं हो सकता। वे जंगल में बसे हैं। वहीं सबसे ज्यादा सम्पत्ति है। वहीं सबसे ज्यादा खनिज हैं। इसलिए सबसे ज्यादा तबाही और बरबादी उन्हीं की हो रही है। उनके लिए संविधान में जो कानूनी प्रोटेक्शन दिया

गया है, वह उन्हें नहीं मिल रहा है। मैं इस बारे में राष्ट्रपति जी से मिला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह उनका अभिभाषण है, इसमें भी उन आदिवासियों के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस अभिभाषण में शेड्यूल 5 और 6 के बारे में कोई चर्चा नहीं है। यह उनके ऊपर कहीं भी लागू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह देश मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि हिन्दुस्तान का इतना बड़ा तबका आज पूरी तरह से अपने अधिकारों से वंचित है।

महोदय, झारखंड में एक कानून बना और इस बारे में छोटा नागपुर में भी काफी आन्दोलन हुए हैं। वहां जो कानून बना, उसके जरिए वहां के जो आदिवासी हैं, उनकी खेती और जमीन को हड़पने का खेल खेला जा रहा है। मेरे साथी ने मुझे याद दिलाया कि वह आन्दोलन इतना बड़ा हो गया है कि सारी पार्टियां उसमें लगी हुई हैं, लेकिन सरकार बिलकुल अड़ी हुई है कि नहीं, हम तो यह काम करेंगे। आज देश में आदिवासियों के इस तरह के हालात हैं और इस तरह की खराब स्थिति है।

महोदय, हमारे देश की सबसे बड़ी और गम्भीर समस्या सामाजिक विषमता की है। इस समस्या का समाधान तो हमें ही करना पड़ेगा। जो सोशल डिस्पैरिटी है, उसके चलते ही यह इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जो सामाजिक विषमता है, वही सब चीज की जड़ है। जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, उसके बाबत तो 'स्टैंड अप' है, 'स्टार्टअप' है, 'मुद्रा' है, 'मेक इन इंडिया' है, 'स्वच्छ भारत' है। इसके लिए तो अनेक काम चल रहे हैं। ये काम केवल यही सरकार नहीं कर रही है, बल्कि इससे पिछली सरकारों ने भी कई बार किए हैं। सब ने किया है , लेकिन भारत

सरकार द्वारा दी गई सहायता उन तक पहुंचती ही नहीं है। उन्हें दिया गया धन पर्कुलेट ही नहीं होता है। इसलिए कि पूरे के पूरे देश की न्याय व्यवस्था में उन आदिवासियों का कोई हिस्सा नहीं है।

महोदय, श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय विधि और न्याय मंत्री ने जो कानून बनाए, वे नहीं चल पाए। कोलीजियम चल रहा है। मेरा तो यह मानना है कि चाहे आपका सिस्टम है या उनका सिस्टम है, उसमें गरीब की कोई जगह नहीं है। उसे कैसे न्याय मिले? जो सारे देश के न्यायालय हैं, चाहे वे हाई कोट्र्स हैं और चाहे वह सुप्रीम कोर्ट है, वहां उनकी कोई जगह नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार बताने का काम करे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोट्र्स में कितने-कितने लोग, वीकर सैक्शन, खासकर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ट कास्ट्स के हैं? आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि हिन्दुस्तान के संविधान में देश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ऊपर उठाने के लिए जो अवसर मिला यानी नौकरियों में जो आरक्षण मिला, वह देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोट्र्स में जितने भी कर्मचारी हैं, उनमें अभी तक लागू नहीं हुआ है। किसी भी कैटेगरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। एक में भी आरक्षण नहीं है। जो लोग सदियों से दबे-कुचले और पिछड़े हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोट्र्स, जो देश के लोगों को न्याय देते हैं, वह न्याय की संस्था अपने संविधान के साथ अन्याय करती है।

(2Q/पीएसवी पर जारी)

PSV-PK/2Q/3.10

श्री शरद यादव (क्रमागत): इस सदन में एक बार नहीं, कई बार यहाँ के लोगों ने इस सवाल को उठाने का काम किया है। एक दिन भी सरकार इसकी तरफ सचेत नहीं होती। वह सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं कहती? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संविधान के दायरे के बाहर नहीं हैं। क्यों उन्होंने हर जगह रिजर्वेशन नहीं रखा है? जब वे वहाँ रिजर्वेशन नहीं देते, इसलिए रिजर्वेशन के खिलाफ कई बार-- हिन्दुस्तान की समाज-व्यवस्था के बारे में कुछ लोग तो जानते ही नहीं हैं और कुछ लोग अपने जन्म के साथ जुड़े रहते हैं। ये जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, ये हिन्दुस्तान की एक-चौथाई आबादी हैं। इस एक-चौथाई आबादी के बारे में, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वे अपने नीचे अपने यहाँ जो भर्ती करते हैं, उसमें न्याय नहीं करते हैं। तो वे इसका जो भी सवाल जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में दलितों के और आदिवासियों के हक़ मिलें, उनको गिराने का, उनको हमेशा खत्म करने का निरन्तर प्रयास करते हैं। क्रीमी लेयर संविधान के अन्दर कैसे आएगी? यह सदन उसको कभी नहीं हटाता है। यदि उन्होंने क्रीमी लेयर लगा दी है, तो हम लोग क्यों नहीं बढ़ाते हैं? यानी क्रीमी लेयर के जो लोग हैं, जैसे अभी 50 लड़के पास हो गए, वे कंपीट कर गए हैं, लेकिन बैकलॉग इतना बड़ा है कि इसकी आप कोई इंतिहा नहीं देख सकते। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं सामने रखता। बैकलॉग इतना है कि कई डिपार्टमेंट्स, कई क्षेत्र तो भर्ती ही नहीं करते हैं। बैकलॉग इतना बड़ा है और सरकार यह कह रही है कि हम देश बना रहे हैं! यह जो राष्ट्रभक्ति का गीत है, तो जो इतनी बड़ी आबादी है, जो दो-तिहाई लोग हैं, हिन्दुस्तान

के 80 फीसदी लोग हैं, जोकि किसान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, ये 80 फीसदी हैं, अगर वे बलशाली नहीं होंगे, वे ताकतवर नहीं होंगे, तो यह देश कैसे मज़बूत हो जाएगा, यह कैसे ताकतवर हो जाएगा? क्या उनके बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई चिन्ता है? क्या इसमें बैकलॉग के बारे में कोई बात है? कानून का पालन नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या आपने कोई बात कही है? मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कुछ नौजवान, कुछ लोग इसमें काम करते हैं। आरटीआई का एक एक्टिविस्ट राजनारायण है। वह इसका काम करता है। एम्स में उसको कहा गया है कि वह आ ही नहीं सकता है। उस पर कई तरह के गलत केसेज़ चलाए जा रहे हैं। यानी न्याय के लिए लड़ाई लड़ना भी मुश्किल है, यह हालत है।

मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाने के लिए, इस सदन में सच्चाई को रखने के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की हालत, हाई कोर्ट की हालत मैंने आपको बताई कि हिन्दुस्तान के जो दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, किसी भी वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको न्याय कैसे मिल सकता है, जो अपने यहाँ न्याय नहीं करते हैं? वह न्याय, जो संविधान में दिया हुआ है, उस संविधान के न्याय को जो लोग बराबर काटने-छाँटने का काम करते हैं, उन्होंने संविधान के विपरीत यह क्रीमी लेयर लगायी है। सदन के पास ताकत है, सरकार के पास ताकत है, तो क्यों नहीं इसे बढ़ाते हैं? आज तो चपरासी की भी तनख्वाह बहुत बड़ी है। तो जिसके पास साधन नहीं होगा, यह जज करने का मामला है, सम्मान का मामला है। यह पैसे का मामला नहीं है, एक तरह की जो सामाजिक विषमता है, उसमें जो इज्ज़त और मान-सम्मान का सब तरह से

शोषण हो जाता है, वह उसकी बाबत है। मैं आपको निवेदन करूँगा कि भारत के जो कॉलेजेज़ हैं, उनमें लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो 100 फीसदी लोग हैं, उनमें से सिर्फ एससी के 7 परसेंट लोग हैं और एसटी के 2 परसेंट हैं। वहाँ हज़ारों, लाखों पोस्ट्स हैं। 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वाइस चांसलर्स कितने हैं- शैड्यूल्ड कास्ट्स के ज़ीरो हैं और आदिवासी कितने हैं? अभी अमरकंटक में एक यूनिवर्सिटी बनी, उसमें एक आदमी रखा गया है। तो बताइए कि देश कैसे बनेगा? बताइए कि यह कैसे मज़बूत बनेगा, हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, वह कैसे मज़बूत और मज़बूत होगा? ये कौन हैं, मुट्ठी भर लोग हैं।

(2आर/वीएनके पर जारी)

VNK-PB/2R/3.15

श्री शरद यादव (क्रमागत) : अब ये तंत्र जो चलाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मुणगेकर जी और पी. एल. पुनिया जी ने यहां जो सवाल पूछा है, मैं उनके सवाल का जवाब यहां दे रहा हूँ। उपसभाध्यक्ष जी, मैं कोई दूसरी बात नहीं कह रहा हूँ, इस सरकार का जवाब है, यहां पर जो दलित लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उन्होंने जो सवाल पूछे हैं, उसी पर मैं कहना चाहता हूँ। इस सरकार में जितने सचिव हैं, एससी, एसटी और ओबीसी.... मैं मानता हूँ ओबीसी के लिए प्रमोशन में जो रिजर्वेशन हुआ है, उसमें इतने समय में उतने लोग नहीं आ पाए, जो प्रमोशन वाला है। 70 सेक्रेटरीज़ हैं, उनमें एससी के 3 हैं, एसटी के 3 हैं और मैं आपसे यह कहूं कि जो असली ट्राइबल हैं, वे ये नहीं हैं। ज्यादा लोग नॉर्थ-ईस्ट के और राजस्थान में मीणा लोग हैं, वे इसमें ज्यादा

compete करते हैं। ये जो असली आदिवासी हैं, जो विंध्याचल और सतपुड़ा की रेंज में बसे हुए लोग हैं, उनका एक भी आदमी इसमें कहीं नहीं है। संयुक्त सचिव 278 हैं, इनमें से 24 एससी के हैं, 10 एसटी के हैं और 10 ओबीसी के हैं। मैंने कहा कि सचिव में एक भी ओबीसी का नहीं है। जब से रिजर्वेशन लागू हुआ है, तब से एक भी ओबीसी नहीं है। उसके पहले के जो लोग हैं, वे एक-दो हैं, जो मुझसे मिले भी हैं। अब यह तंत्र है! ऐसे में आप कैसे नोटबंदी को नीचे तक ले जा सकते हैं? यह जो आपका तंत्र है, उस पर मैं आगे आऊंगा।

सरकारी बैंकों में जनरल मैनेजर के 436 पद हैं और उनमें से 5 ओबीसी के हैं, 14 एससी के हैं, 7 एसटी के हैं। 436 में से 26 हैं। हमारे सरकारी बैंकों में यह हालत है। सरकारी बैंकों में कुल 1,216 डिप्टी मैनेजर हैं और उनमें 14 ओबीसी के हैं, एससी के 72 हैं, एसटी तो सबसे नीचे है। मैं आपसे कहूं, मेरी चुनौती है कि सरकार सर्वे करा ले, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो आदिवासी रहते हैं, उनमें से एक भी नहीं है, जो है, वह ओडिशा का है, वह मध्य प्रदेश का है, वह छत्तीसगढ़ का है या गुजरात का है। मैं यह चुनौती देता हूँ कि आप आईएएस में यहां के एसटी के दो या तीन ऑफिसर्स भी बता देंगे, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। इनको नहीं मिलता है, इनकी जगह ट्राइबल्स के नाम पर दूसरे लोगों को मिलता है। इस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सोचने को तैयार नहीं है।

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हम लोग भी इसको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानते हैं। मैं कई बार उसमें गया हूँ। उसमें जो 100 प्रोफेसर्स

हैं, उनमें से एससी के सिर्फ 9 हैं, एसटी का ज़ीरो है और ओबीसी का ज़ीरो है। यह जो 80 फीसदी आबादी है, यह इससे नदारद है। जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, हिन्दुस्तान में लोग जिस यूनिवर्सिटी को बहस के लिए, तमाम चीजों के लिए मोहब्बत करते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सपनों के साथ जिस यूनिवर्सिटी को बनाया था, उसमें यह हालत है।

(2एस/एनकेआर-एसकेसी पर जारी)

NKR-SKC/2S/3.20

श्री शरद यादव (क्रमागत) : यदि दूसरे आंकड़े मैं दूंगा, तो उसमें काफी समय चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की हालत मैंने आपको बताई। देश में जो सोशल डिस्पैरिटी है, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, आप बताइए कि सबसे ज्यादा, सबसे गम्भीर सवाल जो है, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में थोड़ी-थोड़ी करके सब चीजें हैं, जैसे हर साल रहती हैं, वही इस सरकार के समय में हैं, उसमे कोई नई बात नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : शरद जी, संक्षेप में कहिए। समय समाप्त हो रहा है।

श्री शरद यादव : इसमें सबको साथ लिया गया है। रेल बजट है, जनशक्ति है, स्वच्छ भारत मिशन है, एल.पी.जी. के 2.2 करोड़ हैं यानी सब तरह के आर्थिक और इकोनॉमिक मामलों का वर्णन है, लेकिन जो सोशल डिस्पैरिटी, जो सामाजिक विषमता है जो आर्थिक विषमता की महतारी है, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से और पूरे देश से कहना चाहता हूं कि यदि आपने इस समस्या का समाधान नहीं निकाला तो हिन्दुस्तान

मजबूत नहीं हो सकता और आज नहीं तो कल यहां बगावत होगी। ये भी इंसानों की संतानें हैं, आज दुनिया बदली है, ये ऐसे ही नहीं खड़े रहेंगे, ऐसे ही नहीं देखते रहेंगे। उस सदन में तो संख्या ज्यादा है और एक तरह से उसमें संतुलन भी है लेकिन यहां रिजर्वेशन नहीं है। यहां संतुलन नहीं है।

मैं, अंत में, इस सदन में यही कहूंगा कि जब संविधान सभा का समापन हो गया और बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण हुआ, उस दिन उन्होंने जो चेतावनी दी थी, जो मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के आखिरी भाषण में कहा था कि देश को सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी से लड़ाई लड़नी होगी। एक-तरफा आर्थिक मामले में तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन सामाजिक मामले में बिल्कुल हम सोचते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं और न हमारा हृदय बोलता है। जो हमारा पूरा तंत्र है, संसद भवन की इमारत इस बात की गवाह है, उन्होंने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी के रहते भारत एक राष्ट्र नहीं बन पाएगा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर गैर-बराबरी खत्म नहीं की गई तो व्यवस्था से नाराज लोग पूरे संवैधानिक ढांचे को चरमरा देंगे, गिरा देंगे।

अंत में..(व्यवधान).. मैं समझ गया और बैठना चाहता हूं और अंत में यही कहूंगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो सारी चीजें हैं, विशेषकर नोटबंदी के मामले में पूरे सदन में हर मैम्बर ने जो बोला, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि नोटबंदी के चलते पूरे देश में जितनी तरह के दलाल पैदा हुए, वैसे हालात कभी पहले इस देश में नहीं हुए। पहले दिन से लोग हजार रुपए के 800 रुपए ले लो, फिर आया कि हजार

रुपए के 900 रुपए ले लो, यहां से वहां तक आपका जो तंत्र है, वह तंत्र न्यायसंगत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस तंत्र में सब तरह के लोग हैं। भारतीय समाज के हर हिस्से के लोग होते तो आपकी नोटबंदी के माध्यम से आप जैसा चाहते थे, जो करना चाहते थे, उसका कुछ परिणाम निकलता। लेकिन उसमें इसलिए कुछ नहीं निकला क्योंकि आपका जो तंत्र है, वह किसी भी चीज के लिए तैयार ही नहीं था। जितनी तरह के प्रोग्राम आपने दिए, वे सभी इसीलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि आपका तंत्र नीचे तक बेईमान है। इंदिरा आवास से लेकर हर तरह की जितनी भी सुविधाएं आप देते हैं, कोई न कोई रास्ता वह निकाल लेता है। जिन लोगों से आपका तंत्र बना हुआ है, उनका मन उन्हें वहीं बनाए रखने के लिए, हिन्दुस्तान की बड़ी आबादी को दबाए रखने के लिए, शोषित रखने के लिए, उनकी इज्ज़त, मान-सम्मान, सम्पत्ति, सम्पदा सब चीजों का शोषण करके, उन्हें फिर से वहीं का वहीं रखने के लिए काम करता रहता है।

2T/DS/पर जारी

KSK/DS/3.25/2T

श्री शरद यादव (क्रमागत) : इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरी यह विनती है कि यह अभिभाषण अधूरा है, यह अभिभाषण पूरी तरह से अधूरा है, हिन्दुस्तान को बनाने वाला नहीं है। अगर हिन्दुस्तान को बनाना है, तो हिन्दुस्तान की जो 80 फीसदी आबादी है, जिसको संविधान ने थोड़ा-बहुत जो हिस्सा दिया है, उस हिस्से पर हर अभिभाषण में हमें पूरा ध्यान देना होगा। यह पहली बात हुई।

दूसरी बात यह कि पूरे देश में जो लूट है, अगर उसको रोकना है, तो इसके लिए सबको हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

(समाप्त)

श्री सीताराम येचुरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष जी, चूँकि अभी शरद यादव जी हिन्दी में बोले, इसलिए मैं अंग्रेज़ी में बोल लेता हूँ।

Sir, all of us know that the hon. President delivers an Address conventionally to the Parliament every year, which is a script that is approved by the Cabinet, and he just reads out that script. Normally, the hon. President is very fond of using four 'Ds' to describe the Parliamentary democracy in our country. He often says that there should be debate, discussion and then a decision, and not disruption. That is his very fond philosophy. Four 'Ds' is what he uses. But, unfortunately, the irony is that he read out a speech in which there are also four 'Ds', but these are not the 'Ds' that he is fond of, and these four 'Ds' are - * which are leading up to a * being unfolded. So, I would like to dwell on these four 'Ds' that are contained in this rather long

---

***Expunged as ordered by the Chair.**

80-paragraph Address that the hon. President has delivered. But before I come to the content of this hon. President's Speech, Sir, let me refer to the fact there have been two references that are made to very eminent and very influential personalities of Indian culture and history. One is to the saint-philosopher, Ramanujacharya. The reason I think I should just refer to this is the fact that Ramanujacharya is one of those personalities whose philosophy laid the foundations for the Bhakti Movement in our country, a philosophy where he replaced the devotion to rituals as a devotion to God for the realization of spiritual fulfillment. And, what does he say? He says, "Discursive thought is necessary in humanity search." Please note, "Discursive thought is necessary in humanity search for ultimate verities." Now, he shows his God as Vishnu and the King of the Chola Empire then was a King called Kulottunga. He banished Ramanujacharya because Kulottunga was the King and the official religion was Shaivism, while he chose Vishnu and, therefore, Vaishnavism. Sir, banishing that thing is an important point which must be noted in the background of his own philosophy that because of a certain belief of yours, you are banished from that Kingdom. What we are seeing today in our country is precisely that - if you do not believe in my God, then you are not part of India. And, if that is

the sort of an invocation that you are doing, Ramanujacharya is not the person whom the President of India had to refer to; it should have been Kulottunga because that is exactly the atmosphere that is being built up in our country today. That is the first point of first 'D' that I was talking of deception. The second…(Interruptions)…

SHRI JAIRAM RAMESH: The CPM leader…(Interruptions)…

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, Mr. Jairam Ramesh is always over-awed and disappointed with CPM leaders' invokes, but remember, a CPM leader is a Communist who believes that all that we have today is the product of human labour. (Contd. by 2U - GSP)

GSP-MCM/3.30/2U

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD.): And that human labour is my labour, and, that is why, I am a Communist. All this is my heritage, Sir. So, I also have the right to invoke this.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Jai 'ram' and Sita 'ram' !

SHRI SITARAM YECHURY: That is again an irony. …(Interruptions)… Hon. Minister, Ravi Shankar ji, has actually pointed out a very correct fact that all

the 'rams' are here in the Opposition, no one is there. …(Interruptions)… There is not one 'ram'.

SHRI JAIRAM RAMESH: There is one ram, 'Ramlala'. …(Interruptions)…

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): One 'ram' is coming. …(Interruptions)… One 'ram' is coming.

SHRI SITARAM YECHURY: I come to my second point which is about Guru Gobind Singh. Sir, Guru Gobind Singh is one of the most venerable leaders of the Sikh religion, the Sikh panth of India for what he contributed. All of us know this. Remember, Sir, he was the one who founded the *khalsa panth* at Anandpur Sahib. He founded the *khalsa vani*, and, the slogan that he gave is, "Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh."

On the basis of that slogan of the *khalsa panth*, he finalized the Guru Granth Sahib and said that is the eternal guru, with no more guru to come. The whole thing that he established was based on five Ks. What are these five Ks? These are, Kesh, Kara, Kangha, Kechera and Kirpan.

All of us know this history, and, if some do not know it, I would only beseech them to try and understand this history because it is a very important development in Indian philosophy and history. As far as the 'kirpan' is concerned, he was asked as to why he was giving the kirpan.

What was his answer, Sir? He said, and, I am quoting, "To defend himself and the poor, the weak and the oppressed from all religions, castes and creeds." To defend the *khalsa panth*, to defend the humanity from all forms of religious oppression, all forms of caste oppression, all forms of oppression that we find in this country, the kirpan is one of the necessities of a *khalsa*.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

Now, today, what do we have in our country? Again, therefore, I say, it is an irony why Guru Gobind Singh has been invoked. While the *kirpan* was meant to defend the poor and the oppressed from religious persecution, to defend the poor and the oppressed from caste persecution, instead, Sir, in the line up to the Uttar Pradesh Assembly elections, we heard a new announcement now that they will have these Anti-Romeo Squads. I will come to that point later. Instead of protecting the oppressed, this is being talked about. I will come to the point of these squads later. You just heard my senior friend, Sharad Yadav, speaking about what has been happening to the *dalits*, tribals and to the *OBCs*. Instead of protecting the oppressed, what we have, on the contrary, is that during the course of last year, the President dwelt it in his balance sheet of his Government's

work, there have been greater atrocities only. It is not protection. It has been greater atrocities with official patronage, which is happening in our country. That is why, once again, invoking Guru Gobind Singh is very, very ominous and does not completely match with what has been the experience of the country in the last one year. That is why, Sir, I say that these two invocations are not merely ironic but are part of the philosophy of deception that this Government has been practicing.

Now, I come to the second 'D' that I was talking about, which is disruption. What we have seen in the course of one year, not only with this demonetization which, of course, is the biggest disruption that has happened to our country, to our life, to our economy. It has actually disrupted the normal existence of a vast majority of our people and their day-to-day livelihood. We have been through this debate earlier, Sir. Today, with all the points that were made earlier in the debate, what I myself had made here, I can only say that none of the four points that the hon. Prime Minister cited as reasons for this demonetization were achievable then, and, now, practically, we see that they have not been achieved, and, on the contrary, many things have actually been endorsed and legalized.

(Contd. by SK-2W)

SK-SC/2W/3.35

SHRI SITARAM YECHURY (contd.): Why do I say this? There is more money than what was demonetized that is coming into your banks today. What does that mean? It means that all the black money that was held as stock in the country has now been converted into white. All the illicit, counterfeit money that you have in our country has been legalized. Now, what was the objective? You said that will reduce terrorism, terrorist funding. After your surgical strike, the number of our *jawans*, who are sacrificing their lives to defend us, while we are proud of them and we salute them, the number of them who lost their lives in terrorist attacks has doubled in these three months compared to earlier three months. And about corruption, we have just heard Mr. Sharad Yadav telling us about the levels of corruption. Now the common denominator for corruption transactions has been increased from one thousand rupees to two thousand rupees. So, the rate has only doubled. ..(Interruptions).. Like he says, there have been so many intermediaries. None of these have got finished, but in the process, there is agony of the people. There is not a mention of more than a hundred people who died wanting to withdraw their own money. The Constitution of India, Sir, today gives the right to property. The

money in the banks is individual's property. That right has been violated by this, and those who wanted to exercise that right have lost their lives, but there is not one mention about that. Outside, there are references saying when a big *yagya* takes place, "जब एक बड़ा यज्ञ होता है तो आहुति होती है।" You sacrifice for the sake of a big *yagya*. So, these innocent peoples' deaths are brushed aside as sacrifice of people for something big that is being achieved, and what is that that you have achieved, Sir? When I say 'disruption', it is actually leading up to destruction, if you are not taking up some concrete, countervailing action now. Forty-five per cent of our GDP is contributed by what is called the informal economy. Nearly eighty per cent of our employment is generated in that informal economy, and that informal economy is almost hundred per cent on the basis of cash transactions. All that has been disrupted. Crores of Indian people have been put to unnecessary suffering as a result of this. And we have seen the assessments that were made. We ourselves have said how the international agencies have said the impact of that will be on our GDP. Our former Prime Minister, former Finance Minister and former Governor of the Reserve Bank -- I think there is only one individual in the whole of India who has served in those three capacities -- has said, with all that wisdom, that it will fall the

GDP at least two percentage points. Forget the veracity of what you want to do, the fact is that there is an economic slowdown. Even the Government's own Economic Survey recognises that. In formal sector, your retail trade has fallen in the first two months. As much as 75 per cent is the fall of your retail trade. I have personally witnessed, we all witnessed in Delhi, farmers coming from nearby with onions in their tractors and trailers and selling them at ten rupees a kilo, and some of them dumping. In Raipur, I was there for a meeting, and we had the farmers coming and distributing tomatoes free. I had to ask one of them, "Why are you distributing it free?" He said, "If I want to destroy it, I will spend more money. So, it is better that I go and give it free." The farmers, where the harvesting has been done, are selling their harvest, their crop, for one half of the Minimum Support Price. Nobody is there to procure it because there is no cash to give to the farmers. So, the farmers are selling their produce at one half of the Minimum Support Price. This is the case with the fishermen too. You come from a State, Sir, where a substantial contribution to the economy is made by the fishermen. Now, without cash transactions, you know what happens to the fish they

catch. Their family can't survive the day. The fish will rot, and the entire consequential multiplier effects will take place in the economy.

(Contd. by YSR/2X)

-SK/YSR-GS/3.40/2X

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD.): I am only giving you some of the examples. This is happening to your informal sector. In agriculture, there is reverse migration of agricultural labour from Punjab and Haryana in the peak season, because they can't employ them.

Then what is happening to manufacturing in industries? Every sector in the manufacturing industry has shown a drop in sales and production. In the case of two-wheelers, it is dropped by thirty-five per cent in these three months of demonetisation. The Prime Minister's constituency is famous for *Banarasi sarees*. They are being sold at half the price today because people are not coming to place the contract for those *sarees*. And I will tell you what is worse, Sir. The Prime Minister either yesterday or day before yesterday was in Meerut. He was talking about sports material being produced in Meerut. He said, "With your sports material, our country gets laurels in all the international sports events." And what is the report from there, Sir? Twenty per cent business is down in the sports goods industry.

Half the workers have been laid off. I can go on mentioning it. I have got a list of all the sectors that are there in the country which are badly affected. And what is the net result of this? A massive surge in unemployment. Last year, it was admitted here in an answer to a parliamentary question that the eight core industries in 2015 generated only 1.35 lakh crore jobs. Now the Labour Bureau tells us that there are 55,000 jobs in these eight core industries. Leave alone the informal economy; this is the formal organised economy. This is what is happening. And it is on the basis of this that the Economic Survey had said that in order to get out of this impact of demonetisation what is required is to vastly expand our domestic demand. It means you have to vastly expand the purchasing power of our people. It means you have to vastly expand public investment. This is the recommendation of the Economic Survey. And what does the Budget do? Instead of expansion, it contracts the Indian economy. Just look at these telling figures. The size of the Budget is a contraction from last year's Budget – from 13.4 per cent of our GDP to 12.7 per cent. The Budget itself is contracted as a proportion of the GDP. Then what is the capital expenditure? It has come down from 1.86 per cent of the GDP to 1.84 per cent this year. I am giving you the figure in terms of percentage of GDP,

because that is not merely informative but more accurate in order to understand it. Then an announcement was made that you are giving so much of allocation to various projects. MGNREGA was one of the projects. You have said that it is the highest ever allocated by any Government for MGNREGA! You announced that its allocation is Rs.48,000 crore. It is Rs.600 crore more than what was spent last year which is Rs.47,400 crore. So, what is this great boost that you are talking about for giving employment? Even allocation for agriculture as a percentage of GDP has come down from 1.98 per cent to 1.95 per cent. Remember, Sir, one percentage point of GDP is about one and a half lakh crore of rupees. Am I right? I am taking Mr. Chidambaram's approval because he is an authority on this. So, a reduction of three points in the GDP means a huge amount of money. This is what is happening with the economy. On the other hand, what have you done? The Economic Survey says, "Expand the purchasing power and domestic demand." You have decreased your revenue from direct taxes by Rs.20,000 crore which means relief to the rich. You have increased your indirect tax collection by Rs.75,000 crore which is a greater burden on the consumer, the common man.

(Contd. by VKK/2Y)

-YSR/VKK/2Y/3.45

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD.): So, instead of having a greater disposable income to buy something so that our demand can expand, this whole Budget is contracting your domestic demand further, which means keeping greater miseries on top of demonetisation that you have brought about. So, this is where the disruption of the economic story of India is actually happening. And if this is happening, there is one element of this, which Mr. Sharad Yadav has spoken out in detail and I am not repeating it. But, I must refer to it because this is really telling. The other day the hon. Prime Minister spoke that his and his party's fight in Uttar Pradesh is against what he calls SCAM. He was referring to political parties. It is SCAM. But, what he is doing to the country is actually fighting against a SCAM in which S, C, A and M mean different things. SC stands for scheduled categories and M for minorities. This is a battle that the Prime Minister and this Government is conducting against SCAM. This is against SC, ST and minorities. Look at the Budgetary allocations. 1.48 per cent of the Budget, not of the GDP, has been allocated for SC programmes. It is 1.48 per cent. Then, 2.44 per cent is what has been allocated for ST development. For minority welfare, there is only a mention of various things but there is no

substantial increase in terms of the recommendations of Sachar Committee, Ranganath Mishra Committee, etc. None of them is going to see the light of the day.

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): It is Rs.400 crore. …(Interruptions)…

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I am sorry. The hon. Minister intervened. So, I yielded for that. Naqvi Saheb, I also understand your emotional sentiments concerning this issue. But, what has been allocated is no way near to what is required to implement the recommendations. Sir, for women, what is the allocation? All these are Budget figures. For women, it is only 5.3 per cent. Fifty per cent of our population is women. So, what are we doing? It is a demographic dividend which should be an asset for our country. Already, two-thirds of our country is below the age of 40. Till 2020, this will increase further. Instead of converting that into an asset by providing them with education, jobs and health, we are converting them into a liability that will be a millstone on the whole country and it is something that is completely unacceptable. And that is exactly what these policies are leading up to. Then, you take a moral posture of electoral funding. It says, "reduced

from Rs.20,000 to Rs.2,000". So, I will give you ten more names for the same amount of Rs.20,000. That's all you want. Whom are we fooling, Sir? …(Interruptions)… Sir, please tell me that. Let the Prime Minister and the BJP President explain that in one rally, where they claim ten lakh people came. Officially, the party claims that they hired ten thousand buses apart from helicopters and various other things. Where did the money come from? You don't know; I don't know because there is no ceiling on the expenditure of political parties. You have ceiling on expenditure of candidates. But, political parties can spend as much as they can and finally, you give an account. You file a return saying that this is the thing. That's it. So, if you really want to curb political corruption, then, bring the expenditure of political parties under a ceiling. Why are you not? Why are you resisting that? If you really want to curb political corruption, ban corporate funding to political parties directly. Let the corporates fund and they should fund. If necessary, bring forward a law. Like CSR, bring forward a law for a fund for democracy. Let them fund and let that fund be administered by the Election Commission or the Government and put it in place for State funding of elections. We have discussed that a number of times in our electoral reform agenda. Right from Indrajit Gupta Committee Report downwards, we have

been discussing this. Many countries in the world practise State funding. So, do that. Unless you take such measures, there is no way you can stop the influence of money power and you are only paying lip service and moralistic rituals. All this is meaningless.

(Contd. by BHS/2Z)

-VKK/BHS-ASC/2Z/3.50

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD.): Therefore, this is, eventually, leading up to a situation where this disserving of our economy is only going to make matters worse regarding one aspect, that is, widening inequalities. In 2004, when this Government assumed office, 1 per cent of Indian people held 49 per cent of our GDP. One per cent! Today, that 1 per cent, in 2016, holds 58.4 per cent of our GDP. That is merely a 10 per cent jump in the incomes and wealth of the rich, and the immiserization and wreckage of the lives of the poor! That is what this trajectory is and that is why I say that this is a major disruption that has been caused in our country by them. But why this demonetization now if all the objectives have failed? It is very clear now, shift to a digital economy, where every digital transaction carries a cost. That cost is a bonanza for profit maximization of your foreign capital and also your Indian capital. A one hundred rupee note, if it travels a lakh

transactions, the value of that hundred rupee note will still remain hundred rupees. But if these lakh transactions are done through digital medium with a 2 per cent charge for every transaction or even a 1 per cent charge for every transaction -- it is now 2.5, I think -- so if you take 2.5 per cent for every transaction, a one hundred rupee note transacting one lakh times would mean a profit of 2.5 lakh rupees. Value remains the same 'hundred rupees'. So, what are you doing? Giving the bonanza of profit maximization for these companies, a bulk of which are foreign companies. Internationally, today, there are three major companies -- there may be some others -- who handle your credit card and debit card, that is, Visa, MasterCard and American Express. If these are the ones who are going to be benefitted out of this, what is the meaning of this? This, Sir, ties in with the reduction of India as a strategic ally, a subordinate strategic ally, of the United States of America. This is happening when Mr. Trump has become the President. The present Government seems to be very happy. I mean, it's fine, we wish. Anybody who wins an election, we wish them. That is the normal practice. But wishing them should not translate into being ecstatic about saying that, I mean, eagerly waiting when we will be invited to visit there. And what is he doing with our Indians, Sir? There are five lakh Indian

students. Youth, not students, youth working, mainly, in IT sector who are there on H1B visas and whose existence there has become completely tenuous, a complete state of uncertainty. There is not one word from the Government saying that we will protect their interests. Our Indian-born people there are being harassed and you see reports everyday somebody being picked up and taken up for questioning. It is apart from everything else that is happening in the United States of America. Now, if that is happening to us Indians, your status of a subordinate ally of that USA -- joined naval exercises in South China Sea along with USA and Japan -- what is the signal you are giving to the world? That you are today a junior partner of USA in terms of containment and in terms of their hegemony over the Asia-Pacific Region. Is that in our country's interest? Now, these are issues that are coming up and if this is actually happening in order to save our banks, the banks have become vulnerable because of loot that has happened through the NPAs. If you add the interest today, the existing NPAs amount to Rs. 11 lakh crores. Rs. 11 lakh crores! What have we done through demonetization? You have withdrawn about Rs.15 lakh crores of rupees and you have injected around Rs.5 lakh crores of new notes.

(Contd. by DC/3A)

-BHS/DC-LP/3.55/3A

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD.): So what have you done? You have given ten lakh crores of rupees to the banks as their cash surpluses. The banks that were collapsing because of these NPAs, through demonetization, they are now standing on their feet. Then what did you do? Those, who looted the banks, are going away scot free. We have been asking since time immemorial. If, say, small farmers do not pay back their loans, you get after them. If they don't return the loan, you confiscate their cattle; you confiscate their properties, their land. But when the big fish don't return the money, there is no way of confiscating their properties. Now, they have said, "If they go abroad, we will do something." So, now you are giving them an incentive. "You please go abroad, and then we will see as to what can be done." …(Interruptions)… Sir, please bear with me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Try to conclude also.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, in the last Session, it was announced that Rs. 1.12 lakh crore of NPAs have been waived off. The former Finance Minister is here. Rs. 78,000 crores is what he waived for the farmers then, about ten years ago. Your farmers' rate of suicide has gone up by 26 per cent. By demonetization, they are, today, totally burdened with this debt of

theirs. Waive those loans for the welfare and prosperity of India rather than the loans of the rich, who have but they don't pay back the banks, which is your money, my money. What is happening today in India, Sir? Is it not that when the banks are collapsing, there is a bailout package that is announced by the USA and all other Western countries? In India, today, what you are doing is a bail in package. You are making common people not to withdraw their own money from the banks and, thereby, bailout the banks and, thereby, even exonerate those who have looted the banks. That is why, Sir, this is a very serious matter, and I am very disappointed that the hon. President's speech does not reflect any of this reality. On the contrary, I have gone through this whole thing very meticulously. There are twelve, about one dozen *Pradhan Mantri Yojanas* that have been listed, from last year to this year. Shall I read them out, Sir? It will be an interesting compilation for everybody. These are, *Pradhan Mantri Mudra Yojana*, *Pradhan Mantri Aawas Yojana, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadi Pariyojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana, Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Pradhan Mantri YUVA Yojana, Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana,*

…(Interruptions)…नहीं, नहीं, ग्यारहवीं, *Pradhan Mantri Urja Ganga Yojana,* then the twelfth, *Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana*. इसमें उन्होंने 12 गिनाई हैं। इसके आधार पर वे कह रहे हैं हम देश की बहुत तरक्की कर रहे हैं। हमने इन सब पर अमेंडमेंट्स मूव किए हैं। जो गुजर गए हैं, उनके बारे में जिक्र भी न करना, उनके लिए मुआवजा देना, वह बात छोड़िएगा, लेकिन finally, the last point that I want to come to is, all these three D's i.e., deception, disruption and diversion should not lead up to a fourth 'D', like the hon. President used to remind us that debate, discussion and decision of Parliamentary procedure should not lead to disruption. These three should not lead to the fourth 'D', which is the diabolic agenda that is being unfolded and that is of serious concern for me and I think for you, for the entire august House and for the country also. As I have mentioned earlier, you have now the announcement of anti-romeo squads. You have the cow protection squads, cow protection vigilantism, which has claimed the lives of Dalits in Una; which have claimed the lives of two youths who were hanged to death when they were taking their cattle to a fair in Latehar in Jharkhand; which has claimed the death of Akhlaq, who was lynched in Dadri on the allegation of storing beef.

(Contd. by KR/3B)

KR/KLG/3B/4.00

SHRI SITARAM YECHURY (CONTD.): You have the Rama Sena, another squad, that is, moral policing in the country, and saying how women should behave. In U.P. now you say, we want to protect the women, and, therefore, the anti-Romeo squads. Now, the latest is a very, very film director and producer, Mr. Sanjay Leel Bhansali. He was attacked for so-called distortion of history. Now, who has got the authority over history, we do not know. You had earlier attacks on Aamir Khan and Shah Rukh Khan. You had the intolerance and we saw the killing of Dabholkar, Pansare and Kalburgi. You had this intolerance saying that art can't hurt the religious sentiments of the people. What is the right to information in our Constitution? What is that logic? What is that right there? The right is there only for those people as a work of fiction. Work of fiction can rewrite history, can rewrite mythology. Much of the mythology today that is passed off in history is actually a fiction. Today you say that you can't do that and that intolerance is growing. Actually that is a diabolic project that is actually unfolding today.

Last point, Sir. On diversion, I am suddenly reminded of Mr. Manmohan Desai, a very famous film producer, whose every other film used to be a

silver jubilee hit and a golden jubilee hit. So, he was once asked in final days of his life, and that is why he confessed. He was once asked in one of the old famous magazines, *the Illustrated Weekly* of India, which doesn't exist anymore. In his last interview, he was asked, what was the success of your films? Why is it that every film of yours is a jubilee hit? Then, he said, "The success lies in one fact." The interviewer asked, "What is that?" He said, "Whenever people come to see my films in theatres, from the beginning till the end of the film, the people should not think. If the people think, then, the film is a failure." People should be taken off into a non thinking mode; and that is this Government's practice. One jumla after another, one after another, one after another. Before anybody can forget you have another new one. The point is not let the people think, and, therefore, continue with your diabolic agenda. What is that agenda? Again construction of Ram temple is back on the agenda in U.P., and that agenda is actually the effort to transform the secular, democratic Indian Republic as enshrined in our Constitution into what they call their version of theocratic * Hindu Rashtra which is what the R.S.S. fascistic project is. That diabolic agenda is something that India, as we know of it, can't afford. That is something till the last drop of blood in me and in all of us we will continue to

---

***Expunged as ordered by the Chair.**

defend; and we will continue to defend. Therefore, this * which is the essence of the President's Address should not be allowed to lead to the unfolding of ***** and this is what I beseech this entire august House that before we return the Motion of Thanks that adequate changes be made so that this sentiment is conveyed to the hon. President and that is my final beseeching to the House. Thank you, Sir.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Next, Mr. C.M. Ramesh, not present. Mr. Ram Kumar Kashyap, not present. Shri Dharmapuri Srinivas, not present. Shri Mukhtar Abbas Naqvi. (Followed by 3C/KS)

AKG-KS/3C/4.05

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी) : उपसभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारी पार्टी के लोगों ने इस सम्बन्ध में काफी विस्तार से कहा है। केवल 3-4 विषय ऐसे हैं, जिन्हें मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मैं इस बात से शुरुआत करूँगा कि हम लोग आंदोलन में, क्रांति के समय एक बहुत ही मशहूर गीत गाया करते थे और वह गीत था -

---

***Expunged as ordered by the Chair.**

"हो गई है पीड़ पर्वत-सी पिघलनी चाहिए,

इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,

सारी कोशिश है ये कि सूरत बदलनी चाहिए।"

प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी की सारी की सारी कोशिश यह है कि ढाई-पौने तीन साल पहले जो विरासत मिली, उस विरासत पर बिना सियासत किए हुए हम देश में विकास और विश्वास का माहौल कैसे खड़ा करें, कैसे पैदा करें। पूरा देश जानता है कि जब नरेन्द्र मोदी जी इस देश के प्रधान मंत्री बने और उनको बागडोर मिली, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि करप्शन का पूरा माहौल था, एक लंबी श्रृंखला थी। उसे बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है, पूरे घोटालों का घंटाघर खड़ा था। चारों तरफ घोटाले, चारों तरफ भ्रष्टाचार, चौतरफा, हर तरफ उसकी छाया दिखाई पड़ती थी। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इतनी चुनौती भरी विरासत लेकर कोई सत्ता में आए, तो हम समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पर उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने सबसे पहला काम यह किया कि दिल्ली की सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लॉबी में तालेबंदी की। उपसभापति महोदय, इसका नतीजा यह हुआ कि ढाई-पौने तीन सालों के बाद आज जब हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो हम बहुत गर्व के साथ इस देश को बता रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त व्यवस्था दी है। हमने उन बेईमानों, जिन्होंने इस देश के विकास और इस देश के गरीबों

के विकास में घुन की तरह नुकसान पहुँचाया, उनका खात्मा किया है। यह बात सही है कि यह जो चुनौती थी, यह चुनौती केवल भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नहीं थी। जो गरीब है, जो कमजोर तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो अल्पसंख्यक हैं, जो दलित हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो, उनके विकास में पैसे की कमी कभी नहीं रही है। राज्य सरकारों के पास भी पैसे की कमी कभी नहीं रही है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इतना पैसा खर्च किए जाने के बावजूद जो देश का पिछड़ा तबका है, जो देश का कमजोर तबका है, जो देश का गरीब है, उस तक विकास की रोशनी क्यों नहीं पहुँच पा रही थी। यह बेईमानी का कौन सा बाँध था, जिस बाँध ने विकास की जो अविरल धारा थी, उस अविरल धारा को रोक रखा था? हमने उस बेईमानी के बाँध को ध्वस्त किया और विकास की अविरल धारा उस गरीब, उस आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुँचे, जिसे विकास की जरूरत है, हमने उसके लिए काम किया। प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी का एक ही संकल्प था - विकास और विश्वास। जब हम विकास और विश्वास की बात करते हैं, तो उसमें हम जाति की बात नहीं करते, धर्म की बात नहीं करते, क्षेत्र की बात नहीं करते, बल्कि हम उस व्यक्ति की बात करते हैं, जिस तक विकास की रोशनी नहीं पहुँच पाई है। उपसभापति महोदय, हम गरीब की आँखों में खुशी और उसकी जिन्दगी में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हमने उस संकल्प को काफी हद तक पूरा किया है और आगे आने वाले दिनों में हम उसे और पूरा करेंगे। उपसभापति महोदय, जब हम अपने 5 साल का हिसाब-किताब और लेखा-जोखा देंगे, तो हम आपको एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाएँगे, पूरी दुनिया को

दिखाएँगे, जो तस्वीर एक खुशहाल भारत की होगी, भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्त भारत की होगी और बेईमानों और बेईमानी के बाँध को ध्वस्त करते हुए भारत की होगी।

उपसभापति महोदय, महात्मा गाँधी जी ने एक नारा दिया था, आह्वान किया था। उस समय के बारे में हम लोग किताब में पढ़ते हैं, जिस वक्त अंग्रेजों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। जब महात्मा गाँधी जी ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का आह्वान किया था, तो देश के हजारों-लाखों लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जला दी थी। इससे देश में स्वदेशी का जो संकल्प था, स्वदेशी की जो भावना थी, उसको ताकत मिली थी, बल मिला था। उसके बाद भी हमारे तमाम राष्ट्र नायक हुए हैं, जिन्होंने समय-समय पर जनता का आह्वान किया और लोगों ने उसको नतमस्तक होकर स्वीकार भी किया और उसको लेकर आगे भी बढ़े।

(3डी/एससीएच पर जारी)

SCH-RSS/4.10/3D

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी (क्रमागत) : उपसभापति महोदय, जब श्री नरेन्द्र मोदी जी को प्रधान मंत्री के रूप में सत्ता मिली, तो उन्होंने एक आह्वान किया। उस समय हम लोगों को भी लगता था कि प्रधान मंत्री जी ने यह जो आह्वान किया है, मालूम नहीं लोग उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय राजनीतिक व्यवस्था के प्रति बहुत अधिक विश्वास का माहौल नहीं था। प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया कि जो सम्पन्न लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, उन्हें गैस सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। इसके लिए किसी भी इंस्पेक्टर, दारोगा, पुलिस वाले अथवा प्रशासनिक अधिकारी को नहीं भेजा

गया, केवल एक आह्वान किया गया। मुझे सदन में इस बात को बताते हुए खुशी है कि जब प्रधान मंत्री जी ने यह आह्वान किया, तो करोड़ों लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। गैस सब्सिडी छोड़ने का नतीजा यह हुआ कि जो गरीब लोग थे, कमजोर तबके के लोग थे, जो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके घर भी कभी गैस का चूल्हा आ पाएगा, ऐसे करोड़ों लोगों को free of cost गैस का चूल्हा उपलब्ध करवाया गया। वे माताएं, वे बहनें, जो कभी यह सोचती भी नहीं थीं कि हम भी कभी अपने घरों में गैस का चूल्हा जला पाएंगी, उनको नि:शुल्क ...(व्यवधान)...

श्री सीताराम येचुरी : एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जब मैं बोल रहा था, तब मैंने भी आपके लिए यील्ड किया था। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि आप यह जो गैस की सब्सिडी के बारे में बता रहे हैं, सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी, जो हमारे यहां टेबल भी की गई थी, वह रिपोर्ट यह बताती है कि आप जो भी आंकड़े बता रहे हैं, ये सब गलत हैं। आप इस बात को नोट कर लीजिए। मैं सिर्फ आपको वह बात याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ था।...(व्यवधान)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : ठीक है, जब आप सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा कीजिएगा, तब आप यह बात बताइएगा।

उपसभापति महोदय, करोड़ों लोगों तक गैस का चूल्हा नि:शुल्क दिया गया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार-बार आ चुकी है। सीताराम जी कहेंगे कि सीएजी ने उसको कंट्राडिक्ट किया है, हम कहेंगे कि नहीं, हमने कंट्राडिक्ट नहीं किया है। हम जमीन की हकीकत की बात कर रहे हैं, हम कागज़ या कंप्यूटर की

हक़ीकत की बात नहीं कर रहे हैं। जमीन की हकीक़त यह है कि आज करोड़ों लोग हमें दुआएं दे रहे हैं। जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उनके घर में कभी गैस का चूल्हा आ सकता है, ऐसे लोगों को गैस का चूल्हा मिला है। मैं इसको विकास और विश्वास के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं, क्योंकि राजनैतिक व्यवस्था को लेकर लोगों में कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े हो गए थे। अगर कोई राजनेता, प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री इस तरह का आह्वान करे, तो बहुत कम ही ऐसा देखा गया है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उस आह्वान के पक्ष में खड़े हो जाएं। एक प्रधान मंत्री कहे कि हमें 'स्वच्छ भारत' का अभियान चलाना है और देश की सफाई के लिए काम करना है और लोग उसकी बात पर अमल करें। लोग यह सोचते हैं कि यह प्रधान मंत्री का काम थोड़े ही है कि वह स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छ भारत के लिए काम करे। यह बहुत छोटी चीज़ थी, लेकिन समाज में इसका बहुत बड़ा मैसेज गया था। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाज में जो बदलाव का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने का काम हुआ है और पूरे देश के सामने एक पॉज़िटिव मैसेज गया है।

उपसभापति महोदय, आज जिस विकास की बात हो रही है, वह धर्म, जाति, क्षेत्र या संप्रदाय इत्यादि की तमाम सीमाओं से ऊपर उठकर बात हो रही है। प्रधान मंत्री जी जब भी कोई बात कहते हैं, तो 125 करोड़ हिन्दुस्तानियों को संबोधित करते हुए कहते हैं। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि यह अमुक क्षेत्र के लोगों, अमुक धर्म के लोगों अथवा अमुक जाति या संप्रदाय के लोगों के लिए है, वे हमेशा 125 करोड़ लोगों का नाम लेते हुए अपनी बात कहते हैं। आज अगर विकास की सबसे ज्यादा किसी को जरूरत

है, तो निश्चित रूप से गरीब को है। अभी सीताराम जी एससी/एसटी और माइनॉरिटीज़ की बात कह रहे थे। तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या हमारे समाज में सबसे ज्यादा है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम गरीबों के विकास, गरीबों के सशक्तिकरण और empowerment की बात कर रहे हैं।

उपसभापति महोदय, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए हम ईमानदार राजनैतिक इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। यह हमारा राजधर्म ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य भी है और हम अपने उस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। यह वोट का सौदा नहीं है, यह विकास का मसौदा है।

उपसभापति महोदय, मैं नहीं मानता कि यह हमारी सरकार की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन चूंकि अल्पसंख्यकों का जिक्र आया है, तो मैं आपको इसके आंकड़े देना चाहूंगा। सरकारी नौकरियों में, विशेष तौर पर केन्द्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों का जो प्रतिशत था, वह 2014 में 5.3% था। सर, आज जब हम 2016 और 2017 के शुरुआती दिनों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज केन्द्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी 9.9% हुई है।

(3e/rpm पर जारी)

RPM-KGG/4.15/3E

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी (क्रमागत): महोदय, यह हमारी वजह से नहीं हुई है, हम नहीं मानते कि उनमें काबिलियत नहीं थी, उनकी काबिलियत भी थी। उनका यह अधिकार उन्हें पहले मिलना चाहिए था। भेदभाव हुआ होगा, लेकिन हमने वह माहौल

पैदा किया जिससे कि भेदभाव का माहौल खत्म हो और ईमानदारी के साथ उनकी काबिलियत का सम्मान किया जाए। इसका नतीज़ा यह हुआ कि इन पौने तीन सालों के अंदर केन्द्र सरकार में जो नौकरियों का प्रतिशत है, वह बढ़ता हुआ दिख रहा है। यह उनके अंदर विकास और विश्वास के माहौल की वजह से बढ़ रहा है। हम अपना राष्ट्रीय कर्तव्य और राज-धर्म मानते हैं कि यह माहौल बने रहना चाहिए और समाज के सभी वर्गों की काबिलियत का सम्मान होना चाहिए।

माननीय उपसभापति महोदय, आतंकवाद की बात आई, असहिष्णुता की बात आई, इनटॉलरेंस की बात आई, अवॉर्ड वापसी भी होती रही और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से अवॉर्ड निकाल-निकाल कर दिखाए जाते रहे कि यह अवॉर्ड हमें अंग्रेजों ने दिया है और मोदी जी हम इसे वापस करने जा रहे हैं। इन सारी चीजों के बावजूद भी माईनॉरिटी कमीशन अपनी जो रिपोर्ट देता है, वह बताता है कि इस बीच साम्प्रदायिक घटनाएं 200 प्रतिशत से ज्यादा कम हो गई हैं। इस बीच देश में कोई बड़ी साम्प्रदायिक उन्माद और और साम्प्रदायिक दंगों की घटना नहीं हुई। हम कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, यानी एक छोटी सी घटना भी नहीं होनी चाहिए। हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन अगर देश में विकास और विश्वास का माहौल बना है, तो यह हर देशवासी के लिए गर्व का विषय है। यह केवल हमारी सरकार या मोदी जी के लिए ही गर्व का विषय नहीं है। यह समाज के सभी वर्गों के लिए है। हम तो हमेशा कहते हैं कि "तू हाकिम बना है, तो इंसाफ भी कर, तू हिन्दू मुसलमान क्या देखता है"। जो हाकिम है, उसके लिए हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई कोई चीज नहीं है और उसे केवल

इंसाफ करना चाहिए और उस इंसाफ के रास्ते पर हम चल रहे हैं, इसलिए चीजें आएंगी और जाएंगी।

महोदय, मैं अक्सर कहता हूं और इस बार भी दोहराऊंगा कि -

"दौर है संगे आज़माई का और हम आईना सज़ाते हैं,

तुम हवाओं को हौसला बख्शो, हम चिरागों की लौ बढ़ाते हैं।"

हम चिरागों की लौ बढ़ा रहे हैं। पत्थर मारिए, विरोध करिए, आरोप लगाइए, लेकिन विकास के रास्ते में रोड़े मत अटकाइए। यह संकल्प है और हम इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

उपसभापति महोदय, एक तरफ बिचौलिए, एक तरफ बेईमानों की नाकेबन्दी, करप्शन और कुशासन का एक पूरा का पूरा माहौल खत्म किया है। कहीं पर करप्शन और कुशासन की जुगलबन्दी हो जाती है, तो वह अपने साथ चलता रहेगा। यह राजनीति है।

महोदय, मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात देश के लिए तो गर्व की है, लेकिन जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उनके लिए भी गर्व की बात है। मैं अभी अखबार पढ़ रहा था, उसमें जो पूरे देश में टेररिज्म है और टेररिज्म से जुड़े हुए जो हाउस हैं, इस्लामिक स्टेट, “How the Islamic State is guiding lone wolves across the world.” पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट और टेररिज्म किस तरह से अपने शिकंजे में जकड़ रहा है, यह लिखा था। हमें इस बात को कहने में गर्व और

खुशी हो रही है कि मेरा देश, मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश का संस्कार और मेरे देश के सभी लोगों का जो एक सद्भाव का संकल्प है, उसका नतीजा है कि कि आईएसआई जैसे आतंकवादी और शैतानी संगठन, इससे पहले अलकायदा जैसे आतंकवादी और शैतानी संगठन मेरे देश की धरती पर किसी भी तरह से अपनी जड़ें नहीं जमा पाए और उन जड़ों को जमाने की जहां भी कोशिश हुई, मेरे देश के सारे लोगों ने, सबसे आगे बढ़कर मुसलमानों ने, ऐसी ताकतों का विरोध किया और ऐसी ताकतों के खात्मे के लिए सबसे आगे बढ़े। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : प्लीज बैठिए।

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: उपसभापति महोदय, यह जो आतंकवाद है, यह जो radicalism है, यह किसी एक देश, एक मज़हब और एक समाज के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

(3एफ/पीएसवी पर जारी)

PSV-KLS/3F/4.20

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी (क्रमागत): ऐसी जो हैवानी ताकतें हैं, ऐसी ताकतें जो इंसानियत की दुश्मन हैं, उन ताकतों का खात्मा हम सब को मिल कर करना होगा। मेरे भारत के समाज के सभी लोग पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श हैं। ऐसी ताकतें, जोकि पूरी दुनिया में अपना खतरनाक जाल बिछाती हैं, जाल बिछाकर अपने काम को सफलता के साथ अंजाम दे रही हैं, यहाँ सफल नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पर अगर किसी परिवार में आईएस जैसे संगठन के लोग अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करते हैं, तो

उस परिवार के लोग सुरक्षा एजेंसीज़ को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मेरे परिवार का बच्चा ऐसे संगठनों के चंगुल में आ रहा है, आप इसका इंतजाम करिए। ऐसी एक-दो घटनाएँ हुई भी हैं। मुझे लगता है कि यह हमारे देश की संस्कृति और संस्कार का नतीजा है और इस देश में जो विकास और विश्वास का माहौल बना है, यह उसका नतीजा है। मेरा यह कहना है कि हम राजनैतिक रूप से जंग करते रहेंगे, राजनैतिक रूप से लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा पर हमें एक स्वर में, एक आवाज़ में बात करनी चाहिए। यही वह वजह है कि आज हमारा देश सुरक्षित भी और आज हमारा देश पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श भी बना हुआ है। उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, one minute. Sir, the hon. Minister has used a piece of paper to give some figures on the employment in the Central Government. I would request him to authenticate that paper and lay it on the Table of the House so that we know what the source of this data is. He has said that employment of minorities has gone up from 5 per cent to 9 per cent in two years.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He did not say he is quoting.

श्री जयराम रमेश: क्या चमत्कार है! दो साल में 5 प्रतिशत से 9 प्रतिशत हुआ है, उसको ऑथेंटिकेट करिए, ताकि हम भी जानें कि आपके डेटा का क्या सोर्स है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, he did not say that he is quoting.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: पहली बात, मैं आपको ऑथेंटिकेट करूँ ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: इसे छोड़िए। ...(व्यवधान)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: मैं पहले आपको बता देता हूँ कि यह जो फिगर है, यह मैंने हिन्दी में बोली थी, मैं दोबारा इंग्लिश में बता देता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister**,** you did not say that you are quoting, therefore, no need of authentication. But, however, if you think he has misled the House, there are other ways of tackling it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ahmed Patelji.

श्री अहमद पटेल (गुजरात): उपसभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने हेतु खड़ा हुआ हूँ और आपने मुझे यह अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, मैं अपना वक्तव्य शुरू करूँ, उससे पहले मैं नक़वी साहब को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि सब कुछ ठीक है, माइनॉरिटी, अक़ल्लियत, एससी, एसटी सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो गया है, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि:

"जलते हुए घरों की रोशनी शहरों को जगमगा चुकी,
अब तो खुदा के वास्ते दिल के दिये जलाएँ।
अब न जले कोई मकां, अब न उठे कोई धुआँ,

आग लगी जो बुझ गई, आग दबी बुझाइए।"

जो दबी हुई आग है, कम से कम उसको बुझाने की कोशिश करेंगे, तो ही मैं समझता हूँ कि देश का कल्याण हो पाएगा, देश का विकास होगा, देश की प्रगति होगी, देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। यू.पी. में अभी जो हो रहा है, जिस तरह से भाषण हो रहे हैं, जिस तरह से बातें हो रही हैं, कम से कम इसे तो रोकने की कोशिश करिए, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा माहौल हो जाएगा और देश तरक्की करेगा।

उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मुझे एक दिलचस्प बात, इंटरेस्टिंग बात यह लगी कि उन्होंने जो शुरुआत की है, उन्होंने तीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं से शुरुआत की है। सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी, जिनकी 350वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, दूसरे, रामानुजाचार्य जी की 100वीं जयंती मनाने जा रहे हैं और तीसरी बात चम्पारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ मनाने की कही है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें क्या सिखाया- सामूहिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करो, न कि सिर्फ एक व्यक्ति पर। इसीलिए वे पाँच प्यारों के साथ आए और उन्होंने विभाजन और घृणा की राजनीति को अस्वीकार करना सिखाया। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर किस-किस के साथ मशवरा करके प्रधान मंत्री जी आगे चल रहे हैं। मुझे खुशी होती अगर रवि शंकर प्रसाद जी का और आपका नाम भी इसमें होता या आपके साथ ही परामर्श और विचार करके प्रधान मंत्री जी आगे बढ़ते, तो मैं समझता हूँ कि शायद नोटबंदी नहीं हो पाती।

(3जी/वीएनके पर जारी)

VNK-SSS/3G/4.25

श्री अहमद पटेल (क्रमागत) : लेकिन आपको पता ही नहीं था कि नोटबंदी हो रही है या demonitisation का निर्णय लिया गया है, क्योंकि जहां तक मैंने अख़बार में पढ़ा है और जो सुना है कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई, बैठक बुलाने के बाद जब तक राष्ट्र के नाम संदेश नहीं हुआ, तब तक मंत्रियों को बाहर नहीं जाने दिया गया। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? सिर्फ टेलीविजन पर दिखाया गया। मैं समझता हूँ कि अगर आप गुरु गोबिन्द सिंह जी की 350वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं, तो कम से कम इनका जो जीवन है, उससे कुछ सीख लीजिए।

आपने दूसरी जो महत्वपूर्ण बात की है, वह रामानुजाचार्य की है। उन्होंने अपने जीवन को तीन विचारों के लिए समर्पित किया - विनम्रता और दया के लिए। उनकी शिक्षा का सार यह था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर झांके। हर एक व्यक्ति के अंदर जगाने वाला होता है। रवि शंकर प्रसाद जी बात कर रहे थे कि कोई जगाने वाला आया और लागों ने अपनी-अपनी गैस सब्सिडी भी वापस कर दी। आप जो बात कर रहे थे, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति हमें जगा नहीं सकता है। अगर हमें कोई जगा सकता है, तो हमारी जो अन्दरूनी शक्ति है, वही हमें जगा सकती है। हमने चम्पारण सत्याग्रह से क्या सीखा? गरीबी और हाशिये पर खड़े लोगों के शोषण के खिलाफ संघर्ष और सत्याग्रह। जब अंग्रेज सरकार ने किसानों और आदिवासियों के अधिकारों को छीनने की कोशिश की थी, उनका हक लेने की कोशिश की थी, तब वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही थी, जो आगे आई और चम्पारण और खेड़ा के सत्याग्रह के बाद गांधीजी 'महात्मा'

कहलाए और वल्लभभाई पटेल 'सरदार' कहलाए। मैं इस सरकार से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख तो किया गया और आप जश्न भी मनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार ने इन घटनाओं से कुछ सीखा भी है या सीखने वाले भी हैं? मैं सरकार से सिर्फ चार सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये सेलिब्रेशन्स तो करने जा रहे हैं, जन्म जयंती भी मनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या नफरत की राजनीति खत्म हुई? क्या वास्तव में सबकी राय को शामिल करके निर्णय हो रहा है, जो गुरु गोबिन्द सिंह ही ने हमें सिखाया था? क्या इस सरकार में विनम्रता है, जो रामानुजाचार्य जी को प्रिय थी? क्या किसानों और हाशिये पर खड़े लोगों का शोषण बंद हो गया है, जो चम्पारण और खेड़ा के सत्याग्रह ने हमें सिखाया था? सिर्फ जश्न मनाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इवेंट क्रिएट करने से कुछ नहीं होता। जो जनता का पैसा है, उससे आप इवेंट क्रिएट कर दीजिए और लोगों के सामने symbolic कोई चीज रख दीजिए, लेकिन लोगों का और जनता का भला नहीं होता। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो आपकी मानसिकता है, जो mentality है कि सिर्फ इवेंट क्रिएट करो, advertisement करो, publicity करो और कुछ हासिल कर लो। मैं समझता हूँ कि आपको इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है।

मैं समझता हूँ कि इस मोशन के जो मूवर थे, जो धन्यवाद कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देश बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि न तो आप देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, न तो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन ढाई साल में आपने सिर्फ बदले की भावना से काम किया, जिसे 'प्रतिशोध' कहते

हैं। आपके दिल में वह ज्वाला है कि जो हमारे प्रतिपक्ष हैं या जो हमारे विरोधी हैं, उनसे किस तरह से बदला लिया जाए। अगर यह नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं,..... आपने किस तरह से राष्ट्रपति जी के एक अभिभाषण में से उनके नाम को निकालने की कोशिश की, यह एक शर्म की बात है। राजीव जी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी,..... क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ नहीं किया? इतने सालों में आज देश जहां पर खड़ा है, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी का हिस्सा है, तो मैं समझता हूँ कि वह उनका है, जिन्होंने प्लानिंग की। बाकी औरों का भी है, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आज़ाद, लालबहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, राजीव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कहीं न कहीं सभी प्रधान मंत्रियों का हिस्सा है।

(3एच/एनकेआर-एनबीआर पर जारी)

NKR-NBR/3H/4.30

श्री अहमद पटेल (क्रमागत) : लेकिन आपने बदले की भावना से, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के लिए काफी काम किया, आप उनका नाम भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंदिरा जी के नाम को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि राजीव जी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, सद्भावना से, आपने उनका नाम भी हटा दिया। देश के सभी लीडरों का देश के विकास में कहीं-न-कहीं हिस्सा रहा है। Recently, आपने जी.एस.पी.सी. जिसमें इतना स्कैम हुआ, उसको ONGC में मर्ज तो कर दिया और राजीव जी ने ONGC के लिए जो काम किया, उसके बिल्ले से भी आपने उनका नाम हटाने की

कोशिश की। यह बदले की भावना की राजनीति है और आप बात करते हैं गुरु गोबिन्द सिंह जी की, जिन दूसरे महापुरुषों की जयंती है, उनकी जन्म जयंती को मनाने की। आप करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। कम-से-कम उनके जीवन से कुछ तो सीखने की कोशिश कीजिए।

आप देखें कि अनेक विश्वविद्यालयों में वहां के छात्रों के साथ क्या हुआ? आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से प्रतिशोध या बदला लिया जाए। मैं नहीं समझता कि आप किस चीज का बदला लेना चाहते हैं? किस चीज के प्रतिशोध के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं? मैं यहां आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जब देश में भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से कांग्रेस पार्टी ने, आजादी के इतिहास में जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए, शहादतें दीं और आजादी के बाद भी, आप जानते हैं कि देश को आर्थिक तौर पर आजाद करने के लिए, इस देश को एक और अखंडित रखने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, सरदार बेअंत सिंह जी ने दी, इंदिरा जी ने दी, राजीव जी ने दी, आप लाख कोशिश कर लें लेकिन कभी भी कांग्रेस-मुक्त भारत नहीं बना सकते या इंदिरा जी, राजीव जी, पंडित जी, जिन लोगों ने कुछ किया है, उनका नाम आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि देश को बनाने में हमारा खून भी शामिल है।

"इस रंगे गुलशन में हमारा खून भी शामिल है,

और यह रंग वह नहीं, जो मिट जाए लग जाने के बाद।"

मैं समझता हूं कि आपने पिछले तीन सालों में अगर कुछ किया है, तो देश की एजेन्सियों का दुरुपयोग कैसे किया जाए, यह किया है। विचारों में मतभेद हो सकता है लेकिन यह मतभेद कभी मनभेद में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई सहमत नहीं है, पॉलिसी या विचारधारा में, तो उसे परेशान नहीं किया जाता। आज क्या हो रहा है? आज किस तरह से नियुक्तियां हो रही हैं? जो एजेन्सीज़ के हैड्स हैं, उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि आपको प्रमोशन मिलेगा। अब न्यायालय ने उनके मामले में क्या कहा? Extra Constitutional Authorities के घरों पर एजेन्सीज के हैड्स जाकर वहां से ऑर्डर्स लेते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात दूसरी क्या हो सकती है? अगर टेलिफोन रिकॉर्ड्स निकालकर देखें, तो आपको पता चलेगा कि ऑर्डर्स कहां से लिए जाते हैं?

तीन सालों में, जो आपके साथ सहमत नहीं हैं, उन्हें या तो आपने कम्युनल बना दिया या एंटी-नेशनल बना दिया। मेरे विचार से इससे ऊपर उठने की जरूरत है। क्या यही आपका परिवर्तन है, क्या यही आपका बदलाव है?

नोटबंदी की बात यहां काफी हुई। मैं उसमें आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, आरंभ में हम लोगों ने भी कहा और नोटबंदी या demonitization को सपोर्ट किया, क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने जैसा कहा, हमने माना कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा, इससे काला धन बाहर आएगा, इससे देश में जो टैररिस्ट एक्टीविटीज हैं, आतंकवाद रुक जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपको कुछ नहीं मिला, बल्कि आपने पूरे देश के लोगों को लाइन में खड़ा कर

दिया, चाहे वह बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, मां हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो। मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा। एक बूढ़ा बाप लाइन में खड़ा हुआ था। उसकी बेटी की शादी थी। बैंक से पैसे मिल जाएं तो बेटी की शादी कर सके लेकिन बेचारा लाइन में खड़ा-खड़ा मर गया। उसका निधन हो गया, इंतकाल हो गया। फिर बेटी लाइन में लग गई क्योंकि अपने बाप की अंतिम क्रिया के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इससे बड़ी अफसोस की बात और क्या हो सकती है? बिना सोचे-समझे आपने जो फैसला लिया, अल्टीमेटली नोटबंदी से क्या मिला? क्या सारे-के-सारे पैसे आ गए? कुछ ज्यादा पैसे भी आ गए? मैं समझता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी आर.बी.आई. या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से काम कर रही थी - क्या रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया बन गई थी? हर रोज़ नए फतवे निकल रहे थे। नियम चेंज किए जा रहे थे। नोटिफिकेशन निकाले जा रहे थे। आखिर, नए नोट कहां गए जो इतने सारे आपने प्रिंट किए थे?

(3J/DS पर जारी)

DS-USY/4.35/3J

श्री अहमद पटेल (क्रमागत) : आखिर जो भी है, जब आपने इतने सारे नोट प्रिंट किए थे, तो नये नोट कहाँ गये? इसमें अभी भी restrictions हैं, मैं अपने पूरे पैसे नहीं निकाल सकता। आखिर पैसा कहाँ गया? बाहर 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत पर लोग अपने काले धन को एक्सचेंज कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि यह सबसे बड़ा स्कैम है और इसके बारे में जाँच होनी चाहिए कि ये पैसे कैसे एक्सचेंज हो रहे थे? ये लोग कौन थे,

जो पैसे एक्सचेंज कर रहे थे, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी।

दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी। यूपीए के समय में 8 प्रतिशत ग्रोथ रेट थी, लेकिन अब आप पॉलिसी पैरालिसिस के नाम पर 6.5 प्रतिशत की वृद्धि को बेहतरीन गिनाने की कोशिश कर रहे हैं और वह भी नई गणना से! हक़ीकत यह है कि आप अपने कार्यकाल के दौरान 8 प्रतिशत के ग्रोथ रेट कभी हासिल नहीं कर पाए। चाहे आप यह कह लें कि आप 8 प्रतिशत के ग्रोथ रेट पर पहुँच जाएँगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप 8 प्रतिशत के ग्रोथ रेट पर पहुँच पाएँगे। इससे आप क्या करना चाहते हैं? क्या यही आपका परिवर्तन है, यही बदलाव है? कहा जा रहा है कि देश बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। उस पर मैं आगे आऊँगा, लेकिन जहाँ तक एग्रीकल्चर का सवाल है, हमारे मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किसानों की क्या हालत है। वे परेशान हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। आपने नोटबंदी का डिसीज़न उस वक्त पर लिया, जब उनकी रबी का प्रोडक्शन आने वाला था। उसे वे लोग बेच नहीं पाए और जो नई फसल उनको उगानी थी, उसके लिए उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उनके पास बीज के पैसे नहीं थे, खाद के पैसे नहीं थे। आपने इन लोगों को बहुत ही दयनीय स्थिति में डाल दिया। किसानों के नाम पर आप कह रहे हैं कि 40 प्रतिशत किसान कल्याण में वृद्धि हुई, लेकिन किसानों के लिए बजट में सिर्फ 6.14 परसेंट वृद्धि हुई।

राष्ट्रपति जी ने कृषि विकास योजना की बात की है। बजट तो आपने 12 प्रतिशत कम कर दिया और आप बैंकों द्वारा अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले कर्ज को अपनी उपलब्धि के रूप में गिना रहे हैं। उसमें आपने कमी कर दी। आपने कृषि योग्य भूमि में 57 प्रतिशत सिंचाई की बुनियादी सुविधाओं की बात की है। आपने कहा है कि सिंचाई की सुविधाओं में 57 प्रतिशत की वृद्धि होगी और उसके लिए 1,450 करोड़ रुपये रख दिए गए, लेकिन उसमें से हज़ार करोड़ रुपये तो ब्याज में जाएँगे, आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ 400 करोड़ रुपये! फ्लैगशिप प्रोग्राम- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लेकिन जिन्होंने कृषि के लिए लोन नहीं लिया है, उनके कवरेज में सिर्फ 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यूपी, बिहार में जब फ्लड आया, जब बारिश आई, तो इस स्कीम का लाभ नहीं मिला। ये सब बातें पेपर पर हैं, मैं इनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको जो सारी उपलब्धियाँ हैं, उनको मैं गिनाने की कोशिश कर रहा हूँ।

राष्ट्रपति जी ने अपने पहले के अभिभाषण में कहा था- Per drop, more crop. पता नहीं वह ड्रॉप भी कहाँ गया और वह क्रॉप भी कहाँ गयी, लेकिन जब drought आया तो सरकार का रवैया कुछ और ही था। न कोई टीम भेजी गई, न उसे सीरियसली लिया गया। Drought में किसी को फायदा नहीं मिला और न तो किसी को मदद मिली। मेरे ख्याल से ये जो उपलब्धियाँ आप गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ कागजी हैं। बेचारा किसान मेहनत करता है, रात और दिन मजदूरी करता है, लेकिन ultimately उसको क्या मिला? आप कह रहे हैं कि किसान को बहुत कुछ मिला है, तो इतनी आत्महत्याएँ क्यों हो रही हैं? किसान आज परेशान है, वह मारा-मारा घूम रहा है,

उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपने किसानों की उपज का 50 प्रतिशत मुनाफा देने की बात की थी, लेकिन वह सिर्फ जुमला बनकर रह गया। उसके बावजूद, आपने यह कहना शुरू कर दिया कि किसानों की आय को हम लोग वर्ष 2020 में दोगुना कर देंगे। पता नहीं आप वर्ष 2020 में कहाँ से उसको दोगुना करेंगे? क्योंकि आप तो करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वर्ष 2020 में जब आप ही नहीं रहेंगे तो उनकी आय को आप कहाँ से दोगुना करेंगे?

किसानों के बाद अब मैं एससीज़ और एसटीज़ पर आता हूँ, जिनके बारे में शरद यादव जी और सीताराम येचुरी जी भी बात कर रहे थे। इस सरकार ने सिर्फ किसानों से नहीं, बल्कि एससीज़ और एसटीज़ के साथ भी विश्वासघात किया है, उनको * किया है। वर्ष 2016 में रोहित वेमुला से लेकर उना में दलितों पर अत्याचार हुआ। पिछले साल दलित उद्यमियों के लिए Stand-up India की शुरुआत की थी, आपने 2,000 करोड़ रुपये देने का वादा किया था, लेकिन कितना दिया? सिर्फ 200 करोड़ रुपये! यह * नहीं है तो और क्या है? यह है आपका बदलाव, यह है आपका परिवर्तन?

(3के/एमसीएम पर जारी)

MCM-PK/3K/4-40

श्री अहमद पटेल (क्रमागत) : मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा था, लेकिन शर्म की बात तो यह है कि इकोनॉमिक सर्वे में कहीं पर दलित का जिक्र नहीं किया गया। यहां आप बात कर रहे हैं एस0सी0 और दलित की। वजह क्या है, एस0सी0, एस0टी0 भाई-

---

***Expunged as ordered by the Chair.**

बहन जितना हिस्सा लेने के लिए हकदार हैं, उसे आधा कर दिया गया है। मैं आपको जो कम्युनिटी है, उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। "In the merged scenario of Plan and Non-Plan, estimates following the Jadhav guidelines mandate allocating a minimum of 4.63 per cent under the Scheduled Castes Sub-Plan and 2.39 per cent under the Tribal Sub-Plan of the total Budgetary allocation of the Union." In that case, the denied and misallocated amount should total Rs.71,139 crores for the SC and Rs.34,000 crores for the ST." लेकिन आपने दिया क्या, एस0सी0 के लिए 4.63 परसेंट होना चाहिए, एस0टी0 के लिए 2.39 परसेंट होना चाहिए, जिसको आपने आधा करके रख दिया है। दलितों के लिए जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान था, उसको आपने कल्याण योजना में बनाकर रख दिया एस0सी0, एस0टी0 के लिए। रवि शंकर प्रसाद जी बात कर रहे थे दिव्यांग की, विकलांग की। प्रधान मंत्री जी ने इसका नाम विकलांग से दिव्यांग कर दिया। वैसे बहुत बड़ी बात कर दी। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस दिन उन्होंने यह किया तो उसी दिन जो एसोसिएशन थी, इसको उन्होंने अपोज़ किया। उन्होंने यह कहा कि "Several Disabled People's Organisations on Friday strongly objected to the use of the term 'Divyang' to address the disabled people community and urged Prime Minister, Shri Narendra Modi, not to use it and to replace it as 'Viklang'." वे लोग खुद विरोध कर रहे हैं, सिर्फ आपको क्योंकि कहीं न कहीं कुछ परिवर्तन करना है, कहीं न कहीं कुछ चेंज करना है, कहीं न कहीं कुछ बदलाव करना

है, लेकिन कभी यह भी नहीं सोचना है कि जो आप परिवर्तन कर रहे हैं या जो आप बदलाव कर रहे हैं, वह आप सही मायने के लिए कर रहे हैं, सही चीज के लिए कर रहे हैं या गलत चीज के लिए कर रहे हैं। इस देश में दिव्यांग की जो संख्या है, वह 2 करोड़ 60 लाख है। उसमें से एंप्लॉएबल कितने हैं? वे 1 करोड़ 60 लाख हैं। उसमें सिर्फ employed कितने हैं? 60 per cent are employed. अभी भी एक करोड़ ऐसे डिसएबल्ड हैं दिव्यांग या विकलांग, जिनको रोजगार नहीं मिलना है। सरकार दिव्यांगों के लिए बड़ी बातें करती है, लेकिन बजट में The Right to Disabilities Act के लिए कोई प्रावधान नहीं है। दो प्रोविजन हैं। यू0पी0ए0 टाइम पर जो 5 प्रतिशत का प्रावधान था, वह घटाकर आपने 4 प्रतिशत कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट पर डिसएबल के जॉब अभी भी अवेलेबल नहीं हैं। जो लिस्टिंग है, वह अवेलेबल नहीं है कि कहां-कहां जॉब्स उपलब्ध हैं, कहां-कहां नौकरियां उपलब्ध हैं? वह भी अवेलेबल नहीं है। जो मुझे कहा गया है, कितना सही है, कितना गलत है, आप वेरिफाई कर सकते हैं। जब प्रधान मंत्री जी गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, मैं नहीं समझता कि सरकारी नौकरी में विकलांग को या डिसएबल्ड को इतनी नौकरी या जॉब्स दी गई हों। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? आप बात कर रहे हैं विकलांग की, दिव्यांग की, सबसे ज्यादा अगर कोई काम रहे हैं डिसएबल्ड के लिए, विकलांग के लिए और दिव्यांग के लिए, तो एन0जी0ओज़0 कर रहे हैं। जो जयपुर फुट है, वह बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अभी मेरे यहां भी कैम्प किया था दो दिन के लिए। अगर वे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, उसका श्रेय अगर किसी को जाना चाहिए तो

यू0पी0ए0 की सरकार को जाना चाहिए, क्योंकि सी0एस0आर0 से जो फंड उनको मिल रहा है, उसी से वे काम कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं दिव्यांग की और विकलांग की। मैं समझता हूं कि सिर्फ यश लेने के लिए बात करना, यह सही बात नहीं है। मैं इस सरकार से यही कहना चाहूंगा कि इस सरकार पर वास्तविक सेवाओं के बजाए केवल भाषण सेवा का जुनून सवार है, सिर्फ जुमला सेवा का जुनून सवार है। यह सरकार यह नहीं सोचती कि जमीन पर क्या अच्छा लगता है, बल्कि यह सरकार यह सोचती है कि विज्ञापन में क्या अच्छा लगता है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ फोटोग्राफ। हर जगह एडवर्टाइजमेंट, जैसे यह सरकार पूरी विज्ञापन पर चल रही है, एडवर्टाइजमेंट पर चल रही है। आपके पैसे सुरक्षित हैं, सिर्फ यह कहने से तो काम नहीं चलता। जब बैंक में जाते हैं तो वहां उनको अपने पैसे भी नहीं मिल सकते। अपने पैसे जो खुद नहीं ले सकते महीनों तक, उसे आप कह दो कि आपके पैसे सुरक्षित हैं। हरेक जगह जहां आप जाओ, आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा।

सब्सिडी की बड़ी बात हो रही थी, महिलाओं को कहीं से सब्सिडी लेकर गैस के कनेक्शन दिए गए। कोई मुफ्त में तो नहीं दिए गए। जो भी बिल आता है, वह उसकी पेमेंट कर रही है। सिर्फ एक कनेक्शन आपने दिया होगा, बहुत अच्छी बात है। हम उसका स्वागत करते हैं।

(3L/SC पर जारी)

SC-PB/4.45/3L

श्री अहमद पटेल (क्रमागत) : हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एससी, एसटी, - जो downtrodden हैं, जो ओबीसी हैं, उनके बजट में आपने कटौती की है। उनकी जो सारी योजनाएं थीं, उनके जो सारे प्रोग्राम थे, वे बंद हो गए। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। उस दिन रवि शंकर प्रसाद जी कह रहे थे कि अब की बार एक महिला अधिकारी द्वारा परेड का नेतृत्व करना देश के लिए गर्व की बात है। अच्छी बात है। We are also proud of that. ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आएं, यह बहुत ही जरूरी है, लेकिन रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा? रक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि सेना में कोई महिला यूनिट नहीं होगी। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? 'No plan for women in army combat role', Parrikar tells Rajya Sabha. इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि महिलाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, वे इस तरह की बात कर रहे हैं।

सर, 31 दिसम्बर, 2016 को प्रधान मंत्री जी ने कहा कि "गर्भवती महिलाओं के लिए नयी योजना की घोषणा" अब उन्हें पता ही नहीं था कि उनके लिए पहले से ही योजना थी। हकीकत यह है कि फूड सिक्योरिटी योजना के तहत यह अधिकार दिया गया था, लेकिन सरकार ढाई साल तक यह बात टालती रही और फिर announcement कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कर दिया। आप ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्या यह आपका परिवर्तन है? क्या यह आपका बदलाव है? महिलाओं के आरक्षण का क्या हुआ? पुलिस आधुनिकीकरण की बात हो रही है, लेकिन उसका जो फंड है, जो

धन है, जो राशि उन्हें मिलनी चाहिए, उसमें कटौती की गयी है। जीडीपी के हिसाब से डिफेंस में होने वाले खर्च में कटौती की गयी है। क्या यह आपका परिवर्तन है? क्या यह आपका बदलाव है?

आपने डिजिटल इंडिया के बारे में कहा। सन् 2016 तक ये लोग सभी ग्राम पंचायतों को broadband से जोड़ने वाले थे। ये कह रहे थे कि broadband से हम सारी पंचायतों को जोड़ देंगे, लेकिन ultimately लक्ष्य क्या प्राप्त किया, target क्या प्राप्त किया - केवल 26 प्रतिशत। पता नहीं, 2016 भी निकल गया और सिर्फ 26 प्रतिशत को इन्होंने broadband से जोड़ा। "आधार" के लिए ये लोग कह रहे थे कि आप "आधार" ले आए - जरूर हम ले आए। रमेश जी बैठे हैं, लेकिन हम लोग, जो उनकी privacy है, जो उनकी व्यक्तिगत जानकारी है, उसकी रक्षा करना चाहते हैं। आज क्या हो रहा है? आज उनकी व्यक्तिगत जानकारियां लीक हो रही है।

इसी प्रकार उन्होंने JAM की बात की, जन-धन आधार मोबाइल के बारे में कहा। मूवर JAM की बात कर रहे थे। सच्चाई यह है कि आज आपकी सारी योजनाएं jam हो चुकी हैं, आपकी कोई योजना चल नहीं रही है। बजट में जिस तरह से प्रावधान होना चाहिए, अगर प्रावधान है भी, तो भी उसका implementation नहीं हो रहा है। आपने पुदुचेरी में बात की थी, 'Direct Benefit Transfer' की, लेकिन ultimately क्या हुआ - वह विफल हो गया, jam हो गया और फिर बंद हो गया। आप Smart Cities की बात कर रहे हैं। Smart Cities में अज़ीम प्रेमजी ने दो दिन पहले क्या कहा? उन्होंने कहा कि 'Smart Cities project more talk than action'. आप Smart Cities की बात कर रहे

हैं! अज़ीम प्रेमजी, जो आपकी तारीफ कर रहे थे, जो बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, आज वे आपको यह सर्टिफिकेट दे रहे हैं।

आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य समिति के बारे में मैं कहना चाहूंगा। सर, उन्होंने एक और बात की थी - "स्वच्छ भारत" की बात। उन्होंने कहा था कि सन् 2016 तक 4 हज़ार शहर और 6 लाख गांव ODF, Open Defecation Free, खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगे। पता नहीं उसका क्या हुआ? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ 141 शहरों में आप यह काम कर पाए हैं और गांवों का तो अता-पता ही नहीं है कि वहां पर क्या स्थिति है? सफाई ऐसे नहीं होती है। आप कह रहे थे कि आपने तीन लाख toilets बना दिए, लेकिन जहां toilets हैं, वहां पानी का इंतज़ाम नहीं है। आप सफाई करने निकले हैं! अगर सफाई करनी है तो जो आपका झाड़ू है, वह साफ होना चाहिए। यहां तो आपका झाड़ू ही गंदा है, उससे क्या सफाई होगी? इसके लिए मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। अगर मानसिकता सही है तो सफाई सही होगी। आप जो स्वच्छता की बात करते हैं, उसके लिए सबसे पहले अगर किसी चीज़ की जरूरत है तो आपकी जो मानसिकता है, उसे सही करना होगा। ..(व्यवधान).. मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं कि आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आप बदलाव की बात कर रहे हैं। उस दिन रवि शंकर प्रसाद जी बात कर रहे थे।..(व्यवधान).. गुजरात में आपको मालूम है। आपको मालूम है, अभी भी सौराष्ट्र में किस तरह से हो रहा है? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।

(3एम-जीएस पर जारी)

SKC-GS/3M/4.50

श्री अहमद पटेल (क्रमागत): आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, उस दिन रवि शंकर प्रसाद जी महिलाओं के बारे में कह रहे थे। वे पी.वी. सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा करमाकर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार नहीं थी, तब भी ये लोग उत्कृष्ट और बेहतरीन प्रदर्शन किया करते थे, ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार ने कुछ किया, इसीलिए उन्हें मेडल मिला या अवार्ड मिला। वर्ष 2014 के राष्ट्रपति अभिभाषण में खेल प्रतिभा खोज प्रणाली बनाने की बात कही थी, पता नहीं उसका क्या हुआ? इस बात को तीन साल हो गए। आपके सब वायदे ही वायदे हैं। ...(व्यवधान)...

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): खेल प्रतिभा वाली यह स्कीम तो अभी चल रही है। ...(व्यवधान)... बाकी आपने सत्य कहा है या असत्य कहा है, यह मुझे नहीं मालूम है। ...(व्यवधान)... उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री अहमद पटेल: खेल प्रतिभा खोज प्रणाली कैसी चल रही है, यह मुझे नहीं मालूम। ...(व्यवधान)... स्कीम ठीक तरह से तो चलनी चाहिए। ...(व्यवधान)... और अभी तो आप आए हैं, अभी तो छह-महीने, साल हुआ है। विजय गोयल जी, हम अपेक्षा करेंगे कि आप आगे चलकर कुछ अच्छा करें। ...(व्यवधान)... स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा पिछले साल की थी, वह भी लाल किले से घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम है। सिर्फ घोषणाएं ही घोषणाएं हो

रही हैं, सिर्फ बातें ही बातें हो रही हैं, सिर्फ वायदे ही वायदे हो रहे हैं। अच्छा, नार्थ-ईस्ट के बारे में बात करते हैं। उत्तर पूर्व को तो अष्ट लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन अष्ट लक्ष्मी के साथ आपने क्या किया? अरुणाचल की सरकार, जहां पर आप थे ही नहीं, क्योंकि आपको राष्ट्रपति के लिए वोट चाहिए, इसलिए वहां की सरकार गिरा दी। ...(व्यवधान)... अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी और आज नागालैंड में क्या हो रहा है, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। उत्तराखंड देवभूमि मानी जाती है और उत्तराखंड के साथ आपने छेड़खानी की, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। जम्मू-कश्मीर के बारे में LoP ने बहुत कुछ बताया है, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं।

अच्छा, आप लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। भ्रष्टाचार के बारे में राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा था कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकपाल का होना जरूरी है। यह वर्ष 2014 में कहा था और मेरी सरकार इसके लिए कानून बनाने का समर्थन करेगी और जरूरी नियमों का अनुपालन करेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि न्याय मिलने में देरी, न्याय नहीं मिलने जैसा है, बराबर है। मेरी सरकार हमारी न्याय प्रणाली में लम्बित पड़े हुए मामलों को निपटाने के लिए एक बहुकोणीय रुख अख्तियार करेगी। तीन साल हो गए हैं, क्या हुआ लोकपाल का? क्या हो रहा है न्यायपालिकाओं में ? शर्म की बात तो यह है कि फॉरमर चीफ जस्टिस को जजों के तबादले करने के लिए, नियुक्तियां करने के लिए रोना पड़ा। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? भ्रष्टाचार रोकने के लिए सबसे बड़ा

हथियार प्रवर्तन एजेंसियां होती हैं। वे एजेंसियां किस तरह से काम कर रही हैं, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्रवर्तन एजेंसियां उनके अनुसार काम कर रही हैं, राजनीतिक विरोधियों की कार्यवाही के लिए जैसे ये एजेंसियां बनाई गई हों। मेरे ख्याल से ये बातें अच्छी नहीं हैं। इस साल यह बात फैलाई जा रही है कि जो अवॉर्ड योग्य पात्र हैं, उनको ही अवॉर्ड दिए गए हैं। श्री रवि शंकर प्रसाद जी बड़े जोरों से इस बात को कह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले सात साल में जो अवॉर्ड दिए गए, जो पुरस्कार दिए गए, क्या वे गलत दिए गए? क्या ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आज़ाद योग्य नहीं थे? क्या सिस्टर निर्मला योग्य नहीं थीं? क्या जयपुर को बनाने वाले बी.आर. मेहता योग्य नहीं थे? हम भी गिनवा सकते हैं, तीन साल में कई नाम हैं, जिनको मैं गिनवा सकता हूं। गुजरात से अभी किसी को दिया है, मैं भी गिनवा सकता हूं कि किस तरह से पोलिटिकल कंसिडरेशन के तौर पर ये अवॉर्ड दिए गए हैं। मैं ज्यादा इस में जाना नहीं चाहता हूं। ठीक है, इस बार आपने कुछ अच्छे अवॉर्ड दिए होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि पिछले सात साल में जो अवॉर्ड दिए गए, वे बिल्कुल खराब थे और वे योग्य नहीं थे। कम से कम अवॉर्ड के नाम पर तो राजनीति करना बंद कर दीजिए। इस पर तो पोलिटिक्स न करें। अवॉर्ड देना कोई बड़ी सिद्धि नहीं है, जैसे सरकार ने बहुत बड़ी सिद्धि कर दी और बहुत बड़ा अचीवमेंट कर दिया।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में simultaneously election के बारे में बात की है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब भी आप कोई डिसिज़न

लें, तो मेरे ख्याल से इसमें एक आम सहमति बनानी जरूरी है, consensus बनाना बहुत ही जरूरी है।

उपसभापति जी, यह सरकार गरीबों के लिए नहीं, बल्कि कुछ अमीरों के प्रति समर्पित है। आज किसान बदहाल हैं, एस0सी0/एस0टी0 आज संसाधनों की कमी झेल रहे हैं, अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग नुकसान झेल रहा है। आजकल प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में तीन शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। एक तो "मित्रो" कहना बंद कर दिया है, दूसरे "नोटबंदी" कहना बंद कर दिया है और तीसरे नौकरी के बारे में, जॉब के बारे में कहना बंद कर दिया है।

(HMS/3N पर जारी)

HK-HMS/3N/4.55

श्री अहमद पटेल (क्रमागत) : मुझे नहीं मालूम क्यों बंद कर दिया है? किस का साथ और किस का विकास, किसी को पता नहीं है। जागने वाले की बात हुई, लेकिन हमने सुना है कि आजकल भजिए वालों और चाय वालों पर भी ई0डी0 के रेड पड़ रही है। मुझे पता नहीं, उस पर जांच करने की जरूरत है? मंत्री जी ने जनशक्ति की बात की, लेकिन जनशक्ति तभी आती है, जब मन की बात नहीं, जन की बात सुनी जाती है।

महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। मान्यवर, हमारा देश प्राचीन देश है। यह भूमि संतों की भूमि है। यहां जगाने वालों की जरूरत नहीं है, यहां काम करने वालों की जरूरत है क्योंकि सिर्फ जगाने वालों से काम नहीं होता। यहां कोई साथी कह रहे थे कि कोई जगाने वाला आ गया, जिस ने देश को जगा दिया। सर,

जगाने वाला आएगा और देश जाग जाएगा, यह बहुत ही भयावह है। It is dangerous. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी जगाने वाले के बिना हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं।

महोदय, अभी परिवर्तन की बात की जा रही थी। राजा राम मोहन राय ने कहा था कि परिवर्तन से बड़ी होती है परिभाषा। उन्नति से दुर्गति को भी परिवर्तन कहते हैं, जो आज हो रही है। उजाले से अंधेरे को भी परिवर्तन कहते हैं, आशा से निराशा को भी परिवर्तन कहते हैं। गांधी जी की नकल करने से पहले गांधी जी के कहे को भी ध्यान में रखना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि दूसरों को बदलने से पहले खुद अपने आपको बदलो। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। मान्यवर, अच्छी बात है कि इस अभिभाषण में गांधी जी और "मनरेगा" की बात की गयी है, लेकिन सरकार में बैठे लोग, अपने नायकों को ही अभिभाषण में भूल गए हैं। अच्छा ही हुआ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो अपने नायकों को ही भूल जाते हैं, उन पर जनता क्या भरोसा करेगी?

उपसभापति जी, अंत में इतना ही कहूंगा कि सरकार कह रही है कि देश बदल रहा है। अब सिर्फ 24 महीने बाकी हैं। मैं कहूंगा कि कुछ भी नहीं बदला है। चिड़ियों ने कहा, चमन बदल गया, गुलों ने कहा गुलशन बदल गया, रविशंकर जी ने कहा, देश बदल गया, लेकिन पीछे से जनता की आवाज आयी, देश वहीं-का-वहीं है। अगर बदला है तो सिर्फ और सिर्फ किसी की चाल बदली है, किसी का चेहरा बदला है और किसी का अंदाज़ बदला है। सरकार में सिर्फ अहम है, अभिमान है और गुरूर है। 2019 में यह

गुरूर भी टूट जाएगा, यह अभिमान भी टूट जाएगा। अगर देश को आगे बढ़ाना है, तरक्की और प्रगति करनी है, तो जो गांधी जी ने कहा था, हमारे संतों ने कहा था, उसे ध्यान में रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन की औपचारिकता निभाते हुए अपना वक्तव्य खत्म करता हूं और उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हमने क्रम संख्या 1 से 78 तक संशोधन रखे हैं। महोदय, मुझे समाजवादी पार्टी की ओर से बोलने का मौका दिया गया है, मैं अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास किया है ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prasad*ji*, your party has only three minutes left.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : सर, उनकी maiden speech थी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You take five minutes.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : सर, संजय सेठ जी की maiden speech थी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am sorry; this kind of strategy of giving the maiden speech to the last speaker is not good. How can it be? Don't try to

make this kind of a strategy. I will not treat it your maiden speech. …(Interruptions)… Take only five minutes. …(Interruptions) ..

(Contd. by KSK/3O)

ASC-KSK/5.00/3O

MR. DEPUTY CHAIRMAN (CONTD.): Nishadji, this will not be treated as your maiden speech.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : सर, मेरी maiden speech नहीं, श्री संजय सेठ जी की maiden speech थी।

श्री उपसभापति : पहली maiden speech थी, यह ठीक है। So, you take five minutes more.

(उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) पीठासीन हुए)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है, उसमें सरकार की तरफ से जो कहा गया है, वे केवल असत्य वायदे हैं। आज किसान अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। पूरे देश का किसान तबाह व बरबाद हो गया है। नोटबंदी के बाद किसान की यह दशा हुई है कि उसका अपना उत्पादन टमाटर, मटर और आलू खेत में ही सड़ गया है, जिसके कारण लोगों ने उसको नदी, नालों और समुद्र में फेंकने का काम किया है। आज जिस तरह से कृषि उत्पाद के दाम घटे हैं, तो इससे किसान को उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, जबकि

पश्चिमी देशों में और अमरीका जैसे शक्तिशाली देशों में किसान की उपज के मूल्य की गारंटी ली जाती है। जो भी किसान उपज पैदा करता है, उस पर लागत और नफा लगाकर सरकार खुद उसको खरीदने का काम करती है, भले ही बाद में सरकार उसको समुद्र में फेंकने का काम करे, लेकिन किसान को कोई घाटा नहीं होने दिया जाता है। दूसरी तरफ यहां पर बातें तो बड़ी की जाती हैं कि हम किसानों को फसल बीमा देंगे, लेकिन पूरे देश में फसल बीमे का कहीं अता-पता ही नहीं है। अधिकारी उनके आंकड़ों के चक्र में फंसे हैं, कहते हैं कि हम हर खेत को पानी देंगे। हमारे बुंदेलखंड का हाल बेहाल है। आज वहां पर पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई के पानी की समस्या है तथा अन्य जानवरों के लिए पानी की समस्या है। वहां पर सर्दियों में किसान अपनी खेती के लिए खेत में पड़ा रहता है। उसको वहां कोई बिच्छू काट लेता है, सांप काट लेता या कोई पागल सियार काट लेता है। वहां इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं। मान्यवर, इस अभिभाषण में बुंदेलखंड का कोई उल्लेख नहीं है और न ही बजट में है।

मान्यवर, जिस तरह से नोटबंदी आई और सरकार ने online के लिए ATM और Paytm के बारे में कहा कि इसका प्रयोग करो, तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आप स्वच्छता अभियान में अरबों- करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। एक तरफ तो आप बता रहे हैं कि आपको कहां लैट्रीन जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए और दूसरी तरफ आप ATM और Paytm के बारे में कह रहे हैं। वह आदमी कैसे ATM और Paytm ऑपरेट कर पाएगा, जिस आदमी को आप सिखा रहे हो कि कहां लैट्रीन के

लिए बैठना चाहिए और कहां नहीं बैठना चाहिए? जब तक देश में हर आदमी के पास अपना मकान नहीं होगा, हर आदमी शिक्षित नहीं होगा, हर आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक यह कैसे संभव होगा? इस समय देश का नौजवान परेशान है और वह अपनी दिशा से इधर-उधर धूम रहा है। देश में नोटबंदी के बाद से जितने धंधे व कुटीर उद्योग-धंधे थे, वे सारे के सारे उद्योग-धंधे बंद हो गए हैं। गुजरात से लेकर नोएडा, गाजियाबाद, मुम्बई और सूरत सभी जगह रोजगार बंद हो गए हैं। आज करोड़ों लोग बेरोजगार होकर अपने घरों में चले गए हैं। आज उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। माननीय मंत्री जी 'मनरेगा' की बात कर रहे थे, आज 'मनरेगा' का भी बुरा हाल है। आप 'मनरेगा' को फंड दे नहीं रहे हैं। आज उसमें इतनी परेशानियां हैं कि जब तक टेक्नीकल इंजीनियर उसका एस्टिमेट नहीं बनाएगा, उसकी MB नहीं करेगा और बिना पैसे के वह MB नहीं करता है, वह बिना पैसों के एस्टिमेट नहीं बनाता है, तो फिर कैसे यह सफल होगा? कैसे लेन-देन सफल होगा? उसकी पादर्शिता के लिए नियम बनाना चाहिए।

मान्यवर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसान बेहाल है, परेशान है और तमाम चीजें हैं, मैं यहां अपनी मोटी-मोटी बातें रखना चाहूंगा। हम लोग यहां उनको बार-बार उठाते हैं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कश्यप, कहार, निषाद,केवट, मल्लाह,धीमर और तिराह को परिभाषित करने के लिए कई बार भारत सरकार को संस्तुतियां दी हैं। पूरे देश में तमाम पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं। यह भारत सरकार का काम है कि वह इनकी विसंगतियां दूर करे। चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है,

चाहे महाराष्ट्र, चाहे बिहार और छत्तीसगढ़ है, सभी प्रदेशों से मांग आ रही है, प्रस्ताव आ रहे हैं, इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इन विसंगतियों को दूर करने का इंतजाम किया जाना चाहिए।

मान्यवर, आज पूरे देश में लोग परेशान और बेहाल हैं। ...(समय की घंटी)...जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है।

(LP /3p पर जारी)

LP-GSP/5.05/3p

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत) : जिस तरह से लोगों की आमदनी घटी है, उससे..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आपका टाइम समाप्त हो गया।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव ने 102 नंबर, 108 नंबर चलाने का काम किया है, जिसकी वजह से दस मिनट में, पंद्रह मिनट में प्रसव से पीड़ित महिला के पास गाड़ी पहुंच जाती है और अस्पताल पहुंचाने का काम करती है, वह सराहनीय कदम है। उन्होंने 100 नंबर चलाने का काम भी किया है, जिसके तहत पुलिस पंद्रह मिनट के अंदर अपराध को कंट्रोल करने का काम करती है।

सर, एक तरफ यह व्यवस्था है, दूसरी तरफ आप रेलगाड़ियों की हालत देखिए। आपके पास जाकर यात्री टिकट बनवाता है, लेकिन जिस तरह से ठूँस-ठूँस कर गाड़ी भरी जाती है, यात्री लैट्रिन के डिब्बे में घुस जाते हैं, ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, वह

दयनीय स्थिति होती है, इसलिए आप उतनी व्यवस्था कीजिए, आप ट्रेन्स की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि जब आदमी पैसा देता है, टिकट बनवाता है, तो उसके बैठने का भी इंतजाम होना चाहिए, लेकिन आप आखिरी के डिब्बे नहीं बढ़ा रहे हैं, पटरी में सुधार नहीं कर रहे हैं। रेल दुर्घटनाएँ हो रही हैं, अन्य तमाम चीज़ें हैं, आप उसका भी डायवर्ज़न करने का काम करते हैं कि किसकी वजह से हो गई? जाँच-पड़ताल कराने का काम करते हैं।

मान्यवर, इस तरह से..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : समाप्त कीजिए, आपका टाइम पूरा हो चुका है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, आज अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। आपने ऐसा कानून बनाया है कि सात साल से नीचे सजा वाले को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने कह दिया है। बड़ा आदमी, दबंग आदमी गरीब आदमी को पीटने का काम करता है, उसके हाथ, पैर तोड़ देता है। एफ.आई.आर. लिख दी जाती है, लेकिन पुलिस उसको जेल नहीं भेज पाती है। मान्यवर, वह उसको दुबारा से पीटने का काम करता है। जहाँ पहले उसका एक हाथ तोड़ा था, अब एक पैर भी तोड़ने का काम करता है कि और जाओ, मेरी एफ.आई.आर. कराओ। मान्यवर, केंद्र को इस तरफ पहल करके कानून बनाना चाहिए। जो पीड़ित और परेशान लोग हैं, उनको मदद मिलनी चाहिए। आज जिस तरह से पूरे देश में बेरोज़गारी, महंगाई बढ़ रही है, वह चिंताजनक है। आपने कहा था कि दाल के दाम आसमान में चले गए हैं,

आपने कहा था कि हम महंगाई को समाप्त करेंगे, बेरोजगारी समाप्त करेंगे ..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आप समाप्त कीजिए, आपका टाइम पूरा हो चुका है। ..(व्यवधान)..

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, हमारा 18 मिनट का टाइम था। मेडेन स्पीच संजय सेठ जी ने दी थी। हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि हमने जो संशोधन दिए हैं..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आपको बताया था कि आपके पाँच मिनट हैं, आपके पाँच मिनट पूरे हो चुके हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : हमारे वे सारे संशोधन मान लिए जाएं और मैं अपने संशोधनों पर बल देता हूं, धन्यवाद।

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Next speaker is Shrimati Vijila Sathyananth; not here. Next is Shri Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (ANDHRA PRADESH): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have carefully gone through the hon. President's speech but I did not find even an iota of reference to the special-category status that was promised to the State of Andhra Pradesh. Not only the special-category

status but certain other assurances also, which were given by the Government at the time of division of the State and subsequently, do not find any place in the hon. President's speech. Therefore, Sir, I would like to bring the following points to the notice of the august House. In fact, I have proposed some of the amendments and I request the august House to add the same to the Presidential Address.

In particular, Mr. Vice-Chairman, Sir, the special-category status, which has been assured to the State of Andhra Pradesh is, in fact, a sentiment of the people of Andhra Pradesh. It is a lifeline for the State of Andhra Pradesh. Sir, I would like to explain the sequence of events even at the cost of repetition. I would like to repeat some of the issues in this regard because some of the Members were not present at that time.

Sir, I would like to recall the assurance given at the time of division of the State of Andhra Pradesh by the then Prime Minister of this country in the month of February, 2014 that the divided Andhra Pradesh would be granted special-category status. This was the assurance that was given by the then Prime Minister, Manmohan Singh *ji*, on the floor of this House, and, many of the Members were present at that point of time.

(CONTD. BY 3Q/SK)

SK/3Q/5.10

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (CONTD.): And it was the UPA-II Government that was headed by Manmohan Singh*ji*. Further, Sir, on 2nd March, 2014, the Union Cabinet passed a Resolution granting the Special Category status to the State of Andhra Pradesh and the Resolution that had been passed by the respected Union Cabinet on 2nd March, 2014 was forwarded to the then Planning Commission, which was in existence at that point of time, for implementation of the Special Category status. I draw the kind attention of the hon. Vice-Chairman, Sir. Sir, please listen to me. In fact, it is very unfortunate that most of the Ministers are conspicuously absent. I thought I would present my points when all the Ministers were present. In fact, except one or two, none of the Ministers are present here even to take note of the points which I am making.

Sir, I have two legal questions, two questions of law. In fact, the author of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, my colleague, Shri Jairam Ramesh*ji*, was here sometime back. I thought at least he would be here when I raise this issue. Sir, the question of law which I am referring to is -- in fact, I am asking the Minister, he is present here -- can a decision taken

by the Union Cabinet go unimplemented? This is a question of law which I am raising in this august House. Sir, the decision that had been taken on 2nd March, 2014 and which was forwarded to the then Planning Commission for implementation, is not implemented even today. What is the sanctity of a Union Cabinet decision then? Sir, what is the legal recourse in such a scenario? The NDA Government which took over subsequently refused to implement the decision that had been taken by the then Union Cabinet on 2nd March, 2014 on the premise that the neighbouring States are opposing it. On the one hand, the hon. Minister, Venkaiah*ji* says that the Special Category status is not *sanjeevani*, on the other hand, the Andhra Pradesh Chief Minister also says that the Special Category status is not *sanjeevani*. On some pretext or the other, the NDA Government is not inclined to implement the decision that had been taken by the then Union Cabinet on 2nd March, 2014. Further, the NDA Government says that the 14th Finance Commission has not recommended, or, the 14th Finance Commission has stated that no further Special Category status should be granted to any of the States. I am asking the NDA Government: Where is it mentioned in the 14th Finance Commission Report? Is it stated anywhere in the Report that no more Special Category status would be granted further to any of the

States? To the best of my knowledge, the 14th Finance Commission has merely stated that it has not made any distinction between the Special Category States and the other States in so far as Post-Devolution Revenue Deficit Grants are concerned. This is the only reference that has been made in the 14th Finance Commission's Report. This NDA Government has not implemented it on the pretext that the 14th Finance Commission has opposed it and the neighbouring States are opposing it, and the Planning Commission which was in existence at that point of time -- in fact, the Planning Commission was still in existence for ten months or so after the NDA Government came into force -- never implemented it.

(Contd. by YSR/3R)

-SK/YSR-AKG/5.15/3R

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (CONTD.): The Planning Commission has never implemented it. Now the question is: What is the recourse left if a decision taken by the Union Government is not implemented? Is this the regard that you are showing to the decision of the Union Cabinet? That is the question of law that I am raising on the floor of the august House.

Former Prime Minister in the month of February 2014 stated that the Special Category Status would be granted to Andhra Pradesh. In fact,

Venkaiahji was in the Opposition at that point in time. He stood up and asked that the Special Category Status to Andhra Pradesh should be granted not just for five years, but it should be granted for ten years. That was his line of argument. I really do not understand why the NDA Government, after coming to power, has taken a U-turn and refused to grant the Special Category Status to the State of Andhra Pradesh. This is another question of law.

The third question of law is this. Whatever recommendations or observations the Planning Commission or the Fourteenth Finance Commission makes, they are recommendatory in nature. They are not binding on the Government. The Government can always take a decision. My colleague, Jairam Rameshji, has come. I am very happy. In fact, he should have been here. Can I repeat the question of law? Can a decision taken by the Union Cabinet on 2nd March 2014 granting the Special Category Status to the State of Andhra Pradesh go unimplemented? What is the sanctity of the decision taken by the Union Cabinet then? This is the question of law that I am raising in the august House. Since you were not present, I am repeating it again.

SHRI JAIRAM RAMESH: Former Law Minister is also here. You can ask him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please mind your time.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Okay, Sir. I will not take much time. In fact, you have given me fifteen minutes. I will conclude within fifteen minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thirteen minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, kindly give me three-four minutes more.

Now, I come to the Special Package. Who asked for the Special Package? Where has it been mentioned that it's a Special Package? Even in September 2016, when it was announced, the Central Government never said that that was a Special Package for Andhra Pradesh. Hon. Finance Minister merely said that he was giving some concession to the State of Andhra Pradesh. What is the concession that the NDA Government is giving? In fact, there is nothing in the so-called Special Package. What is going to be given for the next five years towards the State's share from the Pool of Central Taxes, by way of devolution of funds, has been mentioned as the Special Package and then they say that this is the Special Package

that is offered. Not just Andhra Pradesh, every State in India is entitled to State's share from the Pool of Central Taxes. There is nothing new or unique or extra what is being offered to the State of Andhra Pradesh. These are all the issues.

Sir, allow me to speak for five minutes more on another very important issue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Try to conclude it.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, through you, I would like to draw the attention of the former Law Minister to a very important issue. In 1985, the former Prime Minister, Late Rajiv Gandhi, who had the vision, brought 52nd amendment to the Constitution incorporating anti-defection law in the Constitution.

(Contd. by VKK/3S)

-YSR/VKK/3S/5.20

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (CONTD.): It provided that if one-third of the Members elected from a particular party go out of the party, it would be construed as a split and, therefore, it will not attract disqualification proceedings. Subsequently, in the year 2003, depending upon the situation

prevailing at that point of time, the revered leader, Shri Vajpayee, brought forward another amendment, the Constitution (Ninety-First) Amendment, providing that not one-third but two-thirds of the Members who switch over from one political party to another political party would only be construed as a split. Not even split, it would be construed as an amalgamation of the party, and therefore, disqualification proceedings would not be attracted. Sir, I need two more minutes. I will finish. This is a very important subject. When the Congress was in power, they had taken advantage of these loopholes. When NDA has come to power, they are trying to take advantage of these loopholes. So, whichever party is in power, it always takes advantage. The very foundation of democracy is at stake today. That is why, I am requesting you to give me 2-3 more minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I cannot extend time again and again. Please conclude now.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, you are affected; I am affected; everybody here is affected. I will tell you why. How is the power vested with the Speaker? Para 6 of the Tenth Schedule says that the power is vested with the Speaker. Further, Para 7 of the Tenth Schedule – and I am also referring to Article 212 of the Constitution – says that any proceedings relating to

disqualification would be construed as Parliamentary or Legislative proceedings. Therefore, the courts are barred from interfering in the proceedings. This is the status now. In the light of this scenario, the elected representatives from many political parties other than the ruling dispensation switch over freely, taking bribe or money and switching over parties and switching over loyalties. Bravely and blatantly, they switch over the party. Speakers of the respective Assemblies are not in a position to take a decision because there is no provision that has been incorporated either in 52nd Amendment or 91st Amendment. Therefore, there is a necessity as of today to introduce an amendment to plug that loophole stipulating a time limit within which the Speaker has to dispose of the disqualification petition filed before him. I request the august House to take note of it and then, implement it immediately. I also request the Government. Former Law Minister is present. In fact, he should have dealt with the situation. In fact, when they were not in power, they were also the sufferers. He should remember that. Sir, I have one more issue. It is the final issue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No more issue. You will have another occasion to speak.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I will just refer to it and then leave it. It is about women reservation. This is a very, very important issue. Women Reservation Bill which was passed by this august House and sent to Lok Sabha had lapsed on account of dissolution of Lok Sabha. For the Government of the day, the NDA Government, there is every necessity today to implement it in order to empower the women and then, bring it into force immediately. I would have spoken much more on this. Since you are not allowing me to make my submissions, I conclude my speech. Sir, I am thankful to you.

(Ends)

(Followed by BHS/3T)

-VKK/BHS-RPM/3T/5.25

SHRI JOY ABRAHAM (KERALA): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. The President's Address to the Joint Session of Parliament is a Constitutional obligation. The Governors also have this Constitutional obligation to make an Address in the Legislative Assemblies. Unfortunately, this has become a mere ritual. The President is supposed to give new policies and vision of the Government for the next financial year. Now, the Address is just a mere narration of the programmes one by one. There is no

new policy statement. Except a reference regarding simultaneous elections I did not find any other point, any new policy or vision embedded in the Address. It is unfortunate that various schemes are depicted in Hindi only. My learned friend Mr. Yechury has numbered some twelve or thirteen Prime Minister's schemes. All these schemes are known by their name in Hindi only. I come from a non-Hindi State. I am not against Hindi. I know to read and write Hindi but I am not proficient. All our national schemes, all Central schemes are named in Hindi. No English equivalent is given there. For '*Swachh Bharat'*, there is 'Clean India'. So, my humble submission is, for every scheme of the Central Government, if it is in Hindi, there should be an English equivalent to the schemes. Every scheme should be known to the masses by their literal meaning. If a person is not proficient in Hindi, he cannot understand the real, literal meaning of the words. So, I repeat my submission that all the Central schemes should be supported by an equivalent English name so that the masses can understand its full implications.

At the outset, the President says that this is a historic Session. His argument is based on the advancement of the Budget cycle and merger of the Railway Budget. That is why he said that it is a historic Session. But, I

think, it will remain as a tall claim without proof of its advantages. The former Railway Minister and the former Law Minister are here. I think, the Railway Budget is sidelined. There are just some references. It is a public utility service and needs a special consideration. I think so. Therefore, there should be a separate Railway Budget in future.

In paragraph 16, a very rosy picture of the climatic condition of the nation is depicted. The President ought to have mentioned the drought situation in South India, especially, in the Southern States of Tamil Nadu, Kerala etc. (Contd. by DC/3U)

DC-PSV/5.30/3U

SHRI JOY ABRAHAM (CONTD.): The hon. President has given a rosy picture of good crops, good monsoon and good rain. But the fact is that, Tamil Nadu, Kerala and other Southern States are reeling under drought.

Then, para 55 says about demonetization. It says that demonetization was aimed to combat the evils of black money, corruption, counterfeit currency and terror financing. Demonetization was a bold step. I will not question its *bona fides*. But one thing is clear; the rationing of currency was not anticipated. I think, even by the Government, there was not sufficient preparation. There was not sufficient foresight. So, for the common man, it

was a tragedy and the common man suffered the most. I again refer Mr. Yechury. Somebody claimed that it was a surgical strike. To compare demonetization with surgical strike is really an insult to our Armed Forces and their supreme sacrifices. Demonetization has not the essential ingredients of a surgical strike. A surgical strike has its own ingredients. One is, maximum destruction of the target with minimum casualty on the striking side. Here, unfortunately, the target may be black-money, the target may be fake currency, the target may be corruption, but, unfortunately, the target was the common man and the common man was the casualty. We saw long queues, several hardships and currency rationing. So please don't compare this move with surgical strike. That is my point. Actually the common man suffered the brunt of demonetization. I was hearing the arguments from Shri Ravi Shankar Prasad too; I am sorry to say,-- we have to support the Motion expressing thanks to the President's Address; that has also become a ritual--but I can't find any merit in Shri Ravi Shankar Prasad who moved the motion. Thank you very much.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Dr. Satyanarayan Jatiya.

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण सरकार के पिछले साल के, 2016-17 के कार्यकरण का एक तरह से लेखा-जोखा है। इसका संबंध उसके सामाजिक सरोकारों से है, उसके आर्थिक प्रबंधनों से है, विकास कार्यों से है, वैदेशिक नीतियों से है और कुल मिलाकर यह राष्ट्रहित में किए गए कार्यों का एक विवरण है। इसके साथ ही साथ अर्थ-संकल्प और बजट ऐसे निरंतर तीन महत्वपूर्ण विषय चर्चा में आए हुए हैं।

मैं जानता हूँ कि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उसका आरम्भ ही अत्यंत सुन्दर तरीके से किया गया है। "नूतन और नवजीवन की प्रतीक वसंत ऋतु" से अभिभाषण की शुरुआत हुई है। हम जानते हैं कि जब वसन्त ऋतु आती है, तो पुरानी चीज़ें जाती हैं और नयी बातें आती हैं। जो पुराना है, उसको छोड़ना और जो नया है, उसको स्वीकार करना होता है। विसंगतियाँ और चुनौतियाँ होती हैं। इन्हीं बातों को यदि हम कहें, तो निश्चित रूप से इसको ऐसा कहा जा सकता है कि जो विसंगतियाँ थीं, जो चुनौतियाँ थीं, उनमें से भी हमने कुछ अच्छा निकालने की कोशिश की है।

(3डब्ल्यू/वीएनके पर जारी)

VNK-KR/3W/5.35

डा. सत्यनारायण जटिया (क्रमागत) : यदि माननीय अटल जी के शब्दों में कहा जाए, तो हम यह कह सकते हैं :-

"टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर,
पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर,
झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात,
प्राची में, अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ,
गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।"

वैसे ही एक नव विहान के लिए, एक नई संरचना के लिए सरकार ने जो काम करना आरंभ किया, उसकी परिणति होती हम देख रहे हैं। हमारा जो लोकतंत्र है, जिसको कहा गया है कि "हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए" जो-जो चीजें आवश्यक हैं, उन-उन बातों को करते जाना है। इससे धीरे-धीरे हमारा देश आगे बढ़ता जाता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, जो सरकार ने कदम उठाए हैं, उनकी अभिव्यक्ति राष्ट्रपति के अभिभाषण में मिलती है। इसमें कहा गया है, 'सबका साथ, सबका विकास'। यह 'सबका साथ, सबका विकास' ही हमारा लोकतंत्र है। सबको साथ में लेकर, सब समाज को साथ में लेकर आगे बढ़ते जाना है। हमारा जो यह उदात्त लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए हम जो विविध उपाय करते हैं, उसमें सबका विकास अंतर्निहित होता है। हमारे यहां सूत्र में कहा गया है, "सं गच्छध्वं सं वदध्वम्",

साथ-साथ चलें, साथ-साथ चर्चा करें, **"**सं वो मनांसि जानताम्", सबकी बातों को हम समझें - यह हमारे लोकतंत्र का एक तरह से दिशासूचक है। अभिभाषण में इस विषय में बात करते हुए कहा गया, "सहनाववतु सह नौ भुनक्तु , सह वीर्यं करवावहै**",** हम साथ-साथ एक-दूसरे की रक्षा करें और हम परस्पर पोषित भी हों और पोषित करें - ऐसे पुरुषार्थ के मार्ग पर चलने का यह वक्तव्य था। विशुद्ध रूप में इसमें बहुत बड़ी बात हुई है। 80 पदों में इन सारी बातों को, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया है और अगर मैं उन सभी उपलब्धियों की यहां पर चर्चा करूं, तो मेरे लिए जितना समय है, उसमें यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें कहना संभव नहीं है। इसमें हमने गुरु गोबिन्द सिंह जी की 350वीं जयंती के अवसर पर उनको भी याद किया है और जिनका संकल्प था :-

"देहि शिवा वर मोहि इहै, शुभं करमन ते कबहूं न टरूं,

न डरूं अरि सौं जब जाइ लरूं, निसचै कर अपनी जीत करूं..."

जो सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है, उसको करना एकदम आसान काम नहीं था या एकदम निर्णय की हुई बात नहीं थी। "शठे शाठ्यम् समाचरेत", जैसे को तैसा करना चाहिए, इसलिए जो कुछ हमारे लिए अनुकूल नहीं था, यदि कुछ हो गया है, तो उसका जवाब तो देते आना चाहिए। मैं कह सकता हूँ :-

"सबसे बड़ा धर्म है नर का, सदा प्रज्ज्वलित रहना,

दाह की शक्ति समेत स्पर्श भी नहीं किसी का सहना।"

यदि हमें किसी ने चुनौती दी है, तो उस चुनौती को स्वीकार करने की सामर्थ्य हममें है, यह हमें प्रकट करते आना चाहिए और हमने प्रकट करके दिखाया है।

इन सारी बातों को याद करते हुए हमने दार्शनिक संत, रामानुजाचार्य को भी स्मरण किया है। यह हमारी परंपरा है और रामानुजाचार्य की परंपरा के बाद हम देखते हैं, तो पाते हैं कि उसके बाद गुरु रामानंद की परंपरा है, उसमें गुरु नानक देव हैं, उसमें संत कबीर हैं, उसमें संत रविदास हैं, मीराबाई हैं, सदना हैं, सेन हैं, तो ऐसी भक्ति की एक परंपरा है, उसको हमने हमारे दार्शनिक संत, रामानुजाचार्य जी को स्मरण करते हुए प्रतीकात्मक रूप से स्मरण किया है।

हमने चम्पारण सत्याग्रह का भी स्मरण किया है और जनशक्ति की बात कही है। यह जनशक्ति ऐसी है, जो एक वातावरण बनाती है, एक निर्माण करती है कि समाज और देश में जागृति लाने के लिए और मौका पड़े, तो उसको पूरा करने के लिए, सभी बातों के लिए, त्याग करने के लिए उदात्त रहने का जो एक वातावरण होता है, उसी को हम जनशक्ति कहते हैं। उसी को करने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने जब आह्वान किया, तो देश उसका पालन करने के लिए तत्पर हुआ, क्योंकि जिस व्यक्तित्व में त्याग, तपस्या होती है, उसका अनुसरण करने के लिए वह जो जनशक्ति होती है, वह ऐसे ही पैदा होती है और उसके कारण से उन बातों को पूरा करने के लिए जब कहा गया है कि आपको अपनी गैस की सब्सिडी को छोड़ना है, तो लोगों ने आगे

आकर उसको छोड़ने का काम किया है। इस तरह से 1 करोड़ 2 लाख उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी के रूप में जो केन्द्रीय सहायता मिलती थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया है।

(3एक्स/एनकेआर-केएस पर जारी)

NKR-KS/3X/5.40

डा. सत्यनारायण जटिया (क्रमागत): उसका लाभ गरीब वर्ग के व्यक्तियों को, वंचित वर्ग के व्यक्तियों को मिला। इसमें निश्चित रूप से माननीय प्रधान मंत्री जी में जो नैतिक बल था, उस बल का प्रगटीकरण हुआ है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 'स्वच्छ भारत अभियान' की, जो अब जन-आन्दोलन में बदल गया है, जब प्रतीकात्मक शुरुआत होती है, अभी हमारे लोग कह रहे थे कि प्रतीकात्मक झाड़ू लगाने से क्या हो गया? जब कोई ऐसा व्यक्ति जो देश का नेतृत्व करता है और झाड़ू लगाता है तो वह संदेश देता है कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है और यह अभियान निश्चित रूप से सारे भारत में फैल गया है। गांवों में जिस प्रकार से खुले में शौच करने को वर्जित करने के लिए उपाय किए गए हैं, लोगों ने स्वत: उसे स्वीकार किया है। किसी राष्ट्र के निर्माण में जनशक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

"हम करें राष्ट्र आराधन,
तन से, मन से, धन से,
तन-मन-धन जीवन से।"

अगर जीवन में हमें कोई शुरुआत करनी है तो अपने आपसे करनी होती है। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने एक अच्छे आन्दोलन की शुरुआत की है, जिसे अब आगे ले जाया जा रहा है।

अभिभाषण के पैरा 5 में, गरीब वर्ग के दलित, पीड़ित, शोषित और वंचित वर्ग के लोगों के बारे में कहा गया है, किसानों के बारे में कहा गया है, श्रमिकों के बारे में कहा गया है, युवाओं के बारे में कहा गया है। इसलिए इन सारे लोगों का कल्याण ही लोक-कल्याणकारी राज्य का, लोकतंत्र का हमारा लक्ष्य है। इसे पूरा करने के लिए हमने एक संकल्प लिया है -

"मानवता के लिए ऊषा की किरण जगाने वाले हम,

शोषित, पीड़ित, दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम।"

ऐसा संकल्प लेकर सरकार ने काम किया है।

"कौन बनाता हिन्दुस्तान,

भारत का मजदूर किसान।"

इसलिए भारत के मजदूर और किसानों की सुध लेने वाली बात राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कही गई है, जो निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है।

जनधन योजना के बारे में कहा गया है कि गरीब आदमियों का खाता बैंकों में कैसे खुलेगा, ऐसा कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन जन-धन योजना जब आरम्भ की गई और खाते खुलने का काम हुआ तो 26 करोड़ लोगों तक इस योजना को पहुंचाने का काम इस सरकार के समय में हुआ है। जन-धन योजना से जन-सुरक्षा की गतिविधियां

प्रारम्भ हुई हैं और 13 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लाया गया, जो निश्चित रूप से अभिनव प्रयास है। हम आलोचना करने के लिए, समालोचना करने के लिए, समीक्षा करने के लिए सभी बातों का सहारा ले सकते हैं, परन्तु जो कदम अच्छे उठाए गए हैं, उनकी सराहना करने का काम भी होना चाहिए, करना चाहिए। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी और इस सरकार की जो योजनाएं थीं, जो पिछले वर्ष साकार हुईं, उन सबका वर्णन अपने अभिभाषण में किया है।

भारतीय डाक भुगतान बैंक के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। निश्चित रूप से जहां-जहां भी पोस्ट ऑफिस हैं, वे सब अब बैंकिंग का काम भी करेंगे। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के बारे में दो लाख करोड़ रुपए के 5.6 करोड़ ऋण उपलब्ध कराए गए, जिसमें ऋण लेने के लिए किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होगी। पद 8 में इस योजना को शामिल किया गया है।

इस तरह निश्चित रूप से हर प्रोग्राम का कुछ-न-कुछ वर्णन इस अभिभाषण में हैं। दीनदयाल अन्त्योदय योजना, स्वास्थ्य समीक्षा योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें डेढ़ करोड़ परिवारों को गैस कनैक्शन देने का प्रावधान किया गया है, उसमें 37 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं।..(व्यवधान).. मेरे लिए शायद 10 मिनट हैं। आप जितना समय देना चाहें।..(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : 10 मिनट हो चुके हैं।

डा. सत्यनारायण जटिया : मुझे पता नहीं चला, कब 10 मिनट हो गए? कोई दिक्कत नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अतिरिक्त इन्द्रधनुष योजना में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा की बात कही गई है। इसी प्रकार से कृषि और किसानों को समर्पित खड़ी फसलों के लिए जो योजना शामिल की गई है, उन्हें सहायता देने का प्रावधान किया गया है, उनके लिए बीमा की व्यवस्था की गई है और मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना को हमने काफी सफल रूप से चलाने का काम किया है और उससे काफी लोगों को फायदा पहुंचा है। किसान क्रेडिट कार्ड और सिंचाई के लिए, हर फसल और देश में दालों की कमी को दूर करने का प्रयास हुआ है। इसमें सरकार की सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के उपाय किए गए हैं। नारी शक्ति के बारे में - "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:" - नारी शक्ति के सम्मान और खेलों की प्रतिभा के बारे में कहा गया है। हमारे पास जो राष्ट्रीय खेल विकास निधि है, एन.एस.डी.एफ. है, उसे विकसित करने की बात हमारी सरकार करने वाली है। बच्चों में, स्त्री-पुरुष की जो विविधता थी, असमानता थी, उसे दूर करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक बढ़ाने का काम, युवा ऊर्जा के बारे में, हर हाथ को हुनर और काम देने के लिए कौशल विकास की बात और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 951 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित करने की बात शामिल है। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय कौशल केन्द्र के रूप में, वस्त्र परिधानों में, नए रोज़गार सृजन करने के लिए

- श्रमेव जयते - क्योंकि श्रम के बिना कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए श्रम को महत्व देने का काम हुआ है। ..(व्यवधान).. मैं एक-दो मिनट और लेना चाहूंगा।

(3Y/DS पर जारी)

DS-RSS/5.45/3Y

डा. सत्यनारायण जटिया (क्रमागत) : लोग काले धन के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि भ्रष्टाचार मिटाना चाहिए, लेकिन वह हुआ क्यों नहीं? क्योंकि किसी ने किया नहीं, परन्तु प्रधान मंत्री के साहसिक निर्णय के बाद हमने देखा है कि इस ओर जिस तरह का प्रवाह हुआ है, उसे पूरा देश देख रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके परिणाम सुखद और लोगों के लिए सुरक्षात्मक होने वाले हैं, वह सारा पैसा गरीबों को कम ब्याज पर मिलने वाला है, उसके कारण काफी ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : धन्यवाद, आपका टाइम समाप्त हो चुका है।

डा. सत्यनारायण जटिया : सर, अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार की सारी योजनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ।

"सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दु:ख भाग्भवेत्।"

सभी सुखी हों, सभी निरोग, कोई न पावे दु:ख-शोक, ऐसी शुभ-भावना के साथ, राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

(समाप्त)

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र) : सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर मैं बहुत ही कम शब्दों में अपने विचार यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ, उसमें हमें यह अपेक्षा थी कि वह अभिभाषण सभी को लेकर होगा, क्योंकि वे बार-बार बोलते हैं कि "सबका साथ, सबका विकास।" अभी जटिया जी *"सर्वे भवन्तु सुखिनः"* की बात कर रहे थे, लेकिन जिस समाज में सब लोग साथ में रहते हैं, उसी समाज में सिर्फ चंद लोगों को साथ में लेकर और कुछ लोगों को बाजू में रखकर हम आगे नहीं जा सकते, यह हमें सिखाया गया है और यह कांग्रेस की राजनीति है।

सर, मैं आपके माध्यम से यहाँ से यह बोलना चाहूँगी कि काले धन का बार-बार जिक्र किया जाता है। यहाँ पर प्रधान मंत्री हों या अर्थ मंत्री हों, वे कृपा करके इस सदन में हमें आँकड़े दे दें कि उन्होंने जो नोटबंदी का निर्णय लिया, उसकी वजह से कितना काला धन वापस आ गया, टेररिज्म कितना कम हो गया? अगर उसके आँकड़े हमें मिल जाएँ, तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे।

सर, राष्ट्रपति जी ने रसोई गैस के बारे में बोला है कि "ऊर्जा स्कीम" शुरू की गई है और बहुत ही भारी पैमाने पर हमने रसोईघर में गैस पहुँचाने का काम किया है। मैं तो समझती हूँ कि इन्होंने जितना खर्चा गैस पहुँचाने के लिए किया, उससे कहीं ज्यादा खर्चा एडवर्टाइजमेंट पर किया। आप किसी भी पेट्रोल पम्प पर जाइए, वहाँ आपको प्रधान मंत्री, मोदी जी का फोटो और "गैस की सब्सिडी छोड़ो" लिखा हुआ मिल जाएगा। इस तरह से इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट करके खुद का बहुत बड़ा बोलबाला यहाँ पर कर दिया है। खुले में शौच के बारे में बहुत एडवर्टाइजमेंट होती है, लेकिन

आज भी जमीनी हक़ीकत यह है कि खुले में शौच हो रहा है, गाँव-गाँव में हो रहा है। मेरे ऐसा कहने का मतलब यह नहीं है कि यह बात अच्छी है, लेकिन खुले में शौच से निपटने का अभी तक बंदोबस्त नहीं हुआ है।

सर, सबसे ज्यादा मैं तीन मुद्दों के ऊपर बात करना चाहूँगी। मैं सबसे पहले किसान का मुद्दा यहाँ उठाना चाहती हूँ। आज देश का किसान बहुत ही बदतर हालत से जूझ रहा है। जिस समय नोटबंदी का फैसला हुआ, उस समय बहुत सालों के बाद हमारे मराठवाड़ा क्षेत्र में बारिश हुई थी और बारिश के बाद हमें लगा था कि कम से कम अब हमारे अच्छे दिन आ जाएँगे, लेकिन दुर्भाग्य से जब 8 नवम्बर को नोटबंदी का निर्णय हो गया, जब हमारी खरीफ की फसल बाजार में जानी थी, तब उसकी आधे से भी कम कीमत हमें मिली और हमारे सामने परेशानी की परिस्थिति पैदा हो गई।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

सर, तब रबी का सीज़न शुरू हो गया था और जब रबी के लिए हमें बीज बोना है, बीज लाना है और हमें खेती के कई प्रकार के काम करने हैं, उस समय रबी के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था, ऐसी हमारे किसानों की हालत हो गई थी। आज जब बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय वहाँ के किसानों के लिए ढोल बजा-बजाकर यह कह रही है कि हमें चुनकर लाइए, हम किसानों का कर्ज़ा माफ कर देंगे, तो यह सुनकर मुझे बहुत हँसी आती है। हम इतने दिनों से यह माँग कर रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र में, जहाँ किसानों की सबसे ज्यादा आत्महत्याएँ हो रही हैं, वहाँ पर आपने उनको राहत नहीं दी। ऊँट के मुँह में जीरे के समान हमारे कर्ज़े के सात दिन का ब्याज माफ करने का ऐलान

करके अर्थ मंत्री ने किसानों का मज़ाक उड़ाया है। यह बहुत बुरा लगता है। आप कहते हैं कि यूपी में सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज़ा माफ करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार आ चुकी है। वहाँ के लोगों ने तो आपको चुन लिया है, तो वहाँ के किसानों का कर्ज़ा आप क्यों नहीं माफ करते? सर, हमारी मराठी में एक बहुत ही अच्छी कहावत है। मुझे मालूम नहीं कि उसको हिन्दी में कैसे बोला जाता है। वह कहावत है- "लबाडा घरचा आवतण, जेवल्या शिवाय खरं नाही।" जब किसी के मन में खोट होती है और अगर वह खाने पर बुलाता है, तो जब तक खाना नहीं मिलता, तब तक उस खाने का मतलब नहीं है, उसके मन में खोट है, ऐसा हम समझते हैं। इसलिए ये सिर्फ बातें करते हैं।

(3जेड/एमसीएम पर जारी)

MCM-KGG/3Z/5.50

श्रीमती रजनी पाटिल (क्रमागत) : इसलिए ये सिर्फ बातें करते हैं कि यह देंगे, वह देंगे, अलग-अलग योजनाएं हैं, इस प्रकार ये बड़े-बड़े शब्द बोलते हैं। यह मानना पड़ेगा कि बी0जे0पी0 ये शब्द कहां से निकाल कर लाती है? इस तरह से लोगों को कुछ ऐसा बताते रहते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, यह मैं आपको बताना चाहूंगी।

सर, मैं दूसरी बात महिलाओं के बारे में करना चाहूंगी, जिसका जिक्र अभी अहमद पटेल जी ने भी किया था। मैं बताना चाहूंगी कि हम बहुत आशा से देख रहे थे, इस सरकार को 3 साल होने को आए, जबकि सरकार में आने से पहले इन्होंने एक

आश्वासन दिया था कि हमें चुन कर भेजिएगा, हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। हम महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण लोक सभा में देंगे, राज्य सभा में देंगे, विधान सभा में देंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। देश की सब महिलाओं को लगा था कि शायद यह बदलाव हो सकता है, शायद मोदी जी यह बदलाव कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं के लिए कोई भी राहत इस सरकार ने नहीं दी। हमारे राजीव गांधी जी ने पहली बार पहल करके 33 परसेंट आरक्षण पंचायत राज के माध्यम से हमें दिया था। आज हम यहां पर आकर बोल रहे हैं तो उसका अगर कोई कारण है तो सिर्फ राजीव गांधी जी हैं। मैं जिला परिषद से आई हूं। राजीव गांधी जी के आरक्षण के तहत मैं चुनकर आई हूं और उसके बाद में लोक सभा, फिर राज्य सभा, यहां तक आने का जो मेरा फासला है, वह राजीव गांधी नहीं आते तो हम यहां तक कभी नहीं आ सकते थे, यही मुझे मानना पड़ेगा। यह आरक्षण का जो मसला है, यहां पर इन्होंने हमें सिर्फ कागज के फूल दिखाने का काम कर दिया है।

मैं लास्ट में इंदिरा जी के लिए बोलना चाहूंगी। इन्होंने जन्म शताब्दी मनाने की बात की है। लेकिन जिस इंदिरा गांधी जी ने देश पर इतने साल राज किया, जिस इंदिरा गांधी जी को पूरे विश्व में ऑयरन लेडी के रूप में पहचाना जाता है, अमेरिका जैसे देश में कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बन सकी, लेकिन वह चमत्कार हमारे देश ने कई साल पहले किया है, लेकिन ये लोग इंदिरा गांधी जी का नाम भी लेना भूल जाते हैं, उनको भी सौ साल इसी वर्ष हो रहे हैं। उनका इस बारे में जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। पंडित जी का भी नाम भूल गए। वे अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम

भूल गए और राजीव गांधी जी का भी, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, उनका भी नाम भूल गए। उनको ऐसा लगता है कि इन लोगों का नाम लेने से लोगों को फिर वह स्मृति याद आएगी, यानी स्मृति इरानी नहीं। उनकी स्मृति से उनके जो विचार हैं, वे उनके ज़ेहन में आ जाएंगे। फिर अगर लोगों के ज़ेहन में इंदिरा जी का नाम, राजीव जी का नाम, नेहरू जी का नाम, गांधी जी का नाम आ गया तो फिर होगा कि लोगों का दिमाग कांग्रेस के प्रति कुछ विचलित हो सकता है। इस भय से ये उनका नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से इतिहास बदलने से, इस तरह से इतिहास मिटाने से उनका नाम नहीं मिट जाएगा। उनका काम इतना बड़ा है, उनकी शहादत इतनी बड़ी है कि चाहे इंदिरा जी का नाम न भी लें, तो भी हर घर में इंदिरा जी और जो भी यहां बैठे हैं, उनके भी घरों में मालूम हुआ कि अगर इंदिरा जी का नाम लिया तो हरेक के घर में इंदिरा गांधी जी के लिए क्या भावना होगी, वह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। इतना छोटा मन दिखाकर जो बड़ा होता है, जो राज करता है, जो राजकर्ता करके बोलता है, उसका हृदय भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये लोग छोटी-छोटी चीजों में अपना मन छोटा दिखाते हैं। नेहरू जी का नाम जान-बूझ कर नहीं लेंगे। हर कोई जो फ्रीडम मूवमेंट से बड़ा नेता बना है, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार वल्लभभाई पटेल, जो हमारी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हरेक को अपनी तरफ खींचने की ये लोग कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, मेरे खुद के नाना जी हुतात्मा विष्णु गणेश पिंगले, जिन्होंने गदर मूवमेंट में हिस्सा लिया था, जिनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था, उनको भी हमारे यहां के सांसद ने बोला कि ये तो आर0एस0एस0 की तरफ के हैं। तो इस तरह

से इनके यहां कोई धरोहर नहीं है, न उनके यहां कोई परम्परा है, न उनको पता है कि स्वतंत्रता सेनानी का क्या मतलब होता है। इसलिए हर कोई स्वतंत्रता सेनानी या बड़े व्यक्ति के साथ अपने को जोड़ना चाहते हैं।

इतना ही नहीं, नोटबंदी के टाइम पर जो लोग लाइन में लगे थे, उस समय कुछ लोग मर गए थे। उनके लिए हमारे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि ये लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनको इतना भी समझ में नहीं आता कि स्वतंत्रता सेनानी का क्या मतलब है? ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देने का मन भी इनके पास नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह कर अपने भाषण को समाप्त करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर इन दो-तीन चीजों का राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया होता तो अच्छा होता। खास करके महिलाओं को आरक्षण देने की आवश्यकता है। सर, आपने मुझे मौका दिया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर, मैं उनका स्वागत करते हुए अपने भाषण को समाप्त करती हूं।

(समाप्त)

(4A/KLS पर आगे)

KLS/4A-5.55

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you for adhering to the time. Mr. Dharmapuri Srinivas, when your name was called, you were not here. So, you can speak now.

SHRI DHARMAPURI SRINIVAS (TELANGANA): I thank you very much for the opportunity given to me. I also apologize that I was not present when you called me earlier. At the outset, I express my thanks to His Excellency, the President of India for his Address to the Joint Session of Parliament. But I am absolutely disappointed with the raw deal given to the State of Telangana. The Government has declared its intention to carry everyone with it, *sab ka saath, sab ka vikas* wherein the guiding principle is cooperative federalism. In the process the Union Government expects the cooperation of the various States also. In fact, though we are not a part of the NDA, yet our Chief Minister supported the Government and the Prime Minister on various occasions, more so at the time of demonetization in the larger interest of the nation though it caused setback to common man. Now, coming to Telangana, it is a fledgling State. It needs best nourishment and care. At this juncture, Telangana State is lucky in having an eminent visionary like Chandrashekar Raoji, a leader who knows the ins and outs and each nook and corner of the State as its Chief Minister, a right leader at the right time. Nevertheless the helping hand of the Union Government is very much needed at this hour to rebuild the State which has been formed after 60 long years of struggle. I am confident that the Union Government would

in its magnanimity lend its helping hand to the State of Telangana for its development. Yet despite umpteen setbacks, the down to earth Chief Minister took big strides towards the development of the State in all directions, both in development and welfare in the last two-and-a-half years. We are the top State in development. While extending top priority to irrigation and drinking water, other welfare schemes too have been accommodated in the State Budget. I am talking about the State Budgets, during the last three years, with ultimate prudence, which the entire nation is hailing. Our aim and basic idea is to complete the irrigation projects as early as possible so that the resultant bounty could be diverted to other welfare schemes. To quote a few of Telangana State Government's priorities, I may mention that being a new State, it is taking up so many schemes so fast. We are able to implement them. I only wish that the Government of India watches it and help the State Government accordingly. We have Mission Kakatiya for irrigation and Mission Bhagiratha to provide drinking water to every household. These two schemes are very popular. Chief Ministers of various States and other leaders visited our State and announced their intention to start such schemes in their States also. Then we have the schemes like Double Bedroom Houses which is very appreciable. We have

Aasara monthly pension at the rate of Rs.1000/- for about a crore of beneficiaries in the State. As far as marriages in poor families are concerned, *Shaadi Mubarak* and *Kalyana Lakshmi* schemes are there to provide assistance to poor people of all religions. We have residential schools for minorities, SCs, STs, BCs and OBCs. We are also going ahead with the infrastructure development to provide free education to the poor from KG to PG. We have many more such schemes. Within two-and-a-half years of the State formation, I am happy to say that under the dynamic stewardship of Shri KCR, our State has emerged as the most happening State.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Srinivasji, how many more minutes do you want to speak?

SHRI DHARMAPURI SRINIVAS: Maybe, two minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then …(Interruptions)…

SHRI JAIRAM RAMESH: Is he speaking on the Motion of Thanks to the Governor or the President?

(Followed by 4B/SSS)

SSS-GS/6.00/4B

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. We will extend until he finishes and then your statement will be laid. Okay, Shri Srinivas, please proceed.

SHRI DHARMAPURI SRINIVAS: Power cuts have become a thing of the past and many investors are enthusiastically coming forward to start their business in our State. Now, it is time for the Union Government to fulfill the promises made in the State Reorganisation Act. But at this crucial juncture, when a liberal allocation of funds is rightly due to the State, the Union Budget 2017-18, presented the other day, have plunged us in to utter disappointment. Our aspirations are shattered as we got a raw deal despite the fact that our Chief Minister supported the Centre in all times of need. The following issues of importance call for urgent action: The two-and-a-half years time is too long a period for bifurcation of the High Court. Andhra Pradesh Chief Minister has shifted ninety per cent of his offices to Andhra Pradesh Capital, Amaravathi. It is not at all difficult for them to identify a building for a High Court. I appeal to the Union Government to take serious steps in this direction because it is a State and High Court has to be there. I also appeal to the hon. Prime Minister to consider adoption of 'Kaleshwaram Irrigation Project' as a National Irrigation Project. I reiterate our appeal to

fulfill all commitments made in the State Re-organization Act. An increase in the number of Assembly seats would greatly help devolving powers at the grassroots. Hence, there is a need to consider our request to increase the Assembly seats. We are happy that some of the Union Ministers, other State CM's appreciated our initiatives and even they are in a mood to adopt these initiatives in their respective States also. With a heavy heart I am constrained to express our utter disappointment once again at the Union Budget regarding the raw deal extended to Telangana. We still hope that the deficiency will be compensated in a different form, in this Session itself, in the supplementary allocations by the end of the Budget Session. While I conclude, I would like to say that no mention has been made about the OBCs in the President's Address and I also request the Government of India, the Prime Minister especially, to consider forming a separate Ministry for the OBC's.

While I conclude, I reiterate my profound thanks to His Excellency, the President of India for his Address to the Joint Session and I emphasise once again that our party would extend its full support to all the people-friendly endeavours. I appeal to the Government of India to take into consideration the development of the State of Telangana. It has a very big history and a

struggle behind it because I feel they should feel responsibility to see to it that proper sanctions are made. We were all expecting that AIIMS would be announced for Telangana. So, as I said, there is a raw deal given to us. These things should be taken into consideration. Thank you, Sir.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the Statement by Minister.

* STATEMENT RE. NEGOTIATIONS IN 28TH MEETING OF PARTIES TO MONTREAL PROTOCOL HELD IN OCTOBER, 2016 IN KIGALI, RWANDA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, with your permission, on behalf of the Minister of State of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Shri Anil Madhav Dave, I rise to lay on the Table of the House a Statement in English and Hindi in today's Supplementary List of Business.

Sir, I rise to make a *suo motu* statement on the recent negotiations held under the Montreal Protocol for control of ozone depleting

……

*** Laid on the Table.**

substances that was held in Kigali, Rwanda from 6th to 14th October, 2016, and in which I participated. The 28th Meeting of Parties to the Protocol held in Kigali adopted an amendment to the Protocol which is historic and aimed at phasing down the Hydrofluorocarbons (HFCs) that contribute to global warming.

I would like to inform the august House that HFCs do not deplete the Ozone layer. However, they have high global warming potential. The amendment to Montreal Protocol agreed in Kigali has facilitated the creation of an international regime of regulatory actions and financial support for treating this set of chemicals in the same manner and with the same urgency as was accorded to other Ozone Depleting Substances in the past.

Mr. Deputy Chairman, Sir, it is significant to note that the negotiations for phasing down of HFCs under the Montreal Protocol were initiated way back in 2009, but these negotiations gathered momentum only after India submitted an amendment proposal for phase down of HFCs under the Montreal Protocol in April, 2015. The Indian Amendment proposal was crafted in a way to balance the needs of our rapidly growing economy and achieve maximum climate benefit.

Notably, India represents only around 2 per cent of the global production and consumption of HFCs but our manufacturing and consumption sector is expected to grow at a rapid pace in future. Our challenge, therefore, was to secure international agreement on a regulatory regime that served the global expectations and yet protect our national interest.

India has been a strong advocate of the principle of Common but Differentiated Responsibility in the matter of global actions to protect environment and also that national circumstances need to be factored in for arriving at any durable agreement related to climate.

At the commencement of negotiations in Kigali, the developed countries had suggested one single common baseline years for production and consumption of HFCs for developing countries i.e. 20l7-2018-20l9 and freeze year as 2021. However, various developing countries proposed as many as six different baselines range from 2017 to 2030, and freeze year-ranging from 2021 to 2031.

India piloted realistic baseline of 2024-2026 for developing countries and which protects India's interests. As per the agreement reached in Kigali, India will freeze its manufacturing and consumption of HFCs in 2028

and start reducing it from 2032 to 2047 with reference to the baseline years 2024, 2025 and 2026. The Freeze year is subject to technology review and could be further deferred to 2030. The agreement facilitates adequate carbon space for growth on domestic industry while minimizing the cost to the economy during the transition period.

India had consistently taken a position that the baseline and freeze years should be at such a future date which allows for growth of economy while minimizing cost to the economy. The Indian delegation also had steadfastly raised the issues of Intellectual Property Rights of non-HFC technologies, the high cost of these technologies and resultant cost to economy in transitioning away from HFCs.

In the Kigali Amendment, it has been agreed that the developing countries will have two set of baselines - one for the early movers in which case it will be 2020-2021-2022 and the other for those whose national circumstances were different and the manufacturing of the HFCs and consumption in whose case was still rising in the absence of clear alternative technologies. In case of such countries the agreed baseline years are 2024, 2025 and 2026.

At the same time, it has also been agreed that the developed countries will reduce their production and consumption of HFCs by 70 per cent in 2029. India will complete its phase down in four steps from 2032 onwards with cumulative reduction of 10 per cent in 2032, 20 per cent in 2037, 30 per cent in 2042 and 85 per cent in 2047.

The Montreal Protocol had no arrangement till date to incentivise improvement in energy efficiency in case of use of new refrigerant and technology. On India's initiative, it was agreed in Kigali that the Multilateral Fund under the Montreal Protocol will pay for maintaining or increasing the energy efficiency with new technology. Funding for R&D and servicing sector in developing countries has also been included in the agreed solutions on finance.

The success of negotiations at Kigali is a result of the spirit of collective action, accommodation and flexibility by all the parties to ensure the best possible outcome which addresses the needs of all countries and leads to maximum climate benefits.

I am happy to inform the House that India has been able to secure an agreement that provides adequate space for growth of our economy while providing adequate time for industry to shift to sustainable alternatives in the

interest of environment. The agreed arrangements will minimize the cost to consumers in transitioning away from HFCs and provide for domestic innovation to develop in the sector of new generation refrigerants and related technologies.

I am thankful to the hon. Prime Minister under whose constant and active guidance we approached the negotiations with a positive, flexible and constructive mindset and were able to convince the international community of the interests of India and similarly placed developing countries. The resultant agreement reflects the global ambition and at the same time allows us to take necessary steps for protection of environment and our domestic economy in a longer time frame.

I wish to thank the august House for giving me this opportunity and look forward to receiving further guidance from the hon. Members.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please circulate the copies to everybody. Only after that I will adjourn the House.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, can we seek clarifications?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not today. If you want clarifications, we can have it later. Not now because I extended the time by two minutes until the speech was over, and you agreed.

The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. tomorrow, the 7th February, 2017.

...

The House then adjourned at four minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 7th February, 2017.